LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, July 30, 2025 / Sravana 08, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, July 30, 2025 / Sravana 08, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 141 – 146)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 147 – 160)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 1611 – 1840)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, July 30, 2025 / Sravana 8, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, July 30, 2025 / Sravana 8, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 85

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 286
1st and 2nd Reports

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID 286
Shri Pralhad Joshi

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 145TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE – LAID 286
Dr. Jitendra Singh

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 2ND AND 5TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID 287
Dr. Chandra Sekhar Pemmasani

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS – LAID 287
Shri Ravneet Singh

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 253RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS – LAID 288

Shri Sukanta Majumdar

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-NINTH AMENDMENT) BILL, 2024 AND UNION TERRITOREIS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2024 288

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 289 - 326 & 339 - 85

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 327 - 38

Shri Raju Bista 327

Shri Gyaneshwar Patil 327

Shri Janardan Singh Sigriwal 328

Dr. Hemant Vishnu Savara 328

Shri Arun Govil 329

Shri Balabhadra Majhi 329

Shri Rajiv Pratap Rudy 330

Dr. Rabindra Narayan Behera 330

Shri Eatala Rajender 331

Shri Tejasvi Surya 331

Shrimati D. K. Aruna 332

Shri Charanjeet Singh Channi 332

Shri Benny Behanan 333

Shri Balwant Baswant Wankhede 333

Shri Varun Chaudhary 334

Shri Vijaykumar *Alias* Vijay Vasanth 334

Shri Ramashankar Vidharthi Rajbhar 335

Shri Malaiyarasan D. 335

Shri D. M. Kathir Anand 336

Shri G. Lakshminarayana 336

Shri Sunil Kumar 337

Dr. M. P. Abdussamad Samadani 337

Shri Umeshbhai Babubhai Patel 338

Shri Pushpendra Saroj 338

Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava 338

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF CONTINUANCE OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF MANIPUR 386 - 402

Shri Nityanand Rai 386

Shri Anto Antony 387 - 89

Shri Lalji Verma 390

@ Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 391

… 392

@@ Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 393

Dr. Angomcha Bimol Akoijam 394 - 97

Shri C. N. Annadurai 398

Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu 399

Shri Nityanand Rai 400 - 402

Statutory Resolution – Adopted 402

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in Bengali, please see the Supplement (PP 391A to 391C).

@@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in Bengali, please see the Supplement (PP 393A to 393B).

 # For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri C.N. Annadurai in Tamil, please see the Supplement (PP 398A).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, July 30, 2025 / Sravana 8, 1947 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF CONTINUANCE OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF MANIPUR 391A - 91C & 393A - 93B & 398A

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 391A - 91C & 393A - 93B

xxx xxx xxx xxx

Shri C. N. Annadurai 398A

xxx xxx xxx xxx

(1100/DPK/VR)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, क्वेश्चन नंबर 141

श्री बंटी विवेक साहू।

(प्रश्न 141)

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी विश्व के लिए बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरे हैं। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, इसलिए यह हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूर संचार संसाधनों के दुरुपयोग तथा साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे हम लोग आविष्कार और टेक्नॉलजी के आधार पर प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो कभी-कभी टेक्नॉलजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षडयंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। दूरसंचार मंत्रालय और गृह मंत्रालय साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक युद्ध है। दूर संचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मुख्य रूप से चार या पांच कदम उठाए हैं।

पहला कदम, हम लोगों ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेकहोल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर न ले आएं, तब तक हम इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। हमने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) स्थापित किया है, जिसमें हमने 620 संस्थाओं को को-ऑप्ट किया है। इसमें पूरे देश के 570 प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सभी को हमने को-ऑप्ट किया है। हमने 36 राज्यों की पुलिस संस्थाओं को को-ऑप्ट किया है। हमने सारी इंवेस्टीगेशन एजेंसीज़ और टेलिकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी को-ऑप्ट किया है। इसी के साथ हमने इस युद्ध में आम नागरिकों को भी शामिल किया है। हम लोगों ने 16 मई, 2023 को एक 'संचार साथी पोर्टल' स्थापित किया था।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि उस पोर्टल पर साढ़े पंद्रह करोड़ हिट्स आए हैं। हम लोगों ने 17 जनवरी, 2025 को उस पोर्टल की सफलता के आधार पर एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए एक मोबाइल ऐप भी स्थापित किया, जिस ऐप पर भी करीब-करीब 44 लाख हिट्स हो चुके हैं। इस ऐप और पोर्टल के आधार पर हमें इतनी सफलता मिली है कि हम लोगों ने करीब-करीब 29 लाख मोबाइल नंबर्स डिसकनेक्ट किए हैं। हम लोगों ने करीब साढ़े पांच लाख मोबाइल हेंड-सेट्स ब्लॉक किए हैं। हम लोगों ने 20 हजार बल्क एसएमएस सेंडर्स ब्लॉक किए हैं। हम लोगों ने करीब-करीब 24 लाख व्हॉट्सऐप एकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। इसी के साथ इस ऐप पर एक और सुविधा दी गई है कि आप स्वयं अपने चोरी हुए हैंड-सेट को ब्लॉक कर

सकते हैं और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसी 35 लाख रिपोर्टस फाइल की गई हैं, जिनमें से हमारे 21 लाख मोबाइल्स ट्रेस हो चुके हैं। जो 21 लाख मोबाइल्स ट्रेस हुए हैं, हमने उनमें से 5,06,000 मोबाइल्स को रिट्रीव करके उपभोक्ताओं को वापस भी पहुंचा दिए हैं।

(1105/PC/PBT)

अध्यक्ष महोदय, हमने तीसरी यह सुविधा भी दी है – 'Know the mobile connections in your name.' कई बार यह होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर, अखिलेश जी को मालूम भी नहीं होगा कि इनके नाम पर कई मोबाइल कनेक्शन्स दोबारा कई लोगों के द्वारा लिए गए। ये अपने नाम को जब पोर्टल में इनपुट करेंगे, तो सारे नंबर्स, जो इनके नाम पर लिए गए हैं, वे दर्शाए जाएंगे। अगर वे नंबर्स इनके नहीं हैं, तो ये पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 36 लाख मोबाइल कनेक्शन्स डिस्कनेक्ट किए हैं, जो उपभोक्ता ने स्वयं अपने नाम पर नहीं लिए थे।

स्पीकर सर, चौथी बात 'अस्त्र' के बारे में है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। हम लोगों ने 'अस्त्र' एप का इस्तेमाल किया है। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों ने वे मोबाइल नंबर्स अपने नाम पर न लिए हों, टैक्नोलॉजी के आधार पर ऐसे 82 लाख मोबाइल्स हम लोगों ने डिस्कनेक्ट किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और षडयंत्र रचा जाता है। कई बार हमारे मोबाइल पर दिखता था कि भारत का नंबर आ रहा है, लेकिन, एक्चुअली वह कॉल विदेश से आ रहा है। अत: उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया है - 'Centralised International Out Roaming Registry.' विदेशी कंपनियां भारत में कॉल करके अपने आप को भारत की कॉल के रूप में डिस्गाइज़ करके उपभोक्ताओं को परेशान करती थीं। इस CIOR software के आधार पर पहले दिन ही, आपको भी आश्चर्य होगा, हम लोगों ने एक ही दिन में 1 करोड़ 35 लाख कॉल्स को ब्लॉक किया। ये international spoofed calls हैं। हमने अब ऐसे इतने गेटवेज़ ब्लॉक कर दिए हैं कि उनकी संख्या 97 परसेंट ड्रॉप हो चुकी है। अब केवल ऐसी तीन लाख स्पूफ्ड कॉल्स पर-डे आती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष आखिरी बात रखना चाहता हूं। हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर भी निकाला है, जो कि 'Fraud Risk Indicator' सॉफ्टवेयर है। सारे बैंक्स के डेटा को लेकर जो लोग फ्रॉड करते हैं, उनको हम लोगों ने तीन कैटिगरीज़ में डाला है। ये तीन कैटिगरीज हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और वेरी हाई रिस्क हैं। यह सूचना हम लोग सभी बैंक्स को देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर ट्रांजेक्शन करने के लिए आ रहा है और उसका बैकग्राउंड फ्रॉड का है, तो ऑटोमैटिकली बैंक को डीओटी से मालूम हो जाता है कि यह फ्रॉड आदमी है और वह ट्रांजेक्शन रोक दिया जाता है।

इसके तहत एफआरआई के आधार पर हम लोगों ने 3,70,000 लोगों को वेरी हाई, हाई और मीडियम कैटिगरी में रेखांकित किया है। इसके आधार पर कार्ड के ऊपर डेबिट और क्रेडिट

रिस्ट्रिक्शंस से आज तक बैंक्स के द्वारा 3,04,000 ट्रांजेक्शन्स रोके गए हैं। कुल मिलाकर 1,55,000 बैंक अकाउंट्स रोके गए हैं। आज आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीओटी के फ्रॉड रिस्क इंडीकेटर सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज़ किया है और सभी बैंक्स को आदेशित किया है कि वे भी एफआरआई सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डालें, ताकि लोगों की पूंजी को हम प्रोटेक्ट कर पाएं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लिमेंट्री पूछना चाहते हैं?

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से भारत के बाहर कुछ दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों से आने वाली फर्जी कॉल्स की समस्या से निपटने के लिए दूर संचार विभाग क्या कदम उठा रहा है? इसके साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उनको इतनी बारीकी की सूचना है। एक्चुअली, साउथईस्ट एशियन देशों से बहुत सारे, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य मध्य प्रदेश के ही तो सांसद हैं।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : जी हां सर, मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा से माननीय सदस्य सांसद हैं। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत सारी स्पूफ्ड कॉल्स साउथईस्ट एशियन नेशन्स से आती हैं। इसके लिए हम लोगों ने यह निर्धारित किया है, जैसा कि मैंने आपको International Incoming Spoofed Calls Prevention System के आधार पर CIOR software के बारे में बताया, जो हम लोगों ने 1 करोड़ 35 लाख कॉल्स पहले दिन ही रोकी थीं। हमने इसकी छ: महीने पहले ही शुरूआत की थी और अब वह कॉल्स करीब 3.5 लाख तक ही सीमित हो गई हैं।

इसी के साथ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मैं सभी माननीय सांसदों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि हमारे मोबाइल्स पर जब इंटरनेशनल कॉल आ रही हो, तो नंबर के साथ यह दिखना भी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉल आ रही है।

(1110/SPS/SNT)

वह अपवर्डिंग आपके फोन पर आ रहा है कि यह इंटरनेशल कॉल है, तो हमने मेन्डेट किया है कि इंटरनेशनल कॉल की एक स्क्रिप्ट हर एक फोन पर दिखनी चाहिए। इसी के साथ हमने टीएसपीज़ को भी कहा है कि ट्रैफिक के लिए जो अनयूज्ड इंटरनेशनल कोड्स हैं, जो गलत तरीके के इंटरनेशल गेटवेज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग उसी जगह पर रोक रहे हैं। इसके अलावा 300 ऐसे कैरियर्स को हमने पूरे देश के अंदर टीएसपीज़ के द्वारा गेटवे पर ही रोक दिया है, जिसके आधार पर ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स अब घट चुके हैं। हमारे देश के कई लोग भारत के अंदर रोमिंग कार्ड्स लेते हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाकर वहां से कॉल करते हैं। ऐसे रोमिंग इंडियन नंबर्स को हम लोगों ने संचार साथी पोर्टल के द्वारा एनालाइज किया है और ऐसे 26 लाख लिंक्ड मोबाइल कनेक्शन्स को हमने डिसकनेक्ट किया है तथा करीब 1 लाख 23 हजार हैंडसैट्स को हम लोगों ने ब्लॉक किया है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is a good answer given by the hon. Minister regarding the first part of the question, but the question relates to the public sector undertakings, in particular, the BSNL and the MTNL.

It is well known that BSNL and MTNL are not available even in the metro cities. We had a parliamentary Committee visit to Mumbai for three days. Unfortunately, the mobile networks of the public sector undertakings – BSNL and MTNL – were totally blocked. There were no networks. After 32 years, with a heavy heart, a person like me had to shift to a private service provider so as to get the calls. This is the situation prevailing.

My question is regarding the fraudulent crimes. Has any assessment been done regarding the fraudulent crimes in respect of BSNL and MTNL as far as the private service providers are concerned?

Also, what is the status of BSNL and MTNL as far as 4G and 5G are concerned? As far as 4G and 5G are concerned, MTNL is not going with 4G and 5G. What is the status of MTNL and BSNL regarding improving the efficiency and preventing the fraud when compared to the private service providers?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, first of all, my senior colleague and good friend, Premachandran ji, has an innate ability of staying on the question and then going off the question and then coming back to the question. But I want to address his concern even though it is not related to the Question at all.

As far as cybercrime and cyber fraud is concerned, I have given a very detailed answer on the floor of this House. As you always have mentioned, Speaker Sir, we should not be repetitive in answers, I will not belabour the point. But Premachandran ji has taken a segue and raised the issue of BSNL and MTNL and I would like to answer that fairly and squarely. BSNL and MTNL, thanks to the vision of Prime Minister, Narendra Modi and Rs. 3.22 lakh crore packages that have been given over the last three years, are today back on the road to recovery. We have increased our number of consumers from 8.55 crore to 9.1 crore over the last fiscal. As you may have read in the newspapers Premachandran ji, for the first time in the history of the telecom industry, I, along with MoS, Pemmasani ji, have taken a full day review of all the 32 circles of BSNL. Each and every Chief General Manager was involved. We are now presenting a business plan not as BSNL in totality, but we are looking at each business circle. All three verticals are there – consumer mobility, CFA, and enterprise business. Your vertical business plan may be very different from my vertical business plan depending on our geographies. So, we are working with all CGMs. We are creating an open environment where new ideas and innovative ideas

are coming to the fore. We are creating an environment where exchange of best practices is coming to the fore.

As far as the question with regard to the network is concerned, I want to assure you that India has today posed an *atmanirbhar* solution. There are only four equipment manufacturers in the world. This will be of great concern to someone like you who is very keen and attentive towards Indian products.

(1115/RHL/SNT)

There are only four manufacturers of telecom equipment in the world. There is South Korea, there is China, there is Finland, and there is Denmark. For the first time in the history of the world – not only in the history of India – India has come up with its own 4G stack, thanks to the direction given by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Again, you will be very happy to know that our own 4G stack of Core software is made by a public sector undertaking – CDOT. It is being done for the first time in the history of the world. The Random Access Network (RAN), which are the towers that you see, are being made by Tejas, a private sector company, and CDOT. We have TCS as a System Integrator (SI). About 95,000 towers have been mandated and Rs. 20,000 crore of CAPEX has been done. Out of the 95,000 towers, today 75,000 towers are up and radiating. We are making sure that that integrates with the Core software and I commit to you that BSNL will come out with its own 4G. It is already out. We will perfect its 4G network in the coming months and as soon as that 4G network is perfected, we will also move towards 5G. MTNL's area of operations – Bombay and Delhi – have been transferred to BSNL as of 1st January of this year and we are rolling out 4G in those areas as well.

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर एक प्रश्न में 15 मिनट का समय लग जायेगा, तो दिक्कत आएगी। माननीय सदस्य संक्षेप में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री जी संक्षेप में उसका उत्तर दें।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर जी, आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सिम स्वैपिंग/धोखाधड़ी के जो नए मामले सामने आ रहे हैं। जालसाज किसी व्यक्ति की सिम खो जाने की बात कहकर उसी नंबर की दूसरी सिम जारी करवा लेते हैं। इस गंभीर चुनौती से निपटने और आम नागरिकों को बचाने के लिए सरकार कौनसे ठोस कदम उठा रही है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दे दिया था। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने करीब-करीब 28 लाख मोबाइल फोन्स डिस्कनेक्ट किए हैं, साढ़े पांच लाख मोबाइल हैंडसेट्स और करीब-करीब 1 करोड़ 36 लाख मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए हैं। अभी हमारी यह प्रक्रिया जारी है।

(इति)

(प्रश्न 142)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-142, श्री प्रद्युत बोरदोलोई जी - उपस्थित नहीं।
माननीय मंत्री जी।

श्री सतीश चंद्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह प्रश्न कोयले से संबंधित है। तिनसुकिया में जो कोयला वेस्ट होता है, तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि दिनांक-25 अप्रैल, 2025 को ईडी डायरेक्टरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि असम और मेघालय में उन्होंने 15 जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद यह पता चला कि एक अवैध कोयला सिंडिकेट असम और मेघालय में चल रहा है। ईडी की प्रेस रिलीज में जो लिखा है वह मैं पढ़ भी देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये प्रेस रिलीज पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, "ED investigation further revealed that a syndicate having persons…".

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल तो पूछ लूं, ताकि लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रेस रिलीज से डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि ईडी की प्रेस रिलीज हैं, जिसमें उन्होंने खुद ही बोला है कि एक कोयला सिंडिकेट असम-मेघालय में चल रहा है। वैध कोयला माइनिंग से अवैध बिल्स निकालकर ये मुनाफा दे रहे हैं, इसको लेकर मंत्रालय क्या कर रहा है? इसमें अभी तक कोई भी इनवेस्टिगेशन केन्द्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं हुई? कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ पैसा जमा कर लिया, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सतीश चंद्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया था, यह प्रश्न उससे अलग है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री सतीश चंद्र दुबे : सर, हमने बताया कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से अलग है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी तरफ से बोलिए।

श्री सतीश चंद्र दुबे : सर, जो जवाब दिया गया है, यह उससे अलग है।…(व्यवधान)

(1120/VPN/KN)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मन्ना लाल रावत जी।

… (व्यवधान)

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एनसीएसटी द्वारा 28.01.2025 को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया था कि जो ओवर बर्डन है, उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो पत्र है, उसके संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है? क्या उसमें सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हो गई? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सतीश चंद्र दुबे : महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या असम मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जो पत्र मिला है, उन्होंने कागज की डिमांड की थी। हमारे विभाग ने कागज भेज दिया है और उसका जवाब दे दिया गया है। अभी उधर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है।

DR. RICKY A. J. SYNGKON (SHILLONG): Hon. Speaker, I would like to draw the attention of this august House, and the concerned Minister also, through you, to a case of about 4,000 metric tonnes of coal which went missing from two depots that fall under my constituency. I want to know if the Minister is aware of this particular incident where 4,000 metric tonnes of coal went missing. Sadly, one of the Ministers from the State Government says that the rain is the reason for this missing coal. This is a very serious issue. I request the Minister to look into this matter. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन यह प्रश्न नॉर्थ ईस्ट का है। आदरणीय सांसद ने आज इस इश्यु को उठाया है। इस इश्यु को मैंने आज सुबह सोशल मीडिया पर देखा है। इल्लीगल कोल का जो विषय है, पानी के कारण जो कोल मिसिंग है, उसका कोल इंडिया और गवनर्वमेंट ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। हम स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर क्लेरिफिकेशन लेंगे। आने वाले दिनों में क्लेरिफिकेशन आने के बाद आदरणीय सांसद को इसके बारे में जानकारी देंगे।

(इति)

(Q. 143)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, hon. Minister has said in a statement on 21 May, 2025 that two coaches were added and with regard to augmentation, he said that it is strictly in accordance with and subject to traffic justification, operational feasibility and viability of resources etc. It is understandable but what I am saying is that a Minister like him, who is having a vision, must have a social viability also in consideration. This railway line from Nilambur to Trivandrum is an age old railway line. A lot of potential is there. We have to give a special consideration to it. My question which I wish to ask is this. Sir, there is an important train called Rajya Rani that is from Nilambur to Trivandrum**.** This train is coming from Nilambur and stopping at Kochuveli which is not in Trivandrum. It is 10 kilometres away. That train carries a lot of patients. There are two medical institutions that are of national status. One is Regional Cancer Centre and the other is Sree Chitra Tirunal, that also is a national-level institution. Sir, these patients have to go to Kochuveli and then catch the other train. Patients, ladies, kids and other passengers are suffering like anything. Hon. Minister may be knowing that. He is also a kind man. What I am asking is this. Why can he not solve that problem?

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Please extend that train. That is my first question. I would like to add one more thing … (*Interruptions*)

… (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, hon. Member has asked a question about Nilambur-Kottayam Express and about augmentation of general-class coaches in this train. I have already given reply to this. I would also like to point out hon. Speaker, Sir, that Government of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi is committed to the welfare of middle classes and low-income families.

(1125/AK/ANK)

Over the last few years so many steps have been taken, which are basically for the welfare of the low-income families. I will give some examples here. The number of general class coaches, which are basically availed by the low-income families, has substantially increased in the last few years. Today, out of the total 82,000 coaches, about 70 per cent coaches are general class and non-AC coaches. Out of the 69 lakh seats, almost 78 per cent seats are basically non-AC and general class seats.

We have taken up a programme of manufacturing 17,000 general and non-AC coaches. We have also started Amrit Bharat Express.

मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं सभी मान्यवर सांसदों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लो इनकम फैमिलीज़ के लिए प्रधान मंत्री जी का जो विज़न है, उसमें 'अमृत भारत एक्सप्रेस' एक ऐसी ट्रेन है, जो एकदम लो कोस्ट पर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोचेज और 8 स्लीपर क्लास कोचेस हैं। प्रैक्टिकली, जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती हैं, इस ट्रेन में उनके फीचर्स हैं। इसमें जर्क-फ्री सेमी ऑटोमेटिक कप्लर्स लगे हैं, जिसमें चलने के दौरान बिल्कुल भी जर्क्स नहीं आए। क्रैशवर्दी फीचर्स बैटर, ईपी असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, एकदम मॉडर्न फायर सप्रेशन, नए डिजाइन के टॉयलेट्स, कोचेज़ और लगेज रूम में सीसीटीवी कैमराज़, एक एर्गोनोमिकली डिजाइन्ड लैडर, जिससे चढ़ना आसान हो, ए और सी टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, एलईडी फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पेंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज, ये मिडिल क्लासेज के लिए, लो इनकम के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है।

मान्यवर सांसद महोदय ने जो राज्यरानी एक्सप्रेस की, कोच्चुवेली की बात कही है, मैंने इसको संज्ञान में लिया है और जो इन्होंने कहा कि क्या उसका एक्सटेंशन त्रिवेंद्रम हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी लेकर मैं वापस आपसे चर्चा करूंगा।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you very much. Kindly examine about the Trivandrum-Kochuveli issue so that it will be of help for the people.

The other thing is with regard to MEMU service. A lot of work was done in it. The electrification is now over and everything is ready. I do not know the reason for the delay. Kindly examine the issue and take a final decision on the MEMU service that we have requested for.

Another thing is with regard to the Nilambur-Shoranur route, which is a historical route, which is also a tourist destination, and its scenic beauty is unexplainable. So, there is a lot of scope for tourist-related activities, and for that also, some sort of scheme or providing some coaches, etc. can be considered by the Ministry. I would humbly request the hon. Minister to examine whether these few suggestions of mine can also be considered.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the hon. Member has raised a very important point. I would like to say how our Government is basically trying to increase the capacity of railway network in Kerala.

What was the work that was done in Kerala by the Congress, which ruled this country for 60 years? … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, what was the question and what is being replied here? … (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, introduction of new trains basically requires increased capacity of railway tracks. … (*Interruptions*) Today, for the entire railway network in Kerala, our Government under Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's leadership has taken up DPR preparation- Shoranur to Mangalore third and fourth

line DPR is going on; Shoranur to Ernakulam third line DPR is going on; Shoranur to Coimbatore 99 kms. third and fourth line DPR is being prepared; Ernakulam to Kayankulam 115 kms. third line DPR is being prepared; Kayankulam to Trivandrum 105 kms. third line DPR is being prepared; and Trivandrum to Nagercoil 71 kms. third line DPR is being prepared. This is the commitment of Prime Minister, Shri Narendra Modi ji to the railway network of Kerala.

If we compare the work which was done in Kerala, today, under the NDA Government, it is more than the work which was done in the last 60 years. Once we have this capacity, we can introduce more trains. This is the fundamental point, which has to be understood by all the hon. Members.

(1130/RAJ/SRG)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, इसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन उस समय से हमारी कई ट्रेन्स, शटल ट्रेन्स और भुसावल-नागपुर जैसी पैसेंजर्स गाड़ियां बंद हो गई हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेनों को शुरू करते हुए जो नई मेमू ट्रेन्स चलाने की योजना है उसको हमारे नर्मदापुरम लोक सभा क्षेत्र में जल्द से जल्द शुरू करें जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का कल्याण हो सके एवं छोटे स्टेशंस सिहोरा सहित अन्य सभी स्टेशनों का कल्याण हो सके।

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मध्य प्रदेश से चुन कर यहां आए हैं। यह प्रश्न केरल से संबंधित था, फिर भी हमने इनके सुझावों को संज्ञान में लिया है। मैं इस पर जानकारी देकर इनसे बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री वामसि कृष्णा गद्दाम जी। यह पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं।

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): I would like to bring the hon. Minister's attention to Mancherial district. We had asked for a Vande Bharat Express for Mancherial area.

As you know we come from Singareni Colony of that side. We have a huge contribution to the Railway revenue. Revenue to the tune of Rs. 10,000 crore to Rs. 15,000 crore comes from Singareni. We have been requesting for a Vande Bharat and a Kerala Express for a very long time. I request you kindly to look into this matter. A lot of commuters are suffering in Mancherial due to non-availability of connection there.

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद तेलंगाना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जब शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हुई थीं, जितने समय में सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कम्पेयर करें, तो करीब दो दशक से अधिक समय लगा था। जब प्रधान मंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस की, तो तीन सालों के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया। आज वंदे भारत ट्रेन की 144 सर्विसेज चल रही हैं और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। जैसा कि अभी मान्यवर सांसद जी ने एक और वंदे भारत ट्रेन की डिमांड की है। देश भर से इसकी डिमांड आती है। मैंने आपकी डिमांड नोट की है। हम मंचेरियल से संबंधित फिजिबिलिटी जांच करेंगे।

(इति)

(Q. 144)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, the Department of Space headed by our hon. Prime Minister has only provided a sketchy statement about various schemes which are implemented through space technology across the country. I would like to know from the hon. Minister what are the key milestones achieved under Ganganyaan Mission and how the Government is ensuring technological self-reliance and astronaut safety.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker Sir, I am thankful to the hon. Member. She has asked a question which gives me an opportunity to share with this august House that over the last 11 years or so, India has put before the world a unique model of space technology application, which is no longer confined only to the launching of rockets. Today, space technology is extensively being used in infrastructure projects, development works and most of all, as the hon. Member rightly mentioned, to bring ease of living in the life of a common citizen.

Today, space technology has entered every Indian household and that was precisely the commitment and vision envisaged by our founding father Vikram Sarabhai, which is for the first time finding its vindication under Prime Minister Narendra Modi.

Today, we have in the process given the world some of the global success models. For example, Gati Shakti portal is there, which is a portal based on about 200 layers trying to integrate planning with infrastructure projects. It helps in planning, it helps in monitoring, it saves time, it saves money.

(1135/SM/NK)

This has now been acknowledged worldwide as well. Likewise, space technology is being extensively utilised, as we all know, in communication, healthcare, telemedicine, flood and disaster management forecasting, GeoMGNREGA, railways and housing, and in many of the Modi Government's flagship initiatives, such as AMRUT and Smart Cities etc. This technology is also being used extensively in defence and warfare.

This also gives me an opportunity to share with this House one very heartening news that today, precisely at 1740 hours of Indian Standard Time, we will be launching the first-ever ISRO-NASA collaboration satellite, named NISAR. This is going to be a game changer for our disaster response and monitoring capabilities, significantly enhancing our ability to predict and manage

landslides, volcanoes, cyclones, and more. This will be the first technological venture of its kind.

Furthermore, it will have the ability to penetrate fog, dense clouds, and thick ice layers, providing much greater ease not just in disaster management but across a range of other sectors such as aviation, shipping, transport, and more.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to ask the hon. Prime Minister if he could please elaborate the steps being taken to promote the development of small and medium-scale space startups, including funding support, technology sharing, and incubation infrastructure?

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I am pleased that the hon. Member raised this question, as it allows me to share with this august House that for the first time since Independence, a very out of the box decision was made by the Prime Minister which only he could make, given his ability to break past taboos. Space technology was unleashed and media widely reported that India's space sector had been unlocked. For the first time, the private sector was permitted entry into our space ventures and projects.

As the hon. Member rightly pointed out, we initiated this process in 2019, with new space reforms in 2020 and a formal space policy in 2023. The hon. Member will be pleased to learn that just in a short span of three or four years, there has been a quantum jump not only in the number of space startups but also in the overall space economy. For instance, just three or four years ago, we had only a handful of space startups. Today, that number exceeds 300. Many of these startups possess global potential, with some evolving into highly successful entrepreneurial ventures.

Our space economy has seen remarkable growth. We had just a dismal quarter of space economy about half a decade back. We have now reached an eight billon US dollar space economy. Projections for the next ten years indicate that this figure could multiply three to four times, possibly reaching 40 or 45 billon US dollars. In other words, it means that India will move from 10th rank to 4th rank in the global space economy rankings and will aim for 1st rank for Viksit Bharat. Space economy will play a crucial and pivotal role in that success story.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। पिछले दिनों साइंस और टेक्नोलॉजी की कमेटी इसरो गई

थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम चन्द्रयान तीन पर आए हैं, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसे अनलॉक किया है, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है। स्पेस सेक्टर में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी काम कर रही है, चाहे मनरेगा हो या एग्रीकल्चर हो। माननीय मंत्री जी के बताया कि फसल कार्यक्रम के तहत ग्यारह फसलों के लिए एकड़ वार और फसल की पैदावार का पूर्वानुमान लगाने के लिए कार्य करेगा।

जिस तरीके से चमन के अंतर्गत बागवानी में किया है। इन सारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके कहा था कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा किसानों को मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में राज्यवार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप होगा?

(1140/IND/GM)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन में देख रहा हूं कि कई वरिष्ठ माननीय सदस्य सीट्स पर बैठे-बैठे टिप्पणी करते हैं। मैं फिर सभी से आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा को बनाकर रखिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठे-बैठे टिप्पणी न करें।

माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. जितेंद्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मुख्य तौर पर कृषि केंद्रित प्रश्न पूछा है। अत: जैसा कि मैंने कहा, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न सेक्टर्स में स्पेस टैक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है। यदि आप एक्सक्लूसिवली कृषि क्षेत्र की बात करें, तो जैसा कि उन्होंने स्वयं व्याख्या की, हमारा एक बड़ा ही सफल प्रयोग रहा है, जिसका नाम 'चमन' है। चमन का अर्थ - Coordinated Horticulture Assessment and Management Using Geoinformatics है। अर्थात, इस स्पेस टैक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात का अध्ययन करना कि वह जमीन किस प्रकार की कृषि के लिए अनुकूल है और किस प्रकार उसमें बेहतरी लाई जा सकती है।

This successful experiment has been conducted on seven different crops. इसी तरह डेडिकेटिड स्पेस टैक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमारा जो सफल प्रयोग रहा है उसका नाम 'फसल' है। 'फसल' का अर्थ - remote sensing data for generating crop areas and forecasting crop products है। पहले से ही ईको सिस्टम का निर्माण करके, जिसमें मौसम विभाग का भी योगदान है और ये जो स्पेस टैक्नोलॉजी के कृषि केंद्रित प्रयोग हैं, चाहे वह 'चमन' का प्रयोग है या 'फसल' का प्रयोग है, ये मिलकर ऐसे ईको सिस्टम की रचना करते हैं, जिसके अंतर्गत कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने 'डब्लिंग ऑफ फार्मर्स इनकम' का लक्ष्य रखा है, हम 'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल ऑफ साइंस' के कॉन्सेप्ट से उसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon. Speaker Sir, my question is on the human capital front. Could the Government share specific data on the number of students and professionals trained under ISRO's Unnati and IIRS outreach programmes over the last five years and how many of these are from tier-2 or tier-3 cities or aspirational districts?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker Sir, as the hon. Member has placed, the question is prompted by the very fact that there has been a visible game change over the last four or five years, which was not so earlier. For example, our most notable teaching institute in space technology which happens to be in Thiruvananthapuram was one of the premier institutes, one of the world-class institutes. It had registered 100 per cent placement but most of our students had to go abroad for jobs or employment. It is no longer so, partly because of what I said in the earlier question on startups and partly also because the expansion of the space programme in India has generated a lot of job opportunities domestically.

We are also trying to expand our teaching facilities to other parts of the country which were earlier confined mostly to South India. For example, one such teaching centre on the same lines as Thiruvananthapuram has been started in the North-East region at Agartala, in the campus of the NIIT in Tripura. Similarly, in North India, we have started a centre for the Central University of Jammu where we have set up a similar institute which has been named Satish Dhawan Institute because Shri Satish Dhawan happened to belong to the erstwhile State of Jammu and Kashmir which is a lesser-known fact. So, I think with the availability of opportunities, the fellowship is also on the increase; the startup link-up is also on the increase; and we are also in the process of opening up not only new schemes as mentioned by the hon. Member but also opening up new teaching centres.

At the same time, we are also collaborating with the Ministry of Education and several of the universities across India are coming forward. I think one very important feature which I noticed in the last two-three years is that in aerospace engineering, they have a provision of summer training in the third year of engineering. Earlier, we had a few students coming and asking for internship in ISRO. Now we are flooded with thousands and thousands of applications which means suddenly even in the engineering stream, the priority of aerospace in IIT-JEE counselling has gone up tremendously. All this has happened in the last three-four years because of all those factors which have been introduced as I mentioned earlier.

(ends)

(1145/KDS/GTJ)

माननीय अध्यक्ष : अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धि पर जब चर्चा होगी, तो माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का अवसर दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 145, श्री गणेश सिंह जी।

(प्रश्न 145)

श्री गणेश सिंह (सतना) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश में उन्होंने नवीरकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। वर्ष 2025 में आज तक अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 226.9 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मध्य प्रदेश में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से कुल 11,27,915 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयंत्र स्थापित किए जाने की जानकारी दी है।

सर, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तथा नर्मदापुरम में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण जोन की स्थापना भी की जा रही है। उसका विस्तृत विवरण क्या है? मध्य प्रदेश में 4 हजार 248 मेगावाट क्षमता के 8 सौर पार्क्स स्थापित हैं। इनमें 2608 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में सौर ऊर्जा पार्क के लिए कई ऐसे स्थान रिक्त हैं, जहां पेड़ नहीं है। हमारे यहां पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के अलावा पावर ग्रिड भी मौजूद है। क्या माननीय मंत्री जी वहां सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने पर विचार करेंगे?

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष महोदय, श्री गणेश सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपकी अनुमति से मैं उत्तर देने से पहले यह बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कॉप 26 में अनाउंस किया था और दुनिया से कमिटमेंट किया था, जिसमें जी 20 के देश भी शामिल थे। उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कमिटमेंट किया था कि by 2030, India's total installed power capacity out of, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें 50 परसेंट नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। This was a commitment to be fulfilled by 2030. प्रधान मंत्री जी के कमिटमेंट की पूरी दुनिया सराहना कर रही है। Five years ahead of the time हम रिन्यूएबल एनर्जी से इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50 परसेंट उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से कर रहे हैं। आज के दिन नॉन फॉसिल फ्यूल से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 243 गीगावाट हो गई है। देश में कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 485 गीगावाट है। उनमें से 243 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। According to the report by the International Finance Corporation, India is the only G20 country whose climate actions are aligned with the goal of limiting global warming to two per cent. This is the only country in G20 which has achieved this great thing. So, I congratulate hon. Prime Minister. This has happened well in advance five years. सारी दुनिया चकित होकर यह देख रही है, क्योंकि वर्ष 2014 में हमारी सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 2.42 गीगावाट थी, जबकि आज के दिन यह लगभग 130 गीगावाट है। इसे हमें एप्रिशिएट करना चाहिए।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है। आज के दिन मध्य प्रदेश में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी ने कहा था कि यह 11 गीगावाट से ज्यादा हो गया है। हमने एक सोलर पार्क अवार्ड किया है। हम सोलर पार्क का प्रपोजल राज्य सरकार

को देते हैं। राज्य सरकार उस सोलर पार्क के लिए जहां लैंड देती है, वहां हम इंस्टॉल करते हैं। The Omkareshwar Floating Solar Project in Khandwa district is of 518 megawatts and it is one of the largest power projects in the country. यह देखने लायक है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इसे एक बार देखकर आएं। यह बहुत अच्छी तरह से इंस्टॉल हुआ है। The water body acquired on the right to use basis, park construction and the projects have been completed. The tender and e-reverse auction for 240 megawatts is completed. But the DISCOM has denied the purchase of the power at the discovered price. निगोशिएशन चल रहा है। But the overall performance of the Omkareshwar Floating Solar Project is unique in India. यह माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है, जो देखने लायक है। The overall performance of Madhya Pradesh, as far as renewable energy is concerned, is very good.

(1150/CS/RCP)

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी, क्या आप सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री गणेश सिंह (सतना) : जी महोदय।

जिस तरह से ओंकारेश्वर में बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, उसी तरह से हमारे लोक सभा क्षेत्र में बाणसागर परियोजना की बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। उस पर भी यह प्रयोग किया जा सकता है। वैसे सरकार ने एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है। हमारे लोक सभा क्षेत्र से भी कई आवेदन पत्र आए हैं, जिसमें अभी तक 648 घरों में ही रूफटॉप हो पाया है और शेष बचे हुए हैं।

मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि इसके अलावा भी हमारे लोक सभा क्षेत्र में 1,784 गाँव हैं और सभी जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। अधिकांश गाँव ऐसे हैं, जो अंधेरे में रहते हैं। घरों में तो बिजली है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर सौर ऊर्जा की लाइट्स स्थापित की जा सकती हैं? धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी : हम सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अपने किसान भाईयों के लिए पीएम-कुसुम आदि योजनाएँ देते हैं। वैसे तो हमारी जो भी स्कीम्स हैं, वे राज्य सरकारों के द्वारा इम्पलीमेंट होती हैं। पीएम सूर्य घर इम्पलीमेंटेशन भी ऐसे ही होता है। There, 89,000 families have applied for the rooftop solar system. More than 54,000 households have already benefited. इससे उनको फायदा मिला है। इसके लिए हमने 350 करोड़ रुपये रिलीज भी किए हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट्स आदि का सोलराइजेशन करना लोकल बॉडीज का काम है। आज के दिन में भारत सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है। धन्यवाद।

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में व्यापक काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने हेतु किसानों को अपेक्षाकृत अधिक अग्रिम लागत वहन करनी पड़ती है और योजना की प्रक्रिया तकनीकी दृष्टि से किसानों के लिए जटिल है। प्रौद्योगिकी और वित्तीय

पहलुओं को समझना ग्रामीण किसानों के लिए मुश्किल होता है, जिससे योजना में किसानों की भागीदारी कम संभावित होती है। सरकार योजना और सब्सिडी वितरण प्रणाली के सरलीकरण हेतु मध्य प्रदेश, विशेष तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों के किसानों के बीच योजना संबंधी जानकारी की जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, पीएम-कुसुम में तीन कंपोनेन्ट हैं। उसमें कंपोनेन्ट ए है, कंपोनेन्ट बी है और कंपोनेन्ट सी है। हमारा ओवरऑल परफॉरमेंस भी अलॉटमेंट के आधार पर ठीक है, लेकिन पूरे देश से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। शुरुआत में इसके महत्व को कई राज्य सरकारें, वैसे तो किसान भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज के दिन में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई है। मध्य प्रदेश से भी हमारे पास डिमांड आयी है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम जागृति करने के लिए, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने तथा और जो भी काम करना है, माननीय सदस्य का यह सुझाव है तो हम जरूर उस सुझाव पर एक्ट करने के लिए तैयार हैं। आज के दिन में ओवरऑल इसकी परफॉरमेंस और डिमांड बहुत अच्छी है। यह डिमांड रिबन है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आकर इसका ज्यादा अलॉटमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसानों की डिमांड है, इसीलिए वे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मुझे पूरा विश्वास है, 26 मार्च को पीएम-कुसुम, इस प्रजेंट स्कीम का अंत भी हो रहा है, इसलिए जो राज्य इसको फास्ट ट्रैक में करेगा, उसको फायदा होगा। धन्यवाद।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Mr. Speaker, Sir, no doubt this is a beautiful programme. As the Meghalaya State has been indebted with the burden of electricity bills, with this particular scheme, the public, which is slapped by indirect burden, would have been eased. The Government of Meghalaya is indebted with thousands of crores of rupees right now to the private sector. So, this particular renewable energy would have really helped. So, I would like to know whether there is any programme concerning the Government of Meghalaya so that the public of Meghalaya State would be eased from the burden of electricity bills.

(1155/MNS/HDK)

श्री प्रहलाद जोशी : इसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। जहां तक पीएम कुसुम योजना का सवाल है, इसमें पीएम कुसुम ए, पीएम कुसुम बी और पीएम कुसुम सी है। अगर कोई पीएम कुसुम बी में इंडिपेंडेंट सोलर प्लांट लगाता है, तो बिल का कोई सवाल ही नहीं है। यह अलग-अलग स्कीम है। अगर माननीय सदस्य मुझे लिखकर देते हैं कि किस स्कीम में कंपोनेंट ए है, किस में कंपोनेंट बी है, किस में कंपोनेंट सी है, तो हम इसके बारे में जानकारी लेकर उनको जानकारी दे देंगे। इसमें उनको प्रॉब्लम कहां आ रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है?

(इति)

(pp. 19-30)

(प्रश्न 146)

*SHRI SANDIPANRAO ASARAM BHUMARE (AURANGABAD): Hon'ble Speaker Sir, through you, I would like to ask Hon'ble Railway Minister that whether there is any special system in place to evacuate the railway passengers safely and rapidly in case of any big accident or in emergency situation at the railway stations in my district Chhatrapati Sambhajinagar.

Whether the special women RPF constables are deployed at the important railway stations in my district and the women helpline is in place to ensure the safety and security of women passengers. Whether Primary Health Centre or trained medical staff is available on running trains or at railway stations to provide emergency medical treatment to passengers. Whether there is any system in place to co-ordinate with the nearby hospitals. The details of the special and effective steps taken by the Government to ensure these safety measures.

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने कवच के बारे में प्रश्न रखा था, लेकिन इनके सप्लीमेंट्री में कोई और विषय है। मैं फिर भी यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रेलवे में सेफ्टी पर फुल फोकस देकर, नंबर वन प्रायोरिटी देकर काम कर रही है। इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जहां वर्ष 2014-15 में 135 एक्सीडेंट्स थे, वहीं वर्ष 2024-25 में कम होकर 31 रह गए हैं। यानी कि 77 प्रतिशत रिडक्शन हुआ है और इसके बावजूद भी लगातार फोकस है कि रेलवे में कैसे सेफ्टी बढ़ायी जाए, किस तरह से नई-नई टेक्नोलॉजी लाएं, किस तरह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेज को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों की भागीदारी बढ़े, प्रैक्टिसेज बढ़े, इम्प्रूवमेंट आए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कवच के बारे में बताना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जहां विश्व में कई समृद्ध देशों ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम करीब 20 से 30 वर्षों में लगाया और हमारी तुलना में उनके पास आधे रेलवे नेटवर्क्स थे वहां भारत ने प्रधान मंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिजाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वह प्रणाली आरंभ की और पिछले साल जुलाई, 2024 में कवच का वर्जन 4.0 आरडीएसओ से अप्रूव हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोटा से मथुरा के बीच में आपके निर्वाचन क्षेत्र में कवच 4.0 की आज या कल फुल कमर्शियल कमीशनिंग होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि इतनी जटिल टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में लागू करना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि कवच एक तरह से एयरटेल और बीएसएनएल जैसी एक पूरी टेलीकॉम कंपनी स्थापित करने जैसा काम है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है। अब तक 5,856 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का केबल लग चुका है। इसमें टेलीकॉम टावर्स लगते हैं। अब तक 619 टेलीकॉम टावर्स लग चुके हैं। इसमें स्टेशन पर डेटा सेंटर लगता है। अब तक 708 स्टेशनों पर डेटा सेंटर लग चुका है। लोकोमोटिव में एक पूरा सिस्टम लगता है। यह 1107 लोकोमोटिव में लग चुका है। यह ट्रैक्स पर लगता है। 4000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पर कवच लग चुका है। (इति)

प्रश्न काल समाप्त

* Original in Marathi

(1200/RV/PS)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री गुरजीत सिंह औजला, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्री राजेश रंजन, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री एम. के. राघवन, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री शफी परम्बिल, एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्री एंटो एन्टोनी, श्री बैन्नी बेहनन, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्री धर्मेन्द्र यादव, डॉ. मोहम्मद जावेद, मोहम्मद रकीबुल हुसैन, और श्री कोडिकुन्नील सुरेश के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पप्पू जी, अगर आप अपनी सीट पर नहीं जाएंगे तो आपको कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इस संसद के अन्दर जो 'वेल' में आएंगे या 'वेल' के बाहर रहकर बोलेंगे, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है।

आज शून्य काल चलेगा। मैंने आपको विषय बता दिया। आपको शून्य काल में बोलने का अवसर देंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1202 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Lok Sabha:-

SIXTEENTH LOK SABHA

1.	Statement No. 28	Sixth Session, 2015
2.	Statement No. 28	Eighth Session, 2016
3.	Statement No. 26	Tenth Session, 2016
4.	Statement No. 27	Eleventh Session, 2017
5.	Statement No. 21	Thirteenth Session, 2017-18
6.	Statement No. 20	Sixteenth Session, 2018-19

SEVENTEENTH LOK SABHA

7.	Statement No. 26	First Session, 2019
8.	Statement No. 20	Second Session, 2019
9.	Statement No. 20	Third Session, 2020
10.	Statement No. 21	Fifth Session, 2021
11.	Statement No. 20	Sixth Session, 2021
12.	Statement No. 14	Seventh Session, 2021
13.	Statement No. 14	Eighth Session, 2022
14.	Statement No. 12	Ninth Session, 2022
15.	Statement No. 10	Tenth Session, 2022
16.	Statement No. 10	Eleventh Session, 2023
17.	Statement No. 8	Twelfth Session, 2023
18.	Statement No. 8	Fourteenth Session, 2023
19.	Statement No. 6	Fifteenth Session, 2024

EIGHTEENTH LOK SABHA

20.	Statement No. 5	Second Session, 2024
21.	Statement No. 4	Third Session, 2024
22.	Statement No. 2	Fourth Session, 2025

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) आधार (नामांकन और अद्यतन) प्रथम संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचक्यू-16024/4/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-5735) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदया, मैं, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52(4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Madam Chairperson, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Finance Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(ii) Memorandum of Understanding between the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2024-2025.

(iii) Memorandum of Understanding between the Railtel Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(iv) Memorandum of Understanding between the IRCON International Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(v) Memorandum of Understanding between the Konkan Railway Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(vi) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(vii) Memorandum of Understanding between the Braithwaite & Co. Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(viii) Memorandum of Understanding between the Container Corporation of India Limited (CONCOR) and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(ix) Memorandum of Understanding between the RITES Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(x) Memorandum of Understanding between the Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways for the year 2024-2025.

(2) A copy of the Notification No. S.O.2354(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th May, 2025, notifying that the Centre for Railway Information System (CRIS) be allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, to establish the identity of ticket-checking staff, crew members and passengers, using Yes/No or eKYC authentication facility, at the assigned duty station during duty sign on/off before start of and on completion of their duties or for their monitoring, as the case may be, issued under sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

(3) A copy of the Notification No. F.No.2023/E&R/1(1)/2(Pt.) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th May, 2025 notifying constitution of a new Division, mentioned therein, with headquarter at Jammu Tawi under Northern Railway with effect from 01.06.2025.

(4) A copy of the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.451(E) in Gazette of India dated 7th July, 2025 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : सभापति महोदया, मैं, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1459(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी (राजामुन्दरी) : महोदया, मैं, महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं: -

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों की कार्यप्रणाली' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2025-26) का पहला प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं' विषय पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2025-26) का दूसरा प्रतिवेदन।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 5TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD JOSHI): Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

(1205/SNL/MY)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 145th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE - LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 145th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

…

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 2nd AND 5th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I rise to lay the following statements regarding: -

(1) the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

(2) the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

…

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3rd REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Ministry of Railways.

…

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 253rd REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Madam, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 253rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region.

...

संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा से श्री पी. विल्सन की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। "

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा से श्री पी. विल्सन की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

...

*MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

1209 hours

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Chairperson Madam, for giving me this opportunity. I rise to draw the attention of this august House to a deeply disturbing and shocking incident that occurred on 05 July, 2025 at Durg Railway Station, Chhattisgarh.

Madam, on that day, two Catholic Nuns, Sister Vandana and Sister Preeti belonging to the Assisi Church Sister of Marry Immaculate, a Syro-Malabar congregation based in Cherthala, Kerala, were attacked and fiercely accused of religious conversion and human trafficking by Bajrang Dal. Madam, they belong to my constituency, and this institution belongs to my constituency. Do you know what work they have done? They were helping the cancer patients that were terminally-ill patients and they do maximum palliative care services. They were helping a lot of deprived people. Therefore, the people of that area like them very much. They have a service all over India.

(1210/SMN/MLC)

What happened in that Durg Railway Station? They along with three other women went to the railway station to board a train towards Agra. Certainly, Bajrang Dal people jumped on them and they stopped them, they manhandled them and they shouted on them with slogans. Finally, police came. We thought that police will come and rescue them because in the last Christmas period, our hon. Prime Minister went to CPCI headquarters and gave a big speech and made promises to protect minority rights and Christians' rights.

In Kerala, Madam, our BJP friends used to go to church with a cake during Christmas. They used to go with Christmas cake. But now what is happening? For the last five days, these innocent nuns are in jail without any reason. What a cruelty is this? Does our country have a banana republic? Without any reason, you are keeping them in jail. They are from minority community and that too, women.

---

* Please see pp. 383-385. for the List of Members who have associated.

Madam, yesterday, we sent our MPs, Shri Saptagiri Shankar Ulaka, Shri Premachandran, Shri Benny Behanan and Shri Francis George. You have to allow them also to narrate their experiences. We wrote to the Chief Minister of Chhattisgarh. We also wrote to the Home Minister of India. At least, these nuns have to be released. No action is taken so far.

The Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of the Bajrang Dal. What a shame? These types of activities are going on. Therefore, I think this is the high time to act. If the Government is not acting, the situation will go out of control because the situation in Kerala is also burning. Everywhere, agitations are happening. All nuns are in public. This is not only a Christian issue.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : ठीक है, माननीय सदस्य।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, please allow me to speak for one more minute. In Kerala, these people will attack Muslims.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, ये विषय राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, आपका विषय आ गया है।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): They will try to create difference between Muslims and Christians. In other parts of Kerala, they will attack Christians. At least, we need to tell them.

You are also a woman, Madam. Two nuns who were doing service are in jail without any reason and they have not committed any crime.

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री के. सुरेश जी।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Therefore, the Government has to intervene. We need a clearcut answer. The Government has to intervene and they have to release immediately those two nuns.

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Chairperson, as Shri K C Venugopal has pointed out, two innocent nuns, who never disobeyed the law, were unlawfully arrested from Durg railway station, Chhattisgarh. Now they are arrested and remanded to the jail by the Chhattisgarh police. The nuns who sacrificed their life for charity works, especially for the poor cancer patients, were charged with forceful religious conversion and are illegally arrested and jailed with the support of Government of Chhattisgarh. So, these

* Original in Malyalam

nuns should be released immediately. Along with that, the Government of India should intervene in the matters regarding this illegal torture.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य आप इस विषय को संक्षेप में रखिए।

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Ministry of Home Affairs and the Ministry of Minority Affairs should intervene in this matter and make a statement in this House regarding the issue. Madam, in this country, religious minorities are not safe. Christians are not safe.

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। … (व्यवधान)

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Opportunities for nuns to do social services are denied.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य प्लीज़ आप सभी बैठिए, विषय आ गया है। … (व्यवधान)

*SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Everywhere pastors, missionaries and priests are facing this problem.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य डॉ. के.सुधाकर जी। प्लीज माननीय सदस्य विषय आ गया है।

(1215/GG/RP)

€DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon'ble chairperson, thank you for allowing me to speak during the zero hour. Kharif season in monsoon is a very decisive period in Indian agriculture. Important crops like Paddy, jowar, groundnut, soya bean and pulses are grown by our farmers during this period. Even amidst the global conflicts,

our central government under the leadership of hon'ble Prime Minister shri Narendra Modiji, has provided 8 lakh 13 thousand tonnes of Urea to Karnataka state. Unfortunately, Karnataka government, which is lost in rampant corruption and weakened in bad governance, has failed to distribute the stock of Urea DAP fertilisers for the farmers and by doing so, it has done injustice to them. Therefore, hon'ble chairperson, I am hereby appealing to the central government to set right the issue.

Today, the situation in Karnataka is such that, the subsidised Urea which should be made available for Rs. 258 is sold in the black market for Rs. 500 to the farmers. Similarly DAP (Diammonium Phosphate) which should be made available for Rs. 1200 is sold at Rs. 2000 per bag. We, BJP MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha from Karnataka, under the leadership of the hon'ble Union Minister Shri Prahlad Joshi, met and apprised the concerned minister about the issue and urged him to issue an advisory to the chief secretary about the proper distribution of Urea and DAP that are available in the stock and black market. Thank you.

---

* Original in Malyalam

€Original in Kannada

1216 बजे

(इस समय श्री हैबी ईडन, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

1216 बजे

(इस समय श्री हैबी ईडन, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

… (व्यवधान)

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जनविरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है तथा बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके, बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश कर रही है। क्या यही "नया भारत" है जहाँ शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे ,हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है?

मान्यवर, शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर यही है क्या आपकी प्राथमिकता? आरटीई एक्ट, 2009 साफ कहता है कि हर बच्चे के घर के एक किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। यह मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुँचाने वाली है। बेटियाँ कैसे दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर स्कूलों में कैसे जाएंगी? गरीब का बच्चा कैसे अपना गांव छोड़ेगा और दूसरे गांव में पढ़ने के लिए कैसे जाएगा? यह नीति ड्रॉपआउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 16 जून, 2025 का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। दूसरा, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। तीसरा, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। चौथा, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लेकर केवल पढ़ाने दिया जाए।

सभापति महोदया, आज जब सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है।

महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर संसद में गंभीरता से विचार किया जाए और हर बच्चे को उसके गांव में शिक्षा का अधिकार दिलाया जाए।

(1220/RTU/YSH)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Thank You Chairperson. Today, I would like to draw the attention of the House to the denigrating remarks made by our YSRCP leaders against the modesty and dignity of women leaders

belonging to Telugu Desam Party in the State of Andhra Pradesh. The Father of Nation Mahatma Gandhi had said, 'to call a woman the weaker sex is a libel; It is man's injustice to woman.' In terms of brute strength, we might be less brute but in terms of moral strength, we are far better than men.

Today, these remarks have been made when the nation talks about 33 per cent women reservation, when nation no more talks about women development but women-led development under our Hon. Prime Minister Shri Narender Modi Ji and our Hon. Chief Minister Chandrababu Naidu. As we can see, the first AIIMS is given by a woman. Our languages which are put into the court has been given by a woman and what our Constitution is today, is because of our great women and so is the Judiciary and the Executive. Our nation has been led by a woman and also every woman in this nation is playing a role in strengthening our democracy. Why do you think that women perform better than men? This is because we care. We women are wise, outstanding, marvellous and educated, and we are nation builders.

Chairperson, we are not in politics just for the sake of hearing a male chauvinist speak about our character or judge our character. We are here to build the nation's character. Also our public life should never become a punishment to us. Chairperson, today, these remarks are not just verbal abuses. This verbal abuse is equally offensive as sexual abuse. Today, I am not speaking as a woman representative, but I am speaking here as a daughter, as a sister, as a wife who cannot be silenced with their abuse and who cannot be silenced at all in the future.

Chairperson, I would like to request you to bring in a Resolution and pass it today and also bring in a law that would protect the modesty and dignity of women of our country, especially women in public services.

Today, we are in politics and let us spread a word that abuse can no longer be tolerated, it cannot be normalised and also, the justice should not be delayed. Thank You Madam.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Thank You, Chairperson.

*Thank you Madam Chairperson for this opportunity. Hon. Prime Minister during his recent visit to Gangaikonda Cholapuram in Tamil Nadu assured that he will ensure making the pride and achievements of Cholas reach and spread wide throughout the world. Hon. Prime Minister gave a big assurance to the people and the State of Tamil Nadu that the pride of Cholas particularly of King Rajendra Chola would be spread throughout the world. He assured to do everything in this regard. On this basis, I have come here with a demand.

The Great Cholas ruled the world and controlled the sea because they had a powerful navy. Their ships carried over 1,000 elephants and they reached far and wide on the east coast. They conquered most of the present day South East Asian nations. The two ports from where they launched their naval expeditions are Poompuhar and Sembanarkoil. Both ports are laying within Mayiladuthurai Parliamentary Constituency. The Prime Minister, while lauding the Great Cholas at Gangaikonda Cholapuram on 27th July, announced that this Government will do everything to propagate the fame of the Cholas. I request the Government to announce offshore excavation of Poompuhar and Chembanarkoil coastal as they are treasure trove of information on the Chola legacy.

(1225/UB/STS)

Chola's legacy is India's legacy too. If offshore excavation is done at the site of Keeladi, India's naval might will be known to the world. I request the Government to announce a special project, a special team and allocate special funds to do offshore excavation along the coast of Poompuhar and Sembanarkoil. Both were the ports of the Great Cholas. ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महती सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। आज कैंसर की बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया है। यह महामारी आने वाले दिनों में सुनामी का रूप लेने जा रही है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैंसर के कई

* Original in Tamil

प्रकार के मामलों में वृद्धि देखी गयी है। लगभग सभी आयु वर्ग के मामलों में होंठ और ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर सहित बच्चों के भी कैंसर के मामलों में उछाल दर्ज की गयी है और चिंता जतायी गयी है कि 2050 तक इस क्षेत्र में नये कैंसर के मामलों में और इसके कारण मौत में 85 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। देश में बदलती जीवनशैली, पर्यावरण का क्षरण और कैंसर के प्रति जागरुकता की कमी के कारण नौ में से एक पुरुष और आठ में से एक महिला को कैंसर होने का खतरा है। भारत में प्रतिदिन हजारों लोग इस बीमारी के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस जटिल और गंभीर बीमारी के लिए समझ और सतर्कता की आश्यकता है। इसके प्रकार, कारण, लक्षण और रोकथाम की नीतियों के प्रति लोगों को अपने स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनया जा सकता है। सभी कैंसर से पीड़ित लोगों से कैंसर के बारे में ज्ञान साझा करना, प्रभावित लोगों का समर्थन करना और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि 'आयुष्मान भारत योजना' में पांच लाख नहीं पच्चीस लाख तक की इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। लखनऊ में जो कैंसर संस्थान है, उसको एम्स जैसी सुविधा देनी चाहिए और प्रयागराज में जो कमला नेहरू संस्थान है, उसको भी सरकारी मदद देनी चाहिए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी।

सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करती हूं कि वे अपनी बात को दो मिनट के भीतर रखने का प्रयास करें।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे महाराष्ट्र और खास करके मेरे सांगली जिले के जो किसान है, वे ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं। अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और अंगूर से आगे जाकर किशमिश बनता है। किशमिश का एक्सपोर्ट होता है और अलग-अलग राज्यों में जाता है। इसलिए किसानों को इसमें ज्यादा अच्छी आमदनी मिलती है। दुर्भाग्य यह है कि किशमिश का जो भाव है, वह गिर रहा है। उसका कारण यह है कि चाइना का किशमिश, चाइना में अंगूर उपजाकर उससे जो किशमिश तैयार होता है, वह किशशिम नेपाल के माध्यम से अवैध रूप से भारत में स्मगल हो रहा है। स्मगल होने के कारण भारत के किशमिश के रेट गिर रहे हैं और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार को यह इल्लीगल इम्पोर्ट बंद करना चाहिए। पहले जो किसान एक्सपोर्ट करते थे, उनको कुछ सब्सिडी दी जाती थी। उस सब्सिडी के कारण यहां डिमांड-सप्लाई मेंटेन रहता था और किसानों को अच्छी आमदनी मिलती थी। मेरी सरकार से विनती है कि वह सब्सिडी वापस से शुरु करें, एक्सपोर्ट के लिए किसानों को कुछ फायदा दें और इल्लीगल इम्पोर्ट बंद करायें। धन्यवाद

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री धर्मबीर सिंह जी।

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : मैं आपका ध्यान, मेरे लोक सभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी में किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है, जिसमें फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में इस योजना का बहुत फायदा मिला। परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझ कर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर-कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया।

(1230/MM/NKL)

इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय, जब हरियाणा में चुनाव का दौर था और आचार संहिता लगी हुई थी तो 20 अगस्त, 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइज़र के नाम पर किया गया, जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताया गया। इससे हमारे भिवानी और दादरी में कपास के किसानों का लगभग 300 करोड़ रुपये, जिसमें स्टेट और सेंटर का शेयर था, वह क्षेमा कम्पनी थी, जो दक्षिण भारत में वर्ष 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी, वह उस पैसे को लेकर चली गयी। मेरी कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया।

डॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 'शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पीएगा वह दहाड़ेगा।' लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की बहुत दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लेपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं।

मान्यवर, हम आंवला लोक सभा क्षेत्र से आते हैं। आंवला लोक सभा ग्रामीण क्षेत्र की लोक सभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि 'सब पढ़ें, सब बढ़ें।' इसी लोक सभा ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया। इसी लोक सभा ने सभी को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे सबको शिक्षा का अधिकार मिले। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : धन्यवाद सभापति महोदय, आज हमारे बीच सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी बैठे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे भी यह बात संबंधित रहेगी। मैं चाहूंगा कि उनका मेरी तरफ कुछ आकर्षण रहे।

महोदया, आज पहले प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि किस प्रकार से साइबर क्राइम पर वह नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी लाखों टेलिफोन और सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है। लेकिन क्या इनको ब्लॉक करना हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। स्पैम कॉल्स 146.3 करोड़ लोगों को हर रोज़ दर्जनों के हिसाब से मिलता है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स आधार कार्ड से लिंक सिम कार्ड देते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी कम्पनियां, जैसे – अभिनंदन लोढ़ा, पीएनबी मैटलाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी म्युचूअल फंड हैं, इनको दिया जाता है। इनके नंबर मैंने बार-बार दिए हैं और ब्लॉक भी हुए हैं, उसके बावजूद भी नंबर आते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन बड़ी कंपनियों को बंद करेगी? क्योंकि यह जड़ है। इस जड़ को खत्म किया जाए, क्योंकि एक नंबर ब्लॉक करें, दूसरा, तीसरा करें, लेकिन वे एक, दो और तीन हजार सिम कार्ड ले लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। ऐसे में, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सिम कार्ड की जगह इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों - अभिनंदन लोढ़ा, पीएनबी मैटलाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस और ऐसी ही बहुत सारी कम्पनियां हैं क्या उनको बंद करेगी? जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्राइवेसी में आर्टिकल 121 में मेरी प्राइवेसी है। वह मेरा फंडामेंटल राइट है। इसका उल्लंघन हो रहा है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं If the Government cannot stop industry-backed data theft and spam nuisance, how can it protect us from AI-driven cyber frauds? यहां हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित हैं और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया होगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सोर्स है, उसको बंद करेंगे। सिम कार्ड बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक, दो या दस हजार तक ब्लॉक करते रहिए, ये नये-नये लेते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1235/MK/VR)

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : सभापति महोदया, हाल ही में आयी भीषण बाढ़ ने हमारे क्षेत्र के कई गाँवों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की मेहनत और आजीविका को गहरा आघात पहुंचा है। इसके अलावा दर्जनों मकान पूरी तरह से ढह गए हैं। कई परिवार आज खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। न बिजली है, न साफ पीने का पानी है और न आने-जाने की सुविधा है।

अत: मैं सरकार से मांग करती हूं कि वह संबंधित विभागों को निर्देश दे कि प्रभावित गाँवों का तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए। धान की नष्ट फसलों के लिए किसानों को उचित और जल्दी मुवाअजा प्रदान किया जाए। जिनके घर बर्बाद हुए हैं, उन्हें पीएम आवास योजना या आपदा राहत फंड के तहत सहायता दी जाए। राहत सामग्री, जैसे भोजन, कपड़ा और दवा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत दिलाई जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपकी इजाजत से आज इस सदन का ध्यान एक ऐसी महामारी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति, हमारे युवाओं को नष्ट करने की और बढ़ रही है। वह है नशीली पदार्थों का सेवन, जो भयावह स्तर पर पहुँच गया है।

महोदया, पिछले पाँच सालों में भारत में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में दो करोड़ से ज्यादा युवा इसके आदि हो चुके हैं।

महोदया, यह जो मादक पदार्थ है, यह केवल गाँव और शहर में ही नहीं, बल्कि विद्यालयों की कक्षाओं में भी पहुंचने लग गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी पहुंच रहे हैं। इससे युवाओं का ध्यान शिक्षा की ओर न होकर अपराध और नशे की ओर जा रहा है

मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के पास एक चुरु लोक सभा क्षेत्र है, वहां यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है। इसके लिए सरकार एक विशेष कार्य बल गठित करे और हमारे युवाओं को तथा हमारे देश को इस नशे की प्रवृत्ति से बचाए। धन्यवाद।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : धन्यवाद सभपति महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में जालंधर कंटोनमेंट एरिया की कुछ प्रॉब्लम्स, जिनको पब्लिक फेस कर रही है और उसको लेकर पब्लिक में रिसेंटमेंट है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक मुस्लिम ईदगाह कंटोनमेंट एरिया में है। वह मुस्लिम ईदगाह वर्ष 1909 से मुसलमानों के कब्ज में है। वह उनको दान की गई थी। लेकिन, अब दस दिन का एक नोटिस देकर उसको खाली करने के लिए कहा गया है।

दूसरा, कंटोनमेंट एरिया में जो सिविलियन लोग रहते हैं, उनके पास एलॉटेड लैंड है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है।

तीसरा, उसके चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनना है। उसकी भी प्रॉब्लम है। मैं आपसे दो मिनट चाहता हूं। जो ईदगाह है, वह वर्ष 1909 से उनके कब्जे में है और वे वहां उसी समय से नमाज पढ़ रहे हैं। उनको वह जगह दान की गई थी। वर्ष 1995 में सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन जारी की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या आपत्ति है कि वहां नोटिस जारी करके उसको खाली कराया जा रहा है? इससे मुस्लिम कम्युनिटी में रिसेंटमेंट है। यह माइनॉरिटी पर हमला है। इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि उस ईदगाह को उनको वापस दिया जाए और नोटिस को खारिज किया जाए।

वहां के जो सिविलियन्स हैं, उनकी जो एलॉटेड लैंड है, उसकी रजिस्ट्रेशन को जो बंद कर दिया गया है, उसको खोला जाए। उससे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे 13 गाँव हैं, जिनके लिए पंजाब सरकार ने प्रपोजल भेजा है कि कंटोनमेंट एरिया के चारों तरफ एक पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी। अगर सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कंटोनमेंट एरिया और फौजियों को भी फायदा होगा।

(1240/ALK/SNT)

लोग अंदर से होकर जाते हैं फिर वह पेरीफेरल रोड से जाएंगे। हमारे एमएलए परगट सिंह जी भी मंत्री जी से मिले हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है ये तीनों बड़े संवेदनशील इश्यू हैं। माइनोरिटी का इश्यू है।, माइनेरिटी से उनका नमाज पढ़ने का हक छीना जा रहा है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको सीरियसली कंसीडर किया जाए।

श्री लुम्बा राम (जालौर) : मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही दोनों जिले डार्क जोन घोषित हैं। यहां पर पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर, 1965 के अनुसार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित था। 1 अक्टूबर, 1966 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौते में कांगड़ा बांध का निर्माण नहीं हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कडाणा बांध का पानी तब मिलेगा जब तक नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में नहीं आएगा। वर्ष 2005 से नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले को मिल रहा है जबकि सतही समझौते के अनुसार कडाणा बांध और माही बांध के 2/3 राजस्थान के सिरोही, जालौर तय हो चुके थे लेकिन जालौर, सिरोही को पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कडाणा बांध का ओवरफ्लो होकर पानी सुजलाम्, सुफलाम् नहर के द्वारा समुद्र में जा रहा है। भास्कर कमेटी द्वारा सर्वे किया गया जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख एमटीसी पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सुजलाम सुफलाम नहर को सुदृढ़ कर नर्मदा कैनाल से जोड़कर जालौर, सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए और इसके लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस हेतु गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। मैं जालौर, सिरोही की जनता और किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. नामदेव किरसान (गड़चिरोली-चिमुर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जून-जुलाई में फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय किसानों को खाद की जरूरत होती है। इस समय फसल लगाई जाती है और इसी समय खाद की किल्लत शुरू हो होती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड खाद निर्माण की एक यूनिट है। इस यूनिट को बताया गया है कि 70 प्रतिशत खाद महाराष्ट्र और 30 प्रतिशत अन्य राज्यों को दी जाएगी, लेकिन यह रेश्यो मेनटेन नहीं होता है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के किसानों को खाद नहीं मिलती है। इसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हमारी कांस्टीटुएंसी से लगा हुआ है। हमारे कुछ तालुका और विधान सभा कांस्टीटुएंसी इसके पास में आती है। उस यूनिट की खाद हमारे पास के क्षेत्र एरिया को जल्दी मिलने से बहुत सुविधा होगी।

महोदया, खाद की सप्लाई समय पर होनी चाहिए। इसके लिए जो भी सप्लायर कम्पनियां हैं, उनको निर्देश देना चाहिए। ये कंपनियां खाद के साथ लिंकिंग करती हैं। आपने डीएपी लिया तो

डीएपी के साथ नेनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती हैं, यह लिंकिंग बंद की जाए। महाराष्ट्र को 15 लाख 52 हजार मीट्रिक टन की सप्लाई एश्योर्ड की गई है, वह अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ 5 लाख 20 हजार मीट्रिक टन ही हुई है।

(1245/SK/AK)

डीएपी का लक्ष्य 4 लाख 60 हजार मीट्रिक टन एश्योर किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1 लाख 26 हजार मीट्रिक टन ही हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया जाए। फसल लगाने के समय किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। किसानों ने रबी और खरीफ का धान एमएसपी पर बेचा है, लेकिन अब तक उसका पैसा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि वह पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रामटेक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के लोगों की आजीविका जंगल पर निर्भर करती है। जब से पेंच नेशनल पार्क बना है, वहां आदिवासियों को आने-जाने से रोका जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है जबकि उनकी किसानी-खेती जंगल से है। इसकी वजह से हमेशा उन पर टाइगर अटैक्स होते हैं और उनकी जानें जाती हैं। मैंने आंकड़े निकाले हैं कि पूरे देश में सात सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेरे पास वर्ष 2023 तक के ही आंकड़े हैं क्योंकि पिछले तीन सालों के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले तीन सालों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनकी उपजीविका ही पूरी तरह से जंगल पर आधारित है। जंगलों को सुरक्षित करने का काम आदिवासी लोग ही करते हैं। आदिवासियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है और उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। उनके लिए न तो पशुपालन के लिए कोई कॉरिडोर बनाया जाता है, न उनकी उपजीविका के लिए कुछ किया जाता है। ये लोग हमेशा मौत से जूझते रहते हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए ताकि उनकी जान बच सके। मेरा अनुरोध है कि उनके लिए खेती और उद्योग करने के लिए योजना तैयार की जाए। 11 सालों से यह सरकार चल रही है, लेकिन आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आदिवासी भी इस देश के नागरिक हैं। वे जंगली नहीं हैं, जानवर नहीं हैं, इंसान हैं। धन्यवाद।

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय आभार व्यक्त करता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र हाथरस में कोरोना के समय दो महत्वपूर्ण रेल बांदीकुई से बरेली पैसेंजर और देहरादून से सूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस बंद कर दी गई थीं। मेरा निवेदन है कि दोनों रेलों को पुन: चलाने की

कृपा करें। दिल्ली से अलीगढ़ वाया लखनऊ सुबह दो महत्वपूर्ण रेल स्वर्ण शताब्दी और वंदे भारत अलीगढ़ होकर जाती हैं। अलीगढ़ में इनका स्टॉपेज है लेकिन हाथरस जंक्शन में स्टॉपेज नहीं है।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसलिए बहुत लोगों को हाथरस से लखनऊ जनहित में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें से कम से कम एक रेल को वहां रुकवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : माननीय सभापति जी, मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र जलगांव में जनता को हो रही गंभीर असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

गाड़ी संख्या 19005 सूरत-भूसावल एक्सप्रेस, जो पूर्व में उधना से रात 11 बजकर 27 मिनट पर प्रस्थान कर सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर जलगांव पहुंचती थी और कोविड-19 के बाद सुबह सात बजे पहुंच रही है। इस बदलाव से दोंडाईचा और धरणगांव के विद्यार्थियों, सरकारी और निजी कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इसके लिए उन्हें तीन बजे उठकर यात्रा करनी पड़ती है और मानसिक तनाव के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। यदि यह ट्रेन उधना से 1 बजकर 30 मिनट पर चलेगी तभी 8 बजकर 45 मिनट पर जलगांव पहुंचना संभव हो सकेगा।

दूसरी गाड़ी संख्या 11113 देवलाली-भुसावल एक्सप्रेस पूर्व में चालीसगांव और पाचोरा में क्रमश: 7 बजकर 40 मिनट और 8 बजकर 30 मिनट पर पहुंचती थी, लेकिन अब इसमें भी दो घंटे की देरी हो रही है।

(1250/VB/SRG)

इस बदलाव से लगभग 5 हजार दैनिक यात्री, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, मरीज और किसान प्रभावित हो रहे हैं। वे अब मजबूरी में निजी वाहनों और असुरक्षित साधनों से यात्रा कर रहे हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक जोखिम बढ़ रहा है।

अत: मेरी मांग है कि उपरोक्त दोनों गाड़ियों को समय-सारणी के अनुसार बहाल किया जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और उनकी कार्य-क्षमता और जीवन प्रभावित न हो।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र के बारे में एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से, सदन का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर की तरफ दिलाना चाहूँगी।

समस्तीपुर लोक सभा क्षेत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का क्षेत्र है, जो सामाजिक न्याय के साथ-साथ शिक्षा और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ उठाते थे और उसके लिए काम करते थे।

मेरे समस्तीपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जिसने कृषि के क्षेत्र में रिसर्च और एकेडमिक शिक्षा के माध्यम से, देश भर में अपना नाम स्थापित किया है। लेकिन जहाँ यह कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहाँ हमारे युवा साथी

इंजीनियरिंग या कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इनकी पढ़ाई के लिए मेरे लोक सभा क्षेत्र में इंस्टिट्यूट्स नहीं हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, सरकार से माँग करती हूँ कि नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी या आईआईटी जैसे इंस्टिट्यूट्स समस्तीपुर में खुलें ताकि मिथिला के भी युवा छात्रों को शिक्षा में समान अधिकार मिले। उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डेन पड़ता है और ब्रेन-ड्रेन की जो समस्या हमारे लोक सभा क्षेत्र में हो जाती है, चूंकि अगर उनको कानून या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो उनको पटना, दिल्ली, मुम्बई आदि शहरों में जाना पड़ता है, तो इनकी व्यवस्था करने से इस समस्या का हल हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि केन्द्र सरकार आईआईटी और एनएलयू जैसे इंस्टिट्यूटस समस्तीपुर में खोले और युवाओं को समान अवसर दे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, पिछले कई दिनों से शून्यकाल नहीं हुआ था। मेरे पास शून्यकाल में बोलने वाले सदस्यों की एक लम्बी लिस्ट है। मैं आज उन सभी लिस्ट्स में से बारी-बारी से नाम पुकार रही हूँ। कृपया, आप लोग अपनी बात एक-एक मिनट में रखें।

श्री गुरजीत सिंह औजला - उपस्थित नहीं।

श्री महेश कश्यप।

श्री महेश कश्यप (बस्तर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी विपक्ष के नेताओं के द्वारा बस्तर के विषय में बात रखी गई। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जल-जंगल-जमीन से भरे बस्तर को 60 साल तक काले पानी की सज़ा जैसा बनाकर रखा। वहाँ माओवाद, गरीबी, अशिक्षा आदि समस्याएं दी गईं। उसी का फायदा उठाकर आज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में अलग-अलग गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। अबूझमाड़, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में जहाँ कोई भी सामान्य आदमी नहीं घुस सकता है, वहाँ की आदिवासी महिलाओं और बेटियों को अलग-अलग राज्यों में ले जाकर धर्मांतरण जैसे जाल में फंसाना, उनका शारीरिक शोषण कराना और उनसे तस्करी करायी जाती है।... (व्यवधान) यह उनको पता होना चाहिए।... (व्यवधान) आप बस्तर में आइए।... (व्यवधान) बस्तर के आदिवासी बेटियों और बहनों के साथ लगतार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं।... (व्यवधान) कई बार गलत नामों से उनकी शादी कराकर उनको धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है।... (व्यवधान) ऐसे सैंकड़ों मामले हैं।... (व्यवधान)

इसलिए मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र की बेटियों-बहनों की रक्षा करने के लिए एक स्पेशल कानून बने।... (व्यवधान) ऐसा करने वालों को ये संरक्षण न दे पाएं, मैं यह मांग करता हूँ।... (व्यवधान)

SHRIMATI PRIYANKA GANDHI VADRA (WAYANAD): Madam, thank you very allowing me to speak today on behalf of the people of Wayanad whom I represent in this House. I would like to inform the House that it has been one year since a terrible natural disaster struck them. Hundreds of people lost their lives. Madam, 17 whole families were wiped out. More than 1,600 buildings, including homes, shops, businesses were destroyed in the landslide and the floods that followed. Hundreds of acres of land and crop were also destroyed. There are coffee plantations, there are tea plantations. Most people's livelihoods depend on that and on cardamom, tea and coffee. There are people whose entire lives were destroyed, including those of auto drivers, jeep drivers, people who run homestays and do small businesses.

(1255/SJN/SM)

It has been one year now, and I regret to inform you their proper rehabilitation has still not been done. The primary cause of this failure is the inadequate support and funding from the Centre. For an entire year, we have been making requests. I have personally raised this issue multiple times in the House. We have met with the Home Minister. We have persistently sought the release of funds. Some funds were indeed released, but they were insufficient.

Moreover, they were given as loans. This is unprecedented for people who have lost everything, their lives, their livelihoods. They have no means left and we are expecting them to repay what the Government owes them to rebuild their lives.

Madam, we urged for this to be declared a national disaster, but despite our many pleas, it was not done. Eventually, it was designated as a disaster of severe nature. Still, this falls short of what is needed, as evident by the fact that those victims and their families continue to struggle even one year later.

Madam, I wish to read out a judgement by the hon. High Court. Hon. Justice AK Jai Shankaran Nambiar and Justice PM Manoj, in the High Court of Kerala, have observed that the Centre holds the authority to waive these loans. The Centre cannot claim it lacks the power to waive these loans.

Madam, it is my sincere and heartfelt request, on behalf of the people of Wayanad, that the Central Government considers waiving these loans. These loans amount to a small sum for the Centre. It is only Rs.90 crore in personal loans and Rs.36 crore in agricultural cooperative bank loans. This is a very small amount for the Centre.

It is my earnest appeal on behalf of all those people that the Central Government considers this on a humanitarian basis.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, मैं पिछले 10 साल से या उससे अधिक समय से भी लगातार एक बात कह रहा हूं। मेरा संथाल परगना नामक इलाका है। इस सदन में सभी लोग अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या केवल और केवल 27 प्रतिशत है। अभी जो जनगणना शुरू होगी, तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि उनकी संख्या 21 या 22 प्रतिशत होगी।

आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं। उन आदिवासियों को विलुप्त करने में, जो वहां की राज्य सरकार है, वह 'आधार' का सहारा ले रही है। 'आधार' सिटिजनशिप का मामला नहीं है, बल्कि 'आधार' रेसिडेंट का प्रूफ है। उसके आधार पर वहां बांग्लादेशी घुसपैठिएं आ रहे हैं और वे वहां की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। वे जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस कारणवश एक ऐसा दिन आएगा, हमारे यहां वर्ष 2008 में जनगणना नहीं हुई थी। झारखंड में वर्ष 2008 में जनगणना इसलिए नहीं हुई थी, क्योंकि आदिवासियों की संख्या घटने के कारण अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए आरक्षित एक लोक सभा की सीट और छः विधान सभाओं की सीट्स समाप्त हो रही थीं।

अभी जब नई जनगणना होगी, तो मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए आरक्षित लोक सभा की दो सीट्स और कम से कम विधान सभा की 12 सीट्स घटेंगी। यह पूरे देश के समक्ष एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जो हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वहां पर 'एनआरसी' लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट भी यही कहता है। वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, उनको नेस्तनाबूद करिए तथा हमारे झारखंड राज्य और संथाल परगना को बचाइए।

(1300/PC/GM)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी और माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि बाबासाहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज को कमजोर करना हो, उसको शिक्षा से वंचित कर दो।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, बुनकरों, किसानों और छोटे-छोटे गरीब परिवारों को मुख्यधारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करती जा रही है।

सभापति महोदया, जहां हम आजादी का 'अमृतकाल' मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है। जहां 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के तहत हम पर यह कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,012 स्कूल्स बंद कर दिए गए और 5,000 स्कूल्स का मर्जर कर दिया गया। वहां दो लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है।

सभापति महोदया, जहां गरीब लोग, पीडीए परिवारों के लोग और दलित लोग शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई हैं।

सभापति जी, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए, केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। यह हो सकता है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों को उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं या वहां आपस में इंजन टकरा रहे हैं। लेकिन, यदि इंजन टकरा रहे हैं, तो टकराते रहें। उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जन-मानस स्वीकार नहीं करेगा।

इसीलिए, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीडीए नायक के तौर पर जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर सरकार स्कूल बंद करेगी, तो हम 'पीडीए पाठशाला' चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे। हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल्स बंद नहीं होने देंगे, यह मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Madam, I rise today, not as a Member of this House, but as a colleague of those thousands of families in Delhi which have been rendered homeless overnight. Let us be clear that those were not just structures of brick and tin that were demolished, and so were the memories, livelihoods and children's dreams. Today, those children who had books in their hands, have instead been holding bricks, standing in the rubble of what once was their shelter.

Madam, law is not optional. The Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015, the DUSIB Act of 2010 and the Delhi High Court's judgement in Ajay

Maken vs. Union of India clearly state that there should be no eviction without rehabilitation, no demolition without dignity. Yet, bulldozers moved in with no notices. Families were thrown out, with no alternative housing. Even their court stays exist in Jailorwala Bagh and Madrasi camp, homes were still destroyed in open violation of judicial orders. No water, no power, no shelter; just silencing and suffering.

Amidst this silence, one voice did rise. The Leader of the Opposition in this House, Shri Rahul Gandhi visited the demolition sites. He walked through the broken lanes and met mothers sitting in the drains with infants in their arms, and listened truly to their pain. He came with compassion and clarity and asked one question we all also must ask today. If we can send bulldozers so quickly, why can we not send help with the same urgency? Before elections, the ruling party friends spent nights in the same basti, made promises 'जहां झुग्गी, वहां मकान'। But now after the elections, it has become 'जहां झुग्गी, वहां बुल्डोज़र'। This is not governance; this is abandonment. It is time for this House to take notice. How we keep the poorest amongst us, is not the issue, but it is the very soul of this democracy.

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, आज मैं सिक्किम के संदर्भ में एक ऐसे मुद्दे को यहां रखने जा रहा हूं, जो दो दशकों से अविलंबित है। 'लिंबू' और 'तमांग' इन दोनों कम्युनिटीज़ को वर्ष 2003 में शेडयूल ट्राइब में इन्क्लूड किया गया था। लेकिन, दो दशकों के बाद आज भी सिक्किम लजिस्लेटिव असेंबली में इनका सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ है।

(1305/SPS/RCP)

आर्टिकल 371एफ के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बु और तमांग कम्युनिटीज की सीट का रिज़र्वेशन किया जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब्स होने के नाते आर्टिकल 332 भी मेन्डेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब्स को सीट रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। इस 18वीं लोक सभा की शुरुआत से ही गोवा के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब्स को सीटों में रिज़र्वेशन देने के लिए रीएड्जस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल इन द असेंबली ऑफ गोवा को ऑलरेडी हाउस में रखा गया है और इसको पास करना बाकी है। सिक्किम की शेड्यूल ट्राइब्स लिम्बु और तमांग को शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में वर्ष 2003 में इन्क्लूड किया गया था, लेकिन आज तक रीएड्जस्टमेंट की कोई बात नहीं हुई है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आर्टिकल 371एफ और 332 के अंतर्गत भुटिया-लेप्चा, संघा और शेड्यूल कास्ट्स की सीटों को पुन: सुरक्षित रखते हुए लिम्बू और तमांग के लिए भी सीट रिज़र्वेशन दिया जाए। रीप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का अमेंडमेंट करके लिम्बू और तमांग शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिज़र्वेशन किया

जाए, ताकि जो अब डीलिमिटेशन होने वाला है, इस डीलिमिटेशन में लिम्बू और तमांग को सीट दी जा सके। ऑलरेडी पांच इलेक्शन्स हो चुके हैं और लिम्बू और तमांग कम्युनिटीज़ ने बिना किसी सीट रिज़र्वेशन्स के इलेक्शन्स लड़े हैं और आज तक उनकी किसी सीट का रिज़र्वेशन नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करता हूं कि लिम्बू और तमांग के अविलंबित इश्यू को रिज़ॉल्व किया जाए और सीट रिज़र्वेशन दिया जाए।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : मैडम, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सर्वशांति वार्ता का प्रतीक हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल दरबार सहिब, जहां पर अमृतता का उपदेश मिलता है। पूरी संसद के लोग भी वहां जाते हैं और वहां पर सबके भले के लिए अरदास होती है। ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे और आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं होता है, वे लगातार 14 जुलाई से वहां धमकी भरे ई-मेल भेज रहे हैं। जो आदमी गुरू ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी को जानता है, वह आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये आतंकी लोग ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ई-मेल भेज रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी चिंतित है और सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं ढूंढा गया है। अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 14 जुलाई से आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाए हैं।

मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसी पवित्र जगह अमृतसर पर अटैक भी हुआ, जब यह बात चल रही थी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान ने नापाक इरादों से अमृतसर और पूरे देश के ऊपर हमले भी किए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी मानवता वाली जगह को 'नो-वॉर जोन' घोषित करना चाहिए। सरकार को यह मुद्दा इंटरनेशनली उठाना चाहिए। जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से पकड़कर सलाखों को पीछे फेंके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटा मुंह, ओछी बात कर दी। उन्होंने पचास परसेंट दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूंगा कि यदि वर्ष 1971 की बात को लिया जाए, तो बलिदान भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया गया। जो जंग मैदान में जीती थी, वह मेज पर जाकर हार दी। यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे, तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा और मैं उतारना चाहता हूं।

मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारे एक महान स्वाभिमानी देश भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, उसमें ऐसा लगता है कि उनके सामने के एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। उस चिट्ठी से पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था।

… (व्यवधान)

(1310/KN/PS)

देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी। ... (व्यवधान) आयरन थी कि इलास्टिक था, यह आप तय कर लें। ... (व्यवधान) मैं उसके बारे में कुछ पढ़ कर बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान) 3 दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके दो दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी नहीं है, बल्कि एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिये, वे लिखती हैं। राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रमकता तथा सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें, जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है।

वे आगे लिखती हैं कि क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रमक गतिविधियों को राके सकें। क्या उस समय की सेना पर इंदिरा जी को विश्वास नहीं था या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, जो अमरीका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़गिड़ाने का काम कर रही थीं?

माननीय सभापति जी, अगर आप यह देखेंगी तो बड़ा स्पष्ट लिखा।

> "I regret to inform Your Excellency that around 1730 hours on the 3rd of December, Pakistan launched a massive air and ground attack on our country all along the western border. Their aircraft bombed Srinagar, Amritsar, Pathankot, Uttarali, Ambala, Agra, Jodhpur and Avantipur. There has also been heavy shelling of the border cities and townships of Ambala, Ferozepur, Sulaimanki, Khemkaran, Poonch, Mehdipur and Jaiselmere."

मैडम, वे आगे लिखती हैं:

> "It is also significant that within minutes of the launching of the attack the Pakistani publicity media launched a malicious propaganda offensive accusing India of having attacked West Pakistan earlier in the afternoon."

मैडम, सवाल यह खड़ा होता है कि अगर उस समय ... (व्यवधान) मैं कोई छिपा नहीं रहा। मैं आपके सामने तथ्य को ला रहा हूं, जो उस समय की सरकार ने चिट्ठी लिखी।... (व्यवधान) मैडम, सवाल यह खड़ा होता है और मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए।... (व्यवधान) मैडम, मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए।... (व्यवधान)

> "In this hour of danger the Government and the people of India seek your understanding and urge you to persuade Pakistan to desist forthwith from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I

request Your Excellency to exercise your undoubted influence with the Government of Pakistan to stop their aggressive activities against India."

मैडम, यह कौन गिड़गिड़ा रहा था, कौन गुहार लगा रहा था, कौन मदद मांग रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय दम दिखाया या भारत को बेदम करके दिखाया? इंदिरा गांधी जी ने अमरीका के सामने दीन-हीन भाषा में यह पत्र क्यों लिखा? ... (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि आप अमरीका के पास युद्ध रुकवाने के लिए क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? ... (व्यवधान) आपने कहा कि पाकिस्तान मेलेसियस प्रोपेगंडा करता है। आज वही प्रोपेगंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं।... (व्यवधान) दरअसल, यह परिवार और पार्टी दंडवत होने तथा झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप 50 परसेंट कहते हैं।... (व्यवधान) अरे, 50 परसेंट जीरो का भी जीरो ही होता है।... (व्यवधान) आपमें जीरो दम था।... (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया है।... (व्यवधान)

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, hon. Madam Chairperson. I rise with a deep concern to highlight two grave issues affecting maize and coconut farmers in my constituency, Hassan, Karnataka.

Firstly, maize, our primary crop, has been severely affected by fast-spreading fungal disease called downy mildew disease. Out of 45,000 hectares sown in this season, over 12,000 hectares are already affected. The disease is both soil-borne and airborne, making it highly contagious. Despite local awareness efforts, farmers are unable to contain the spread.

I urge the Union Government to implement the observations given by a special team from ICAR who surveyed the issues and approved compensation for affected farmers to prevent deep economic distress.

(1315/RAJ/SMN)

Secondly, coconut farmers in Hassan, Karnataka's second-largest coconut-producing district which is my district, are facing severe challenges. Cultivation over 1.18 lakh hectares, mainly in Arsikere and Channarayapatna, is hit by large-scale pest and disease infestation. As per CPCRI data, 82,000+ hectare is affected by rugose white fly, 15,704 hectare by stem bleeding and 10,473 hectare by black headed caterpillar.

I humbly request the Ministry of Agriculture to extend CPCRI demonstration programs and upgrade biocontrol labs in Arsikere and

Holenarsipura and announce a special support package through Coconut Development Board.

Thank you, Madam.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदया, मेरे लिए यह बहुत अच्छा मौका है कि माननीय रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं।

सभापति महोदया, रेलवे अधिनियम धारा 70 भेदभाव रहित सेवा को नियंत्रित करता है। बिहार में चम्पारण सबसे बड़ा जिला है। चम्पारण में चनपटिया एक मात्र नगर रेलवे स्टेशन है, जहां पर सभी प्रमुख ट्रेन्स नहीं रुकती हैं। जबकि चम्पारण के पंचायत में भी एक ऐसा स्टेशन है, जहां ट्रेन रुकती है। बिहार में दो एसईजेड दिए गए हैं, उनमें चनपटिया और बक्सर हैं। हमारे चनपटिया के स्टार्ट अप जोन के लिए पूरे देश के सेक्रेट्रीज की मीटिंग में माननीय प्रधान मंत्री जी ने डीएम से कहा कि आपने कैसे यहां स्टार्ट अप जोन इतना सक्सेसफुल किया?

सभापति महोदया, चनपटिया में सप्तक्रांति एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस, पोरबंदर एक्सप्रेस, यहां तक की सत्याग्रह एक्सप्रेस भी नहीं रुकती है। जबकि चम्पारण राजकुमार शुक्ला जी की धरती है, जो महात्मा गांधी जी को लेकर चनपटिया गए थे। राजकुमार शुक्ला जी की धरती पर भी चम्पारण-सत्याग्रह ट्रेन नहीं रुकती है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि चनपटिया में ट्रेनों का जरूर स्टॉपेज दें। यह एक मात्र नगर है, जहां ये ट्रेन्स नहीं रुकती हैं।…(व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Madam.

Madam, the National Highway 85 is passing through my constituency and goes from Kochi to Munnar.

Madam, in the last week, that is, on 11th July, hon. High Court has given a judgement. It is against the National Highway development which was going on there. They banned the widening works which have taken place there. The issue is that the Forest Department unwantedly intervened in this case. They have no claim on this land. In this particular stretch from Neriamangalam to Valara area, the ownership is completely vested upon Revenue Department as well as PWD. But, indirectly, Forest Department has helped a private man to go to court and hon. court intervened and stopped the works.

I urge upon this Government to seek the intervention of Kerala Government to change the affidavit filed by Chief Secretary of Kerala. It was a false affidavit. Due to that affidavit only, the High Court verdict came out against the National Highway development. I seek the intervention of the Government of India to change the affidavit filed by the Kerala Government.

Madam, NHAI advocates, the Standing Counsels of NHAI are not all appearing in the courts. That is why, I am seeking the intervention of hon. Minister Shri Nitin Gadkari Ji also.

Thank you, Madam.

श्री राजीव राय (घोसी) : सभापति महोदया, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र से संबंधित यातायात के मामलों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैडम, सबसे पहले मैं एक अच्छे काम के लिए सरकार और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद दूंगा। मैंने इसी सदन में और उनके ऑफिस में जाकर बलिया-मऊ के लिए फोर लेन सड़क की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए तत्काल आदेश कर दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मेरी बैठक भी करवा दी और इंस्पेक्शन भी करवा दिया। उस रोड की डीपीआर बन गई है। हालांकि अब उसका क्रेडिट कोई और लेने आ रहा है। क्रेडिट मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता को जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन उस सड़क का कार्य तत्काल शुरू करा दिया जाए, क्योंकि वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

मैडम, दूसरा मामला वाराणसी से गोरखपुर रोड का है। हमें पत्र भी दिया गया है। मैंने माननीय मंत्री जी से कहकर जांच करवाई थी। जांच में यह पाया गया कि ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया है। एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं। मुझे मंत्री जी के यहां से लिखित रूप से पत्र आया है कि 30 मई तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आज तक वहां कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं।

(1320/NK/RP)

सरहरी-दोहरीघाट अंडपास के अंदर पानी लग गया है, इसे दस किलोमीटर तक लोग प्रभावित होते हैं, सरहरा में जो पुल बना है वह पूरा नहीं हुआ है, न जाने कितने लोग मर गए। अगर यातायात सही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी।

यहां दोनों रेल मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने सदन में वादा किया था और हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एक साल हो गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो वादा किया था, उसे पूरा किया जाएगा।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। दार्जिलिंग भारत के सबसे लोकप्रिय पयर्टन स्थलों में से एक है, लेकिन दार्जिलिंग तक जाने वाली सारी सड़कें ट्रैफिक के कारण समस्या से ग्रस्त रहती है। दार्जिलिंग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग एनएच 55 ब्रिटिश काल में बना था। आज बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण जन जीवन अस्त व्यवस्त है, रोजाना एनएच 55 में लगभग पन्द्रह हजार से ज्यादा वाहन चलते हैं, जो उसकी क्षमता से लगभग दोगुनी है। इसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और ऑफिस जाने वाले कर्मचारी घंटों तक फंसे रहते हैं, उन्हें घंटों सड़क पर समय बिताना पड़ता है।

मैं सिलीगुड़ी से दार्जलिंग तक जोड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे की मांग रखता हूं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग को जोड़ने वाली बालासंघ होते हुए एक वैक्लपिक मार्ग बन सकता है।

जिसके कारण करसन, मिरिक, सोनादार, रंगबूल, धोत्रे, सुखिया पोखरी और परखन वैली से ग्रामीण क्षेत्र को नेटवर्क को जोड़ा जा सकेगा, … (व्यवधान) मैडम, पूरा बोलने दीजिए नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा।

मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गडकरी जी का आभारी हूं, तीस्ता से होते हुए धबईपानी होते हुए लेवइंग जाने के लिए डीपीआर की मंजूरी दी है। चूंकि मेरा पूरा क्षेत्र पहाड़ी है, हर जगह सड़क कामयाब नहीं होगा इसलिए मैं यहां पर घुम से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से बिजनबाड़ी और डेल्लो से कलिम्पोंग रोप-वे कॉरीडोर बनाने की भी मांग रखता हूं।

*SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): Hon Madam Chairperson, Vanakkam. Thank you for this opportunity. It is learnt that the Union government is planning to extract Molybdenum through mining activities in mountainous areas in and around Palani of Dindigul district. The report from the Geological Survey of India (GSI) says that there is availability of this rare mineral, Molybdenum in an area of 400 sq. km. and approximately in 1 lakh acres in Dindigul district. A study was conducted by GSI in the targeted revenue villages like Neikarapatti, Karadikootam, Chatrapatti and also in the adjoining foothills of Idumban hill, Ivar Malai and Viralimalai of the Western Ghats, known for their spiritual, historic and archeological significance. Pilgrimage centres and historically important Ivar Malai will be completely destroyed in the name of mining activities of Molybdenum. Places of archeological importance will be destroyed due to this mining activity. There is a pertinent danger of these fertile agri-lands being converted as barren land. The Union government is trying to amend the important information contained in the Archaeological Excavation Report of Keezhadi having concrete information about the ancient civilization heritage of Tamils. Similar to the mining activities proposed in Arittapatti of Madurai, this Union Government is now trying to extract Molybdenum in the areas in and around Palani Hill. I urge that this anti-people mining activity of this Union Government should be immediately stopped. On one side they are organizing Conclave on Lord Muruga and on the other side they are bringing policy measures aiming to destroy the pilgrim town Palani known for the world famous Murugan Temple. We will not allow these anti-people efforts of this Union government. Similarly

* Original in Tamil

Pulaiyan tribes of the Kodaikanal hills should be included in the list of Scheduled Tribes of the Union. A memorandum in this regard has already been sent to the Union Government. I urge to fulfill this demand as well. Thank you.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री मनीष जायसवाल जी।

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : सभापति महोदय, सरकार सार्वजनिक हित में सम्पत्तियों का निर्माण करती है, लेकिन कई बार उनका उपयोग ही नहीं होता। मेरे लोक सभा क्षेत्र मेरठ के महानगर में शास्त्री नगर स्थिति एल ब्लॉक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सन 1988 में अपने कर्मचारियों के लिए 62 मकान बनाए थे, जिन्हें कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। आज ये मकान जर्जर हालत में है, छतों पर पेड़ उग गए हैं, खिड़कियां और दरवाजे चोरी हो गए हैं। एक मकान की कीमत लगभग 52 लाख रुपये है, जिससे कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपये होता है।

यहां रात के समय यहां भूतहा माहौल बन जाता है और अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इसी प्रकार डी ब्लॉक स्थित आवास विकास परिषद का कम्युनिटी सेंटर भी वर्षों से उपयोग में नहीं है और उसमें आपराधिक गतिविधियां होती रहती है।

(1325/IND/UB)

महोदया, देश भर में ऐसी अनुपयोगी सरकारी सम्पत्तियां बड़ी संख्या में हैं। मेरा सुझाव है कि इन सम्पत्तियों को या तो 'एज़ इज व्हेयर इज बेसिस' पर बेच दिया जाए या उनकी मरम्मत कराकर रेंट पर दे दिया जाए या फिर समाज सेवी संस्थाओं को सामाजिक कार्यों के लिए एलॉट कर दिया जाए। इससे ये सम्पत्तियां उपयोगी बनेंगी और सरकार को राजस्व मिलेगा। इससे अपराध भी कम होते चले जाएंगे।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री डी. एम. कथीर आनंद - उपस्थित नहीं।

श्री खगेन मुर्मु।

*SHRI KHAGEN MURMU (MALDAHA UTTAR): Honourable Chairperson Madam, I have mentioned this fact repeatedly in the House for the past six years. I would like to mention it again before you today. Due to heavy rainfall and a decrease in the depth of the river, the water level of the Ganga, Phulhar and Koshi rivers is flowing above the danger limit every year, resulting in terrible flood situation. More than 800 families have been affected by the devastating impact on the riverbank settlements in the villages of Mahanandtola and Bilaimari gram panchayats of Ratua-1 block of my Lok Sabha constituency, Khasmahal, Nasiruddintola, Gangaramtola, Kantutola, Srikantatola etc. In comparison, more than 235 families in the villages of North

* Original in Bengali

and South Bhakuria, Rashidpur of Harishchandrapur-2 block have been affected by the erosion of the Phulhar river.

Unfortunately, the villagers have been displaced and are forced to live in the open space along the government roads due to the severe erosion of the three rivers. Madam, through you, I would like to request through you to the Government to kindly provide proper relief and compensation as soon as possible and rehabilitate the flood-affected people.

In this situation, I request you to immediately take up the issue of flood-affected areas along the banks of Ganga, Phulhar and Koshi rivers with the Union Minister of Jal Shakti, Hon'ble C. R. Patil and the Government of West Bengal and make arrangements for the rehabilitation of the flood-affected people and permanent prevention of erosion.

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को सहारा इंडिया के निवेशक करोड़ों लोग, जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने छोटी-छोटी रकम सहारा इंडिया में इनवेस्ट की ताकि वे बचत के रूप में अपनी चीजों का इस्तेमाल कर सकें। उनके बच्चों की शादी, उनका पढ़ना-लिखना, घर बनाना आदि सभी विषय इससे जुड़े हुए थे। हम सभी जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा रुक गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सहारा इंडिया के पैसे को जब्त किया और अब लोगों को आशा है कि उन्हें यह पैसा मिलेगा। करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं और लाखों की संख्या में सहारा के एजेंट्स हैं जो अब भी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका पैसा दिलाएंगे। आज भी लोग उन एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसा लौटाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करे और लोगों को राहत देने का काम करे।

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन – उपस्थित नहीं।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरा लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के अंतर्गत सारण जिला के मांझी प्रखंड में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल मांझीगढ़ है, जो सरयू-घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है क्योंकि यहां 13वीं सदी के प्रतापी राजा वीर मकड़ मांझी के किले का अवशेष देखने के लिए आज भी देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की सीमा से भी लगता है।

(1330/KDS/NKL)

महोदया, ऐसे ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अति आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अटल जी के अस्थि अवशेष के कुछ अंश

रामघाट पर भी विसर्जित हुए थे। इसी कारण वह घाट और अधिक प्रसिद्ध हो गया है। रामघाट मांझी पर सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर बिहार का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल विकसित किया जा सकता है। अत: मेरा जल शक्ति मंत्री व पर्यटन मंत्री जी से यह अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उक्त रिवर फ्रंट को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

*SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Hon. Madam Chairperson, I would like to draw your attention towards the PMAY scheme which is being implemented in my state Maharashtra. Under this scheme, an exhaustive list of the beneficiaries is circulated covering not only my constituency Solapur but also entire Maharashtra and an approval for house is mentioned in it. But, in reality, they cannot get houses in the particular village or area due to non-availability of 'Gaonthan' land. But still these villagers find their names in the list of beneficiaries.

In the month of May, the Central Government had issued an order to the District collectors to acquire land for house construction under PMAY where there is no availability of Gaonthan land. But this order is not being implemented in Maharashtra and the people are still deprived of the houses. This scheme is implemented only on paper and not in reality

सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो भी घर गांव की ऐसी जमीन पर हैं, जो गैरान या गौठान की नहीं हैं, वे निकालने चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि 50 सालों से जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या उनके घरों को अतिक्रमण के अंतर्गत घोषित करके महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इस पर स्टे लाने वाली है? धन्यवाद।

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity. With your permission, I would like to draw the attention of this House to the unfortunate crash of Air India-171 aircraft that claimed the lives of over 240 passengers. I have too many emotions attached to this incident as I lost my daughter-in-law, Ms. Aparna Mahadik, who was the head of cabin crew.

The purpose is to highlight the safety and compliance measures that are needed, and the compensation that is to be provided to the families of the victims. Only some of the families have been given the compensation till now. Over 90 families are still remaining to receive compensation.

India has had a strong safety record according to the international standards, ranking 55 out of 187 in rankings by the International Civil Aviation Organization. However, safety concerns still remain. At the international level, the aircraft manufacturer, Boeing, faces scrutiny, specifically for its 737 MAX and 787 Dreamliner aircraft. A 787 Dreamliner was involved in the said crash. Domestically, there are high levels of vacancies in the Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation, Airports Authority of India, and also for the post of Air Traffic Controller. There is also a

* Original in Marathi

need to establish infrastructure and institutions for technical training of aviation professionals.

Thank you very much.

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में बटेश्वर गांव है, जो भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है। बटेश्वर गांव में ब्रह्मलाल महाराज जी का मंदिर है, जो तीर्थों के भांजे कहलाते हैं। यह 108 मंदिरों की श्रृंखला है। बटेश्वर को पर्यटन नगरी के रूप में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विकसित भी कर रही हैं। बटेश्वर में रेलवे हॉल्ट भी है, लेकिन अभी तक वह हॉल्ट रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया है। संयोग से आज रेल मंत्री जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थान बटेश्वर में रेलवे हॉल्ट के स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिससे रेलवे स्टेशन को पूर्ण सुविधाएं मिलें और देश भर के पर्यटक बटेश्वर में आएं।

महोदया, वहां यमुना नदी भी है, ब्रह्मलाल महाराज जी भी हैं और वह श्रद्धेय अटल जी का गांव भी है। श्री अश्विनी वैष्णव साहब भी यहां बैठे हैं। मेरी बात को शायद उन्होंने गौर से सुना है। अत: वहां कृपया रेलवे स्टेशन बनवा दीजिए। यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि भी होगी। धन्यवाद।

(1335/CS/VR)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : "तिलक जंजू राखा प्रभ ताका॥
कीनो बडो कलू महि साका॥"

मैडम, यह देश और दुनिया के इतिहास में इकलौता एक ऐसा साका होगा, जहाँ किसी एक धर्म के गुरु ने किसी और धर्म की रक्षा करने के लिए अपना शीश बलिदान किया। धन-धन गुरु तेग बहादुर साहिब, सिखों के 9वें गुरु ने, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर मुगलों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए जोर-जबर किया जा रहा था, तो इधर लाल किले से हुक्म हुआ और गुरु साहब चलकर दिल्ली आये और लाल किले के सामने शीशगंज साहिब में उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया। 'तिलक जंजू के राखा के वासे', इसकी वजह से उनको हिन्द की चादर का खिताब दिया गया है।

मैडम, आज मैं इस सरकार से पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने आपके तिलक जंजू की राखा करके आपके धर्म को जिन्दा रखा, हमारे सिखों ने, एसजीपीसी ने माँग रखी है कि 24 नवम्बर को मार्टर्डम डे के नाम से सम्मानित किया जाए, गुरु तेग बहादुर की महान शहादत को सम्मानित किया जाए और इस नेशनली मार्टर्डम डे की एक छुट्टी दी जाए। मैं सरकार से यह माँग रखती हूँ। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे?

मैडम, 550 साल गुरु नानक देव जी के अवतार दिवस में आपने हमारे बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जो वर्ष 2019 से आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्या वह वादा भी आप सिखों के गुरुओं के प्रति पूरा करेंगे? धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत जी।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, धन्यवाद।

मेरा विषय बीएसएनएल से संबंधित है। आज प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या 149 में बीएसएनएल की हालत के बारे में पूछा गया था, 4जी टावर के बारे में पूछा गया था। उन्होंने लिखित में जवाब दिया है। पूरे मुम्बई और खासकर महाराष्ट्र के लिए सवाल पूछा गया था। वहाँ एक भी जिले में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर्स नहीं हैं। कुछ जिलों में बीएसएनएल के टावर्स हैं, बाकी कहीं पर भी टावर नहीं हैं।

मैडम, आज यह बताने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि सरकार ने बार-बार कहा कि एमटीएनएल, बीएसएनएल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। ये बार-बार बताते रहे कि हम इतना-इतना काम कर रहे हैं। पिछले सालों में जो बजट एलोकेशन हुआ है, जो कैबिनेट एलोकेशन हुआ है, वह वर्ष 2019 में 3,29,364 करोड़ रुपये था। बाद में 1,62,147 करोड़ आ गया। An amount of Rs.72,028 crore was provided for the current year 2024-25. इतना प्रावधान होने के बावजूद ये जवाब देते हैं कि सब जगह 99 परसेंट में 4जी सर्विस शुरू हुई है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : मैडम, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अभी तो मेरी माँग ही पूरी नहीं हुई है।

माननीय सभापति : आप अपनी माँग कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : 5 मिनट तक अनुराग ठाकुर जी बोलते रहे।

माननीय सभापति : आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी सारे माननीय सदस्य बोल पाएंगे।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : मैडम, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। इतना प्रावधान करने के बाद भी आज टावर्स नहीं हैं। आज भी एमटीएनएल, बीएसएनएल की सर्विस नहीं है। अब मैं सीएजी की रिपोर्ट बताता हूँ। उसमें से चार वाक्य मुझे पढ़ने दीजिएगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं इसे पढ़ देता हूँ।

Madam, please allow me to refer to the C&AG Report. This should come on record. The C&AG in its Report no.1 of 2025 has given certain observations. It says that non-adherence to the contractual terms and conditions, lack of due diligence, non-billing, and deficient planning on the part of BSNL and ITI, PSUs under DoT, have resulted in a loss of Rs.1,944.92 crore. Non-billing to M/s. Reliance Jio Infocomm Ltd (RJIL) is a very serious observation of the C&AG. That is why I demand that the Government should take a serious note of it.....*(Interruptions)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री बैन्नी बेहनन जी।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो रहा है। आप तो हमें बीएसएनएल की सर्विस देते हैं। क्या वह मुम्बई, दिल्ली में

चलता है?… (व्यवधान) What is the fate of employees who are working in BSNL. The shares have increased by three per cent now. In view of this, I would request the Government to conduct an urgent inquiry into the matter. Thank you, Madam.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया है।… (व्यवधान) यह विषय महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है।… (व्यवधान) वहाँ पर भी छठ का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग आज भी भोजपुरी भाषा भारत में बोलते हैं। सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरीशस आदि में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी मॉरीशस में सेकेंड लैंग्वेज है। यह नेपाल में चलती है, भोजपुरी में ओथ ली जाती है। आज राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत है। यह भाषा आज भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस सदन में कई बार आश्वासन भी आ चुका है। आज भारत और भारत से बाहर रहने वाले करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मेरी माँग है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

(1340/RV/SNT)

महोदया, इस सदन में कई बार इसके लिए आश्वासन भी दिए गए हैं। आज भारत में और भारत के बाहर रहने वाले करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। उस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि सरकार उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I wish to bring the attention of the august House to a matter of urgent public interest regarding the need for extending the Kochi metro rail network to Cochin International Airport and to Angamaly.

Currently, Kochi Metro operates within the city limits and does not provide direct connectivity to the international airport. The Cochin International Airport is one of the busiest airports in India, serving millions of passengers annually, including a large number of international travellers and NRIs from Kerala. The proposed metro extension from Aluva to Angamaly via CIAL will not only enhance last-mile connectivity for air travellers but also decongest existing roads and reduce traffic bottlenecks on the NH-544 corridor. Angamaly is also a strategic junction on the railway network, and linking it with the metro system would provide multi-modal integration, benefiting both residents and visitors. Recently, the Railway Minister and the Railway Board in-principle

agreed to have a railway station near Nedumbassery airport and the work will start soon. I thank the hon. Minister for this.

I urge the Government of India and the Ministry of Housing and Urban Affairs to take immediate steps to conduct a feasibility study and initiate the process for extending Kochi Metro to Cochin International Airport via Angamaly.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Vanakkam, Chairperson Madam.

With a voice that echoes the pride of Tamil Nadu and the conscience of this nation, I rise to humbly urge the Government to declare Thirukkural, authored by the sage Thiruvalluvar as India's national treasure book. This is not a regional demand. It is a national call for moral recognition. Thirukkural is not a religious scripture, but a timeless ethical masterpiece – 1,330 couplets that teach *aram*, *porul*, and *inbam*. Its verses speak of non-violence, justice, compassion, equality, and duty. In this House, the Prime Minister has quoted from Thirukkural; the Finance Minister has quoted from Thirukkural; and many others have also displayed the verses.

This is not a new demand. The Tamil Nadu Assembly has already passed resolutions to announce Thirukkural as a national treasure book. Why is there a delay? In these challenging times, when public life yearns for ethical grounding, what better beacon than Thirukkural? It transcends region, religion, and language. It unites where politics divides. By declaring Thirukkural as a national treasure book, we honour not just Tamil heritage but India's commitment to dharma, dignity, and moral clarity.

I appeal to the hon. Minister and this Government to declare Thirukkural as a national treasure book.

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, हमारे यहां शिक्षा के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 है। इसके साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21(ए) के अन्तर्गत देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक एक किलोमीटर तक बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके, इसके लिए विद्यालय खोले गए। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से विद्यालय खोले गए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए संविधान में अनुच्छेद 45 में इसकी व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन, आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कमजोर होगी और

वे नहीं पढ़ पाएंगे। साथ-साथ वहां कार्यरत जो रसोइए हैं, उनका भी इससे रोजगार छिनेगा, 'शिक्षा मित्र' का रोजगार छिनेगा।

महोदया, माननीय नरेश उत्तम जी, माननीय धर्मेन्द्र यादव जी के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि केन्द्र की सरकार यह सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में वे विद्यालय बंद न किए जाएं। धन्यवाद।

(1345/AK/MY)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Madam, whenever an MSME seeks a loan to buy a machinery, they are compelled to buy a machinery breakdown insurance policy. But when the machinery breaks down and they want to repair the machinery, the insurance company denies and delays the claim saying that they must pay for the repair, and only then come and claim it. This actually impedes business, and the bank will not finance the repairing and the insurance company will also not give money to repair the machinery. The small entrepreneur is hamstrung because of a broken machinery that he cannot repair.

There is nothing in the insurance policy which states that they must pay for the repair and then claim it. This is a breach of contract and it makes doing business very difficult. While this Government talks about 'Make in India', they must remove these little niggles which are practically there in the day-to-day life so that businesses can thrive.

The Finance Ministry must instruct the insurance companies to settle claims even before the payment is made and only when the invoice is raised. Thank you very much, Madam.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदया, मैं पुन: आपका ध्यान पटना शहर की तरफ दिलाऊंगा। वर्ष 2019 के बाद पटना शहर फिर से जलमग्न हो गया। पूरा पटना शहर पानी में डूब गया। आज राजेन्द्र नगर से लेकर पूरे एरिया में पानी भरा है। वहां हर घर में पानी घुस गया है। नेता कुंभकरण की नींद की तरह सोए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं।

महोदया, अभी आरा के शाहपुर क्षेत्र स्थित जवईनिया गाँव सहित पांच गांव गंगा नदी में कट गए। वहां लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे बिंद, मल्लाह, केवट, नोनिया, ईबीसी, एससी/एसटी के पूरे के पूरे गांव टूट गए। गंगा नदी में काफी कटाव हो रहा है। वहां के ठेकेदारों ने गलत तरीके से बालू की खुदाई की है। वहां जो 9 करोड़ रुपये दिए गए थे, उसको भी इन माफियाओं की मिलीभगत से लूट लिया गया।

महोदया, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़ा माफिया रिशु सिंह को दुबई भगा दिया। इसने काफी पैसा लूटा है। पटना को लूटने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार के मंत्री और इस माफिया की है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप इसको देखें। मैं नवगछिया, कुरसेला, रूपौली, बायसी और अमौर का भी विषय रखना चाहता हूं।... (व्यवधान)

महोदया, देखिए, मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आपका समय एक मिनट से ज्यादा हो गया। अगर आप सभी सहयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल पाएंगे।

... (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : माननीय सभापति जी, मैं देश का एक बहुत ही सीरियस इश्यू सदन के सामने लाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं।

सभापति जी, इस देश में 35 ईयर्स के बिलो जो पॉपुलेशन है, वह 65 परसेंट है। आज इस 65 परसेंट यंग पॉपुलेशन के सामने एक बड़ी समस्या है। यह समस्या ड्रग्स एंड एल्कोहल एडिक्शन की है। हमारी जो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक पूरे देश में 1.48 करोड़ यूथ हैं, जो अभी ड्रग्स एंड एल्कोहल एडिक्शन के शिकार हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए वह कुछ स्ट्रॉन्ग मैकैनिज्म लाए।... (व्यवधान)

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : मैडम, पंजाब की राज्य सरकार वहां के किसानों की जमीन छीनना चाहती है। पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 50 हजार एकड़ जमीन को किसानों से छीना जा रहा है। आज पूरे पंजाब में वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो तीन काले कानून आए और अब राज्य सरकार द्वारा किसानों को डराया जा रहा है। राज्य सरकार ने उनसे कह दिया है कि अगर आप जमीन नहीं देंगे तो इसके बाद आपकी जमीन का कभी सीएलयू नहीं होगा। एक एकड़ जमीन लेकर उनको 1000 गज का रिहायशी प्लॉट और 200 गज का कमर्शियल प्लॉट दिया जा रहा है। किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि हमारी मर्जी के बिना जमीन नहीं छीनी जाए। डॉ. मनमोहन सिंह जी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे। उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करे और किसान की जमीन छीनने न दें।

(1350/GG/SRG)

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Thank you, Honourable Chairperson Sir, for letting me speak. The people of West Bengal have been repeatedly attacked and deprived. Now the attack on the Bengali language has begun.

---

* Original in Bengali

That's why I say Rabindranath is in everyone's heart, Nazrul in their consciousness. Which effectively means that Bengal belongs to Rabindranath, Kazi Nazrul Islam, Matangini, Vidyasagar, and Rammohan. I strongly protest against how Bengalis are being oppressed in BJP-ruled states and are being labelled as Bangladeshi, and the Bengali language is being terrorised. We say "Look at the country's great unity among different languages, different opinions, different clothes, and diversity". People of all religions should live together, this is the nature of India. Then why this hypocrisy? Why is there a brutal attack on Bengalis? Today, all of a sudden people are shouting that the Rohingyas are entering India. So, does the person who has himself taken the responsibility of guarding India not know anything? When the Mumbai attack happened, Modiji told the then Prime Minister Manmohan Singh-the border is yours, the BSF is yours, the coastal security is yours, then how did the infiltrators come? Why shouldn't this question apply to Modi-ji today? Bengal wants to know, India wants to know. BJP is poking a sleeping volcano.

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Madam Chairperson, thank you. Through you, I would like to draw the Central Government's attention towards an important issue. Online gaming has become such a vicious trap which is ruining the common households., I want to share a real life incident with you. One person named Laxman Jadhav, a JCB driver, living at Bavi Village, Tehsil Dharashiv in my constituency, killed his wife and daughter aged only 2 by poisoning them. Later, he also committed suicide due to online gaming and betting habit.

I am sure the online Junglee Rummy App is the only reason behind his suicide. A large number of these village youths are falling prey to the online betting App and they are ruining their lives. This is a real menace but, the state and Central Governments are blaming each other. So, I want to urge upon the Central Government to ban these online betting and gaming Apps immediately.

Thank you.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : सभापति महोदया, पूरे देश में किसानों का खाद के नाम पर शोषण किया जा रहा है और सरकार कान में तेल डाल कर बैठी है। किसान, जो अपनी फसल के लिए डाई की खाद लेता है, डाई की शॉर्टेज है, उसके साथ हमारी

* Original in Marathi

कोऑपरेटिव सोसाइटी, आईपीएल, कृभको, इफ्को दो मानक पोटाश दे रही है, जिसमें मात्र साढ़े 14 पर्सेंट पोटाश है।

किसान को 1500 रुपये में 60 पर्सेंट पोटाश का 50 किलो का बैग मिलता था। अब साढ़े सात सौ रुपये में साढ़े 14 पर्सेंट का बैग मिलता है। इस प्रकार 60 पर्सेंट का पोटाश लेने के लिए किसान को तीन हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, डबल पैसा देना पड़ता है और दुख इस बात का है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों से वह खाद खरीद कर, जो कारखाने की राख ले कर, राख में प्राकृतिक रूप से पोटाश होता है, उस राख को बैग में बंद कर बेचती है और मेरे जिले में पांच कारखाने हैं। वे कोऑपरेटिव के, इफ्को के, कृभको के, आईपील के माध्यम से बेच रहे हैं। करोड-अरबों रुपया कमाया है, किसान लुट रहा है। अकेले राजस्थान में, 20 हज़ार टन की बजाय 60 हज़ार टन पोटाश बेच दिया गया है।

मान्यवर, किसानों का बेहद शोषण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अधोमानक पोटाश बेच कर के पैसा कमाने वालों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए।... (व्यवधान)

(1355/YSH/SM)

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स को वहां के महानगर पालिका में शामिल कर रही है जैसे पुणे जिले में पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है। देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड पिंपरी-चिंचवाड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लगा हुआ है।

अत: मेरी मांग है कि देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड को पिंपरी-चिंचवाड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड में शामिल किया जाए। इसके अलावा केन्द्र सरकार उसको समय पर वित्तीय सहायता नहीं देती है, जिससे बहुत समस्याएं रहती हैं।

अत: मैं फिर से मांग करता हूँ कि देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड को पिंपरी-चिंचवाड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया जाए।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, यहां पर रेल मंत्री जी उपस्थित हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि अगर हम मुम्बई शहर में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में रेल का इस्तेमाल होता है। मुम्बई के लगभग 70 लाख लोग रेल से ट्रेवल करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहती हूँ कि जनवरी, 2015 से लेकर मई, 2025 तक, 10 सालों में रेलवे की दुर्घटनाओं में लगभग 26,547 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से लगभग 14,175 लोगों की मौत ट्रैक को पार करते हुए हुई है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह भी बताना चाहती हूँ कि उनमें से सिर्फ 1,408 मृतक परिवार को 103 करोड़ रुपये की मदद मिली है तथा घायल लोगों को 14 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली है।

सभापति महोदया, मुझे आपके माध्यम से यह भी बताना है कि मुंब्रा में हुई दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए और उनमें से पांच लोगों की मौत भी हो गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वे अभी कवच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यह सुरक्षा कवच किसके लिए है?

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर के अंतर्गत बरसठी रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहाँ से बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर व प्रयागराज और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं। लेकिन स्टेशन पर बैठने की सुविधा, पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यदि यहाँ आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं तो यात्रियों को राहत मिलेगी और उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा।

इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के निर्णय का विरोध करती हूँ। आज शिक्षा के अधिकार और संविधान के आर्टिकल 21ए का सीधा गला घोंटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और ढाई लाख शिक्षकों-कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।

मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले।

श्री मनोज तिग्गा (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदया, पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में जो चाय उद्योग हैं, उनकी अवस्था दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसलिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वारस, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर में जो चाय बागान हैं, वे वाम मोर्चा के 34 साल तथा टीएमसी के 14 साल की उदासीनता के कारण एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं और वहां के जो श्रमिक हैं, वे पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि चाय उद्योग में ज्यादातर आदिवासी और गोरखा हैं। वे चाय बागान बंद होने के कारण वहां से पलायन कर रहे हैं। उन्हें काम करने के बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलता है। यहां तक कि उनका पीएफ का पैसा काटा जाता है, लेकिन मालिक पक्ष पीएफ का पैसा जमा नहीं करते हैं और वे गबन कर जाते हैं। उस जगह को शिक्षा, पीने का पानी, आवास, जमीन का मालिकाना अधिकार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

यहां तक कि वहां पर बागान बंद होने के कारण तथा समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण मानव तस्करी जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूँ और केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप कर चाय बागानों की हालत सुधारने के लिए आग्रह करता हूँ।

(1400/MK/GM)

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने क्षेत्र की एचसीएल मलाजखंड परियोजना का एक विशेष मुद्दा सदन में रखना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत छिंदी टोला, सुजी, बोरखेडा और उसके आस-पास के गाँव में गंभीर और चिंताजनक समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। एचसीएल की परियोजना से निकलने वाला जहरीले रसायनिक तत्व के कारण क्षेत्र की उपजाऊ जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। जल स्रोत प्रदूषित और विषैले हो चुके हैं। प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य जीवन और पशुधन पर पड़ रहा है। कृषि गतिविधियां भी वहां पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। उसके कारण स्थानीय जनता का जन-जीवन अत्यंत कठिन हो चुका है। यहां तक कि वहां पर बोरवेल तथा पानी की बहुत असुविधा है। उसमें से जहरीला पानी निकल रहा है। इसके अलावा कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सीएसआर की योजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जो भी काम हो रहा है, वह बहुत प्रभावहीन है। उसका विकास कार्य और राहत राशि केवल कागजों पर है। जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वर्षों से किए गए रोजगार और मुआवजे के वायदे भी पूरी तरह से नहीं निभाए गए हैं, जिसके कारण प्रभावित जनता में गहरा असंतोष है।

मैं आपके माध्यम से संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं। ... (व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदया, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों को अंधाधुंध बंद किया जा रहा है। उससे प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों की शिक्षा के साथ-साथ हजारों परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है। इससे करीब साढ़े तीन लाख बच्चे-बच्चियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश सरकार प्रदेश के लाखों गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चे-बच्चियों का भविष्य अंधेरे में डालने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब पांच हजार विद्यालय बंद हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है। उससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है। यह नीति शिक्षा के अधिकार ... (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है। ... (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने लक्षद्वीप रिमोट एरिया में वर्ष 2021 में अंडर आर्टिकल - 16 (4) में डोमिसाइल लॉ बनाया और 40 साल की उम्र तक एज रिलेक्सेशन दिया। मैं मांग करूंगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी यह कानून लागू किया जाए, क्योंकि अंडमान-निकोबार रिमोट बैकवर्ड एरिया में आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान के माध्यम से आर्टिकल - 14 के माध्यम से लक्षद्वीप की तरह 40 साल की उम्र तक एज रिलेक्सेशन दें और यूनियन टेरेटरी के नाते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी डोमिसाइल लॉ लागू करे। जय हिन्द।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदया । मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान औरंगाबाद जिले के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, औरंगाबाद जिले में कई पर्यटक स्थल हैं। देव सूर्य मंदिर, जहां लाखों छठ व्रती प्रतिवर्ष आते हैं। उमगा पहाड़, देवकुंड और गजनाथ धाम जैसे अनेक पर्यटक स्थल हैं, जहां लाखों श्रद्धालू आरंगाबाद जिले में आते हैं। वहां अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि एक भी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर नहीं है, पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अति आवश्यक किया जाए। इसके साथ-साथ रफीगंज स्टेशन पर पुरुषोत्तम ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था की जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1405/GTJ/SK)

*SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon'ble Madam Chairperson, I want to draw your kind attention towards an important issue. Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned as the king and his coronation ceremony took place on June 6,1674 at Raigad Fort. Then, he constituted the Ashtapradhan Mandal, a council of eight ministers, like we have our cabinet today, to assist in the administration of Maratha empire. He established this democratic setup when it was not a common practice. He emphasized on the fundamental values of Liberty, Equality and Justice and then this ideological legacy was carried forward by many social reformers like Mahatma Jyotiba Phule, Rajarshi Shahu Maharaj and Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar throughout Maharashtra and entire country. So, I would like to request you to kindly convene a one-day Special Session at Raigad Fort to commemorate the coronation ceremony.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Madam, on 25th July, 2025, two nuns from Kerala, sister Preethi Mary and sister Vandana Francis, were wrongfully arrested at Chhattisgarh's Durg Railway Station. These nuns have been doing exemplary work in terms of education and in terms of healthcare. But the Bajrang Dal workers have made pressure on the Government and jailed them for the last six days… (*Interruptions*). Since false accusations have been made, cases have wrongfully made on the basis of human trafficking… (*Interruptions*) and also on the basis of anti-conversion…. (*Interruptions*) Madam, you should understand that this is a political case…. (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं, उन सभी सदस्यों को कल बोलने का मौका दिया जाएगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

---

* Original in Marathi

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए

1407 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी है, वे मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिश: या व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

Re: Need to develop Metro Rail connectivity in Siliguri and adjoining areas in West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Siliguri is the second largest urban centre in West Bengal, after Kolkata. More than 10,00,000 residents live in Siliguri and surrounding areas. Siliguri is a transit hub that connects to tourist destinations in Darjeeling, Sikkim, Dooars, and North East states. It is also called as "Gateway to Northeast India" and is a major trading centre directly connected to international borders with Bhutan, Nepal, and Bangladesh. Siliguri connects the Eastern Himalaya regions including states of Bihar, Sikkim, Assam and rest of West Bengal. However, lack of urban transportation infrastructure has hampered Siliguri's growth potential. Because of poor public transportation system, roads have become extremely congested. People have to suffer jam of over 3-4 hours in their daily commute. Sir, I am therefore requesting the Ministry of Railways and Ministry of Housing and Urban Affairs to consider the development of Metro Rail connectivity in Siliguri and adjoining areas. Metro rail will serve over 50,000 daily commuters, reduce traffic, and boost tourism revenue. It will also connect major transit points like the Bagdogra Airport and New Jalpaiguri Railways stations. Introducing Metro Services will propel Siliguri, Darjeeling hills, and Terai region into an engine of growth. It will also address the urban transportation deficiency, boost local economy and tourism sector.

(ends)

Re: Non-payment of salaries to employees of NEPA Limited, Nepanagar, Madhya Pradesh

श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) : मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा मे स्थित ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित नेपालिमिटेड, नेपानगर जिसे "कागज की काशी" के उपमा से अलंकृत किया गया है और यह कारखाना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और स्वतंत्र भारत का पहला अखबारी कागज का कारखाना है, जो भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस मिल के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा कुल 469 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देकर इस मिल का नवीनीकरण किया गया था। मेरे संसदीय क्षेत्र में यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिस पर लगभग 140 गाँव देहातों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं और उन लोगों के रोजगार का एक मात्र साधन भी यही मिल है। यहाँ के कर्मचारियों को विगत एक वर्ष से वेतन भुगतान तक नही किया जा सका है। मैं भारी उद्योग मंत्री जी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि यदि आप इस मिल को बेचना या किराये पर देना चाहते हैं तो उसके पूर्व इस मिल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न होने पाये व उनकी लंबित देनदारियों 2007 व 2017 के लंबित वेतन पुनः निर्धारण को तत्काल लागू किया जाए। जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं उन्हे स्वैछिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया जाए और कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करें। जिससे यह मिल सतत चलती रहे व इस क्षेत्र की स्थानीय जनता को रोजगार मिलता रहे। मुझे विश्वास है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो मिल के कर्मचारियों को ध्यान मे रखते हुए और उनके हित मे लेगी। (इति)

Re: Construction of Saryu River Front in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरे लोकसभा महाराजगंज, बिहार अंतर्गत सारण जिला के माँझी प्रखंड में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल माँझी गढ़ हैं। जो सरयू(घाघरा) नदी के किनारे अवस्थित हैं। यह गढ़ बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। क्योकि यहाँ 13वीं सदी के प्रतापी राजा वीर मकर माँझी के किले का अवशेष देखने के लिए देश- विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की सीमा से भी लगता है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अति आवश्यकता हैं। इसीलिए माँझी गढ़ से अटल रामघाट, माँझी तक सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर बिहार का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल विकसित किया जा सकता हैं। अतः जलशक्ति मंत्री से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत माँझी गढ़ से अटल रामघाट माँझी तक सरयू नदी के किनारे रिवरफ्रंट बनवाया जाये ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

(इति)

Re: Need to give recognition to sports certificates given to students by Navodaya Vidyalaya Samiti at par with those of State/National level

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण छात्रहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देशभर में संचालित पी.एम. श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों के हजारों विद्यार्थी संकुल, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं (School Games Federation of India) स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। किन्तु, उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार की खेल कोटा आधारित नौकरियों में उस स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रदत्त खेल प्रमाणपत्रों को प्रायः राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष मान्यता नहीं दी जाती, जिससे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित हो जाते हैं। जबकि राजस्थान एवं गुजरात जैसे राज्यों ने इन प्रमाणपत्रों को राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान की है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्रों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष मान्यता दी जाए। राज्य एवं केंद्र सरकारों की खेल कोटा आधारित नौकरियों में नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान किया जाए। इस विषय में एक राष्ट्रव्यापी नीति या मार्गदर्शिका जारी की जाए, जिससे समरूपता सुनिश्चित हो सके। यह पहल प्रधानमंत्री जी के "खेलो इंडिया" अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगी और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी।

(इति)

Re: Establishment of Cow Sanctuaries

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय—गोवंश संरक्षण—की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ा है। देश के लगभग 8 करोड़ परिवार आज भी पशुपालन पर निर्भर हैं। गोवंश हमारी कृषि प्रणाली, ग्रामीण आजीविका और पोषण का प्रमुख आधार है। वर्तमान में निराश्रित एवं अनुपयोगी माने जाने वाले गोवंश की संख्या बढ़ रही है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मंडल स्तर पर गौ संरक्षण केंद्र (Cow Sanctuary) की स्थापना की जाए। इन केंद्रों से न केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय मिलेगा, बल्कि स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, गोबर-गोमूत्र आधारित जैविक खेती को बढ़ावा, और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इनके संचालन हेतु भूमि चिन्हांकन, राज्य सरकारों का सहयोग, केंद्र से वित्तीय सहायता, पशु चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जन-जागरूकता अभियान आवश्यक होंगे। साथ ही इन्हें प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे पशुधन और ग्रामीण उद्यमिता को बल मिलेगा। यह पहल न केवल गोवंश संरक्षण को सशक्त बनाएगी, बल्कि गाँवों में समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना भी सुनिश्चित करेगी।

(इति)

Re: Need to ensure efficient implementation of MGNERGS in Odisha

SHRI BALABHADRA MAJHI (NABARANGPUR): It is observed that fund is not available consistently in the MGNREGS account with the Government of Odisha. As a result, poor daily wage labourers are deprived of the benefits of the scheme. The objective of assured word of 100/300 days per year per family is lost and migration not come down in a poor area like mine. Inconsistent fund in this account is also encouraging misutilisation of MGNREGS fund by a few Contractors and Officers with vested interests. It is learnt that Government of Odisha proposed to create a corpus fund wherein money will always be available in MGNREGS account for which work in MGNREGS will not suffer. However, the same has not agreed to by the Centre for some technical issues. In the best interest of poor daily wage labourers and for successful implementation of the scheme, it is requested to come out with a solution at the earliest.

(ends)

Re: Need for stringent action to curb illegal mining and construction activities in Raiwala-Bhogpur region of Haridwar district, Uttarakhand

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I wish to raise a serious concern regarding the rampant illegal mining and construction activities taking place in the Raiwala–Bhogpur region of Haridwar district, Uttarakhand. The Bhogpur area alone houses 53 of the total 121 stone crushers in Haridwar. As per recent reports, 22 of these units have either had their permits suspended or their leases have expired. Shockingly, 10 stone crushers were found operating within 1 km of the Ganga river in the Raiwala to Bhogpur stretch according to CPCB—violating the Uttarakhand Stone Crusher Policy, 2021, which mandates a minimum 1 km distance from the river. Moreover, mined pits of minor minerals have been reported within the flood zone, suggesting unauthorized extraction and posing grave risks to the Ganga ecosystem. I urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to take strict and immediate action to stop these violations and protect the river.

(ends)

Re: Need for revival of canals and sub-canals in Jajpur district, Odisha for irrigation and navigation purpose

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): The Jajpur district in whole is represented as Jajpur Parliamentary Constituency in Odisha. There are several rivers like Brahmani, Baitarani, Kelua, Birupa and many small rivers exist here. The district is endowed with rich mineral resources and vibrant cultural heritage points. In past there was maritime legacy and cultural link with Java, Sumatra, Borneo etc. through these rivers for trade by country boats. During British period many canals and sub-canals were constructed connecting these rivers including Major Jenapur to Choudwer canal connecting river Brahmani and Mahanadi. The District is also an agriculture based district. It is observed that most of these canals are destroyed and buried. I do propose Hon'ble Minister of Shipping, Inland Waterways and Jal Shakti to revive these canals for irrigation and navigation purpose in alignment with the objectives of National Waterways (NW) including National Waterways 22 and connect these rivers.

(ends)

Re: Need to provide rail connectivity to Medaram village in Mulugu district, Telangana and interlink it with nearest railway junctions

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): I wish to raise the following matter of urgent public importance that, the Sammakka Saralamma Jathara, held biennially in Medaram village, Mulugu district, Telangana, is Asia's largest tribal congregation, attracting over 1 crore pilgrims, predominantly from Telangana, Chhattisgarh, Maharashtra, and Odisha. Despite its national significance and cultural prominence, Medaram lacks direct railway connectivity, compelling lakhs of tribal devotees to rely on overcrowded and costly road transport, often leading to severe logistical and safety challenges. A dedicated railway line connecting Medaram to the nearest railway junction such as Warangal, Sirpur-Khagaznagar, or Manuguru would provide safe, affordable access to tribal populations, reduce congestion on state transport networks, and boost eco-tourism and regional development in this forested belt, which includes attractions like Bogatha Waterfalls and Ramappa Temple. I urge the Ministry of Railways to undertake a feasible study for this railway line and initiate planning under pilgrimage connectivity, socially relevant infrastructure, or the PM GatiShakti framework, with convergence from the Ministry of Tribal Affairs and Tourism. Such a step will honour tribal traditions, ensure equitable access, and reaffirm national commitment to inclusive development. (ends)

Re: Need to develop a comprehensive policy framework to put in place the modern tram system in Bengaluru and other cities

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): In line with the Government's National Urban Transport Policy vision, which emphasizes 'moving people' rather than 'moving vehicles' and seeks to provide sustainable mobility and accessibility to all citizens, I suggest the re-initiation of a modern tram system in our cities, especially Bengaluru. With over 1.2 crore population, Bengaluru faces peak-hour average traffic speeds of 12–15 kmph, inadequate last-mile connectivity from Metro stations, rising vehicular emissions and unaffordable transport options for short to medium distances. Despite major investments in Metro rail and bus systems, there remains a critical infrastructure gap for travel within 2–15 km ranges, a gap that can be addressed by surface tram systems. Modern tram systems offer a viable and proven solution that lies between Metro and bus services. These systems can integrate seamlessly with existing infrastructure by sharing road space with other vehicles while maintaining dedicated corridors where necessary, reducing capital costs drastically and requiring significantly lower civil infrastructure. Their implementation timeline is also quicker allowing cities like Bengaluru to respond rapidly to transport crises. I hereby request the Government to support bringing back a modern tram system in our cities, especially Bengaluru, and develop a comprehensive policy framework for urban tram systems across India.

(ends)

Re: Need for utilization of vacant land near Gadwal Railway Station in Telangana by establishing a Skill Development centre for unemployed youth

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice that Gadwal Railway Station, located in the heart of Gadwal town, Jogulamba Gadwal District. Telangana, is surrounded by approximately 150 acres of open and unused land. This land, which was generously donated by Maharani Adi Laxmi Devamma of the Gadwal Samsthan to South Central Railways, remains unutilized. In this connection, it is pertinent to mention that the first train service from Secunderabad to Gadwal commenced on February 1, 1916, during the Nizam Era, making Gadwal one of the oldest, busiest, and most recognized railway junctions in the region. Maharani Adi Laxmi Devamma's intention behind donating this land was not only to provide railway facilities but also to create employment opportunities for the rural youth, particularly in auxiliary roles related to the railways. In the light of the Government of India's various initiatives aimed at empowering unemployed youth, I propose the establishment of a support or training center on this open land. This center could focus on skill development, employment generation, and the promotion of rural artisans, aligning with the Hon'ble Prime Minister's vision of creating opportunities for all Hence. I earnestly request the intervention of the Hon'ble Minister of Railways, to kindly consider utilizing this open land at Gadwal Railway Station in my Parliamentary Constituency, Mahbubnagar for the benefit of local youth and artisans, creating job opportunities that will contribute significantly to the socio-economic development of the region. (ends)

Re: Need to take comprehensive measures for safety and security of Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) in Amritsar, Punjab

SHRI CHARANJIT SINGH CHANNI (JALANDHAR): I wish to raise a matter of urgent public importance concerning the repeated bomb threats received by Sri Harmandir Sahib (Golden Temple), Amritsar—a site of immense spiritual significance for crores across the globe. In the past one week, over seven bomb threat emails—some referencing RDX explosives—have been sent targeting the holy shrine. Despite the detention of one suspect, the threats continue unabated. This raises serious concerns about the efficacy of the ongoing investigation and the possible existence of a broader conspiracy. This issue is far beyond local law and order. It is a direct attack on our national security, religious harmony, and public faith. Through this House, I urge the Union Government to deploy central agencies like the NIA and cybercrime units to thoroughly investigate the source of these threats; ensure coordinated 24x7 security service between Punjab Police and central forces; issue a formal assurance in the House on the protection of all religious sites from such threats; and frame a national strategy for digital surveillance and protection of religious sites. Sri Harmandir Sahib is a symbol of India’s unity and peace. Its protection must be a national priority. (ends)

Re: Need to ensure availability of WHO-standard vaccines and medically guided protocols to address rising rabies deaths due to stray dog menace in Kerala and other parts of country

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I wish to draw the attention of the Hon'ble House to the alarming rise in rabies deaths and stray dog attacks, particularly in Kerala. Between February and June 2025, several tragic fatalities occurred—including children who died despite receiving anti-rabies vaccines, mainly due to high-risk bite sites and delayed treatment. In one case, a fatal bite from a previously vaccinated pet was ignored. Dog bite cases in Kerala rose from 1.35 lakh in 2017 to over 3.16 lakh in 2024, with rabies deaths increasing from 8 to 26. From 2020 to 2024, the state reported over 1.29 million dog bites and 94 rabies deaths. There is growing concern over substandard vaccines, weak cold chain systems, and slow Animal Birth Control (ABC) program execution. Humane handling of aggressive or rabid dogs also lacks clarity. I urge the Government to include PrEP vaccination in national health programs, ensure availability of WHO-standard rabies vaccines with strict quality control, and enforce timely and effective implementation of the ABC programme. A national expert panel must be constituted to review current policy gaps and develop humane, medically guided protocols to deal with dangerous strays. This issue demands immediate national-level intervention.

(ends)

Re: Farmers' suicides in Amravati and Yavatmal districts in Maharashtra

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ संभाग में, विशेषकर अमरावती और यवतमाल जिलों में, वर्ष 2019 से 2025 तक किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की जानकारी है; (b) क्या यह तथ्य सही है कि उक्त अवधि में विदर्भ संभाग में कुल 7334 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में ही 527 किसानों ने आत्महत्या की है; (c) क्या सरकार के पास यह आंकड़ा उपलब्ध है कि अमरावती जिले में 1910 तथा यवतमाल जिले में 2002 किसानों ने आत्महत्या की है; (d) आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या सहायता या मुआवजा प्रदान किया गया है; (e) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित विदर्भ में किसानों की कर्जमाफी योजना कब तक पूर्ण की जाएगी तथा अब तक कितने किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है; और (f) क्या केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई विशेष योजना या नीति प्रस्तावित की गई है? (इति)

Re: Need for restoration of trains originating from/passing through Ambala Parliamentary Constituency

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): I request the honourable Minister of Railways to restart the passenger trains stopped during Covid times which were starting and passing through Ambala Parliamentary Constituency in the interest of the daily wagers, public and private sector employees and the public at large. This act of restarting the passenger trains will generate employment, reduce the economic burden on the passengers, save time and reduce pollution as well.

(ends)

Re: Need to withdraw the mandatory Face Recognition System applied to Anganwadi Workers for Take Home Rations and to address the problems being faced by them

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I rise to bring attention to the plight of Anganwadi workers and helpers who are facing immense challenges due to the mandatory Face Recognition System (FRS) for Take Home Rations (THR). This system is not only causing harassment to workers but also denying benefits to malnourished children and women. The Government must understand that Anganwadi workers are the backbone of our nutrition programs, and their hard work and dedication deserve recognition and support. Instead of providing them with the necessary infrastructure and resources, the government is burdening them with unrealistic expectations and technological demands. I urge the Government to immediately stop the mandatory FRS authentication and provide Anganwadi workers with the necessary support and resources to deliver their services effectively. We must prioritize the well-being of our children and women, and ensure that they receive the nutrition they deserve. The Government must also address the long-pending demands of Anganwadi workers, including regularization, minimum wages, and social security benefits."

(ends)

Re: Need to re-employ the contract para-medical employees who rendered their services in Railway Hospitals during Covid period

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : भारत सरकार के रेलवे अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिकल संविदा कर्मचारियों ने 2020 से 2022 तक कोरोना महामारी के दौरान निरंतर सेवा दी। जब देश संकट में था, लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे और हर ओर मृत्यु का भय था, तब इन स्वास्थ्य कर्मियों ने रेलकर्मियों और आम नागरिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया। इन कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत की, स्वयं बीमार पड़े, फिर भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। दुर्भाग्यवश, रेलवे प्रशासन ने बिना किसी सूचना या टर्मिनेशन लेटर दिए, इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। पूरे भारत में लगभग 2500 से 3000 कोरोना योद्धाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। ये कर्मचारी रेलवे की निर्धारित चयन प्रक्रियाओं को पार कर सेवा में आए थे और महामारी के दौरान अपना 100 प्रतिशत योगदान दिया था। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन कर्मचारियों को पुनः रेलवे अस्पतालों में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए ताकि उनका न्याय हो सके और देश को फिर से उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to provide stoppage to Pallavan Express (No. 12606) and Vaigai Express (No. 12636) at Ulundurpettai railway station in Tamil Nadu

SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): 15 express trains pass through Ulundurpettai daily, of which Kollam Express stops only at night. No other trains stop at Ulundurpettai railway station. I hereby request that steps be taken to provide stoppage to train number 12606 Pallavan Express and train number 12636 Vaigai Express at Ulundurpettai railway station in Tamil Nadu. Also, steps should be taken to improve Ulundurpettai railway station by including Ulundurpettai railway station in the Amrit Bharat Station Scheme (ABSS).

(ends)

Re: Need to declare 'Thirukkural' the book authored by Tamil poet Thiruvalluvar as National Treasure Book of the country

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): With a voice that echoes the pride of Tamil Nadu and the conscience of this nation, I rise to humbly urge the Government to declare "Thirukkural", authored by the sage Tamil Thiruvalluvar, as "India's National Treasure Book". This is not a regional demand. It is a national call for moral recognition. Thirukkural is not a religious scripture, but a timeless ethical masterpiece-1,330 couplets that teach virtue (Aram), governance (Porul), and love (Inbam). Its verses speak of non-violence, justice, compassion, equality, and duty-values that form the very bedrock of our Constitution. Sir, its universal wisdom has been acknowledged across this very House. The Prime Minister, Finance Minister and many others have quoted Thirukkural in Parliament. To immortalise his message the then Chief Minister of Tamil Nadu erected the 133-foot tall statue of Thiruvalluvar in Kanniyakumari, where the three seas meet. That statue stands not just in granite-it stands in history. The Tamil Nadu Legislative Assembly has passed resolutions. Courts have urged the Government to translate Thirukkural into all Indian languages and include it in the national curriculum. It transcends region, religion, and language. It unites where politics divides. It guides where laws fail. I appeal to the Minister of Culture and Union Government to honour a poet who belonged to all of humanity. Let Thiruvalluvar's voice ring not only from textbooks in Tamil Nadu but from the heart of India. Declare Thirukkural as India's National Treasure Book. (ends)

Re: Need to address the problems being faced by handloom weavers in Andhra Pradesh

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): In the drought-prone villages of Rayalaseema, where crops often fail, it is the loom that has sustained generations. Weaving is not just a livelihood here—it is a legacy of patience, pride, and skill. Across Andhra Pradesh, over 3.5 lakh handloom weavers, many of them aging artisans, continue this tradition against all odds. Recognising their contribution, the Government of Andhra Pradesh, has taken important steps. Over 90,000 weavers above the age of 50 are now receiving ₹4,000 per month through the NTR Bharosa Pension. The state has also announced a 200-unit power subsidy for handloom units—an essential relief in reducing production costs. But the support of the Central Government is equally vital to ensure sustainability. I urge the Union Government to take urgent steps to exempt GST on handloom products to protect traditional markets and boost sales; strictly enforce the Handlooms (Reservation) Act to prevent illegal imitation by powerlooms and provide subsidised jacquards and modern weaving tools to enhance productivity and competitiveness. These are not demands—they are lifelines for a community that continues to weave India's cultural identity, thread by thread. (ends)

Re: Need to declare the birthday of King Ashoka as the National festival and declare the day as national holiday

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्राट अशोक का जन्म- दिन प्रति वर्ष हिंदी मास चैत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी को अशोकाष्टमी के रूप में मनाया जाता रहा है । सम्राट अशोक के शासननिति ,नीति शास्त्रों, शिलाशास्त्रों के लोककल्याणकारी प्रभाव को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज में "अशोक चक्र" जो है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट अशोक के जन्म दिन को राजकीय अवकाश घोषित किये है जो बहुत ही सराहनीय है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए इनके जन्म दिन (अशोकाष्टमी) हिंदी मास चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर राष्ट्रीय पर्व की मान्यता देकर इस महापर्व को गति प्रदान करने का कृपा करें।

(इति)

Re: Situation arising out of eviction drive in Assam

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): I rise to vehemently condemn the demolition drive in Assam-forced eviction and destruction of thousands of families displacing them without any provision for rehabilitation, relocation, or relief. Despite Supreme Court guidelines mandating show-cause notices and a 15-day response window, the evictions were executed within days, often just one or two of notice, without personal hearings or meaningful recourse. This illegal action is nothing but breach of law by authorities themselves. What is more alarming is the targeting of Bengali-origin Muslim families, many of whom had lived in the region for over 60-70 years, with due documentations. There was no alternative housing, no compensation, no food, no shelter. Mosque buildings, schools, homes are razed even during heavy monsoon rains, leading to lives uprooted and dignity shattered which led them stateless and disenfranchised. The Supreme Court has already issued a notice to authorities over alleged contempt of court seeking rehabilitation, reconstruction, and constitutional justice for the displaced. Erasing the belongings of poor people overnight is not governance. I urge the Government to strictly pause further demolition, comply fully with judicial mandates, provide immediate relief, resettlement and compensation.

(ends)

Re: Construction of National Highways in Daman and Diu Parliamentary Constituency

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मेरे संसदीय क्षेत्र दमन और दीव अतंर्गत दीव एक आइलैंड जैसा है, जो समुद्र की गोद में बसा हुआ है। यहां हमारे स्थानीय लोगों की मर्जी के विरुद्ध नेशनल हाईवे लाया जा रहा है। हमने बहुत सारे नेशनल हाईवे देखे हैं जिसको नगरपालिका से बाईपास किया जाता है। किंतु दीव में लोगों की मर्जी के विरुद्ध नगरपालिका से निकला जा रहा है, जिससे बहुत लोगों के घर-बार, दुकान टूटेंगे। लोग बेघर होकर बर्बाद हो जाएंगे, जबकि अन्य विकल्प भी है। गुजरात के कोटडा से यह नेशनल हाईवे दीव में लाया जाए तो हमारे लोगों की हानि भी नहीं होगी और नेशनल हाईवे भी बन सकता है। दमण में नेशनल हाईवे तो है लेकिन वह बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, साथ ही अधूरा भी है। नानी दमण से मोटी दमण का कोई जुड़ाव नहीं होने से उसे भी नगरपालिका विस्तार में बने दमण के ब्रिज से लोगों को साधन ले जाने पड़ते हैं, जिसके कारण पूरे दमण में ट्रैफिक जाम रहता है, शनिवार, रविवार एवं वार त्यौहार में कोई गाड़ी लेकर दमण में घूम नहीं सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दीव के NH को कोटडा से बनाकर हमारे लोगों की रक्षा करे एवं दमण में ब्रिज बनाकर नानी दमण से NH को जोड़ा जाए। (इति)

Re: Need to declare and develop Prayagraj-Lucknow State Highway as a National Highway

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कौशांबी (उत्तर प्रदेश) के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर जनपद प्रतापगढ़ के मंनिखेड़ा से होते हुए यह मार्ग राज्य ग्राम चौबसी, दभेहटा पुल (राम ब्रिज), दनियालपुर, सैनी चौराहा, जीतौरा रोड, कामसिन मोड़, सौरई बाजार, मंझनपुर, करारी, भेवरिका कटरा, सर्सई अकील, पुरखास, चंदवा का पुरवा, यमुना नदी घाट से होकर जनपद प्रयागराज के रीवा मार्ग तक पहुँचता है। यह मार्ग प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज जिलों को जोड़ता है तथा अत्यधिक व्यस्त रहता है। इस मार्ग से भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं, किंतु सड़क की चौड़ाई कम होने और स्थिति खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आवागमन का मुख्य साधन है। जनहित में इस राज्य मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर उसका चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराना आवश्यक है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सशक्त हो, यातायात दबाव कम हो और आर्थिक विकास को गति मिले। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर शीघ्र निर्माण कार्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। (इति)

Re: Need to establish ESIC hospital in Bardoli Parliamentary Constituency

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र 23 बारडोली लोकसभा के वस्त्र उद्योग इकाइयों से जुडे श्रमिकों के चिकित्सा उपचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की सत्याग्रह वाली पावन भूमि बारडोली के सूरत जिले की ग्रामीण विस्तार में एक हजार से ज्यादा वस्त्र उद्योग कार्यरत हैं। हर एक इकाई में हजार से ज्यादा श्रमिक कार्य करके अपने एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे श्रमिकों के चिकित्सा उपचार के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) हॉस्पिटल जो मुफ्त या राहत दर पर चिकित्सा उपलब्ध कराती है, किन्तु सूरत ग्रामीण में जहां हजारों की संख्या में वस्त्र उद्योग है, वहां पर एक भी ESIC हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होने के कारण श्रमिकों को उपयुक्त चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अत: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रमिकों के उचित उपचार हेतु एक ESIC हॉस्पिटल देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to construct a railway foot overbridge near Kuber Nagar in Ahmedabad East Parliamentary Constituency

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व में नरोडा विधानसभा में रेलवे लाइन पर "श्रीमद राजचंद्र अंडरब्रिज" के पास कुबेरनगर में आईटीआई स्थित है, जहां आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ समय पहले रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाइन के चारों ओर दीवार बनाने के कारण इन बच्चों को पढ़ाई के लिए आईटीआई तक पहुंचने के लिए खतरनाक तरीके से दीवार और रेलवे ट्रैक कूदना पड़ता है। अंडरपास में भी चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, इसलिए उन्हें दुर्घटना के डर के बीच सड़क पार करनी पड़ती है। भविष्य में कोई दुर्घटना न हो और बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अनुरोध है कि इस रेलवे ट्रैक पर फुटओवर ब्रिज बनाने का उचित निर्णय शीघ्र लिया जाए।

(इति)

लोक महत्व के मुद्दे – जारी

1407 बजे

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य शून्य काल में बोलने की इच्छा रखते हैं इसलिए कुछ सदस्यों को अवसर दिया जा रहा है।

श्रीमती संजना जाटव जी

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर में पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

भारत सरकार की योजना 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत पानी की टंकियां तो बन चुकी हैं किंतु इनमें जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कई स्थानों पर केवल कागजों में ही कार्य पूर्ण दिखाई देता है। हकीकत में न तो जल आम जन को मिल रहा है और न ही इनका निर्माण गुणवत्ता युक्त किया जा रहा है। पानी की पाइपलाइन घटिया क्वालिटी की बिछाई गई है और इस कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया लेकिन उनको रिपेयर नहीं किया गया, इसके कारण आमजन को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर बिना किसी कार्य के फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों को कई करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में दिशा मीटिंग में जवाब मांगा लेकिन आज तक मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में न हो सके।

(1410/VB/RCP)

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 2 लाख 45 हजार रसोइए बिहार में काम कर रही हैं। सभी रसोइयों से छ: से सात घंटे काम कराए जाते हैं। यहाँ तक कि रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी उनको बुलाकर काम कराए जाते हैं। इनको केन्द्र सरकार की ओर से एक हजार रुपए और राज्य सरकार की ओर से 650 रुपए मिलते हैं यानी कुल मिलाकर इन लोगों को केवल 1650 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वेतन के रूप में इनको न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये मिलना चाहिए। 65 साल तक इनकी नौकरी होनी चाहिए। इनको 10 महीने का ही सैलरी दिया जाता है, जो कि पूरे 12 महीने तक दिया जाना चाहिए।

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्मानित सदन में, लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैडम, इंटरनेट और सोशल मीडिया के मामले में आज दैनिक मानसिकता यह है कि इससे जिंदगियाँ छीनी जा रही हैं, प्रतिष्ठा नष्ट की जा रही है और सार्वजनिक संवाद में जहर घोल दिया जा रहा है। हमारे बीच जो सबसे कमजोर हैं, वे इसका शिकार सबसे पहले होते हैं। युवा और महिलाओं को लगातार सायबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यह महिलाओं को सार्वजनिक और ऑनलाइन जीवन में भाग लेने से रोकता है। आज कई परिवारों की अखंडता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा एक क्लिक से चकनाचूर हो रही हैं। यह उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के बारे में नहीं है। यह जवाबदेही का एक ढाँचा स्थापित करने के बारे में है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानहानि, उत्पीड़न और हिंसा के लिए उकसाने का लाइसेंस नहीं बना सकते हैं। हमारे कानूनी ढाँचे को मजबूत करें। इसके लिए हमें वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियमों से परे जाकर उचित और सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। इन नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी चाहिए।

सेंसरशिप खतरनाक और अवैध सामग्रियों पर एक आवश्यक नियंत्रण है, विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच जिम्मेदारीपूर्वक सोशल मीडिया का उपयोग सिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानों में निवेश करने की आवश्यकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा डिजिटल भविष्य एक चौराहे पर खड़ा है। हम या तो अपने समाज में गलत सूचनाएं, नफरत और भय को इरोड होने दे सकते हैं या यह सुनिश्चित कर सकते हैं और एक साहसिक एवं निर्णायक कदम उठा सकते हैं ताकि सोशल मीडिया एक अच्छे उपकरण के रूप में काम करे।

मैं इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित जिम्मेदारी और अधिक न्यायपूर्ण डिजिटल भारत के निर्माण में हम सभी साथ आएं।

धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद – उपस्थित नहीं।

डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Madam Chairperson, I wish to raise concern about the need to revise the wage ceiling under the ESI Scheme. Currently, workers earning above Rs.21,000 per month are excluded from ESI coverage. This limit has not been revised since 2017, despite rising wages and inflation, resulting in the exclusion of lakhs of vulnerable workers from vital social protection.

States like Karnataka have proposed scientific revisions to minimum wages, with the draft notification suggesting monthly wages from Rs.19,000 to over Rs.34,000.

I urge the Government to expedite this process, raise the ESI ceiling to Rs.30,000 per month, institutionalize periodic revisions, and safeguard existing beneficiaries through statutory amendments and stakeholder consultations.

Thank you, Madam.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Madam Chairperson, thank you for this opportunity. Bengaluru is India's economic engine. It is one of the most important cities today and for the next 20 years for India's growth. However, the city is suffering from a big infrastructure deficit. The only way that traffic congestion in the city can be addressed is through expedited metro expansion.

(1415/HDK/SJN)

Madam, through you, I want to request the hon. Minister of Housing and Urban Affairs to kindly expedite the opening of the already delayed yellow line operations. This connects the residential part of Bengaluru to the Electronic City. Once opened, more than eight lakh people will travel in it every day. So, my request is to kindly open it as soon as possible.

The second request I have is that four months ago, the BMRCL hiked the Metro fare by 130 per cent. Public transport, especially services like metro, must be affordable to the common man. This hike in metro fare has resulted in a deep and steep reduction in the ridership. In the last four months, despite multiple requests, the BMRCL has not made public the Fare Fixation Committee Report. Madam, this is a democracy. Public, especially riders who travel in metro, deserve the right to know on what basis the BMRCL increased the metro fares by 130 per cent. My request to the Minister is to instruct the authorities of BMRCL to immediately publish the Fare Fixation Committee Report.

The third and final request I have is that for the last few months, the approval for the red line metro which connects the most important and critical corridor of Bengaluru is pending before the Ministry. I request, through you, the Minister to kindly expedite the approval for red line metro to ease the traffic congestion in Bengaluru. Thank you so much Madam.

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Madam, I am again raising this matter of arrest of nuns in Chhattisgarh. The facts of the matter are very well known to the House. It was raised early in the morning. Madam, the bail

application, when it was moved in the Sessions Court, the Court has committed it to the NIA court now. The issue is getting more serious now.

Madam, this is an absolutely, you know, a concocted case which has been taken up by an outfit, which is very unfortunate. The State Government has to act. We have requested the Chief Minister to immediately intervene in this matter. Now that it has gone out of the hands of the State Government, we would request the Central Government of India, the Ministry of Home Affairs, to intervene in this matter and get justice for those two hapless women who have been jailed for no fault of theirs. Actually, seeking employment is not a crime. We have 2.5 million migrant workers in Kerala. They come through various sources. Likewise, these ladies have sought employment with these nuns and they have come to take them to their place. The Bajrang Dal has alleged human trafficking and forced religious conversion and the police have registered a false case. It is very unfortunate. This cuts the very root of faith in freedom of women which is a constitutional value guaranteed in this country. This is a democracy; this is a secular nation. If this case is not solved immediately, there will be widespread consequences in our country.

I request the Central Government to immediately intervene and get justice for these two hapless nuns. They have done nothing wrong, nothing against the law. I would request the Central Government to intervene in this matter.

डॉ. धर्मवीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में मेरे इलाके के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं पंजाब से आता हूं। पटियाला में एक बरसाती नदी है, वह पिछले कई दशकों से हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उससे जन-धन और पशु-धन को नुकसान पहुंचता है, फसलें तबाह होती हैं तथा आर्थिकता भी तबाह होती है। इससे शहरों और गांवों के लाखों-लाख लोग प्रभावित होते हैं, परंतु पिछले कई दशकों से इस नदी का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और मोहाली, पटियाला, संगरूर और भटिंडा जिलों को नुकसान पहुंचाती है। वहां बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इसका तटबंध बनाया जाए। वहां चेक डैम्स बनाए जाएं। चेक डैम्स के दोनों तरफ तालाब भी बनाए जाएं, ताकि मछली पालन हो, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, यह पानी सिंचाई के भी काम आएगा और हमारा प्रदेश तबाही से भी बच जाएगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान घग्गर नदी की ओर दिलाना चाहता हूं। (1420/PS/DPK)

*SHRI BALYA MAMA SURESH GOPINATH MHATRE (BHIWANDI): Hon'ble Madam Chairperson, thank you. I want to draw your attention towards Navi Mumbai Airport which is going to inaugurate very soon. This airport should be named after Shri. D.B Patil and this demand was raised by the locals there. This proposal has been passed and cleared by Maharashtra Legislature and sent it to the Central Government. Shri D.B. Patil was a Member of Parliament for two times and he was also a 5-term MLA. He also held the post of Leader of Opposition in Maharashtra Vidhan Sabha. He played an instrumental role in passing Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, in 1989 in Maharashtra. The central Government also approved this act in 1994.

He successfully led the agitations against CIDCO in 1984 even after getting injured. Only after his agitation, the Government accepted the policy of land for land and rehabilitation of 12.5%. This was in the line of the Land Acquisition Act passed in 2013.

Government of Maharashtra took a decision in the year 2022 in this regard to honour his valuable and historical contribution in public life. So, I would like to request you to implement this decision as early as possible by naming Navi Mumbai Airport after Late Shri D.B Patil.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam Chairperson.

The Goods and Services Tax has been in effect nationwide since 1st July, 2017 encompassing handloom products as well as essential raw materials such as yarn. In Odisha alone, weavers collectively procure approximately Rs. 152 crore worth of yarn annually, attracting a GST liability of Rs. 7.6 crore at the prevailing rate of five per cent.

The imposition of GST on these inputs directly escalates the production cost and, by extension, the sales price of handloom products. This burden hampers market competitiveness, leading to a decline in marketing turnover and adversely affecting the livelihoods of the weavers dependent on this traditional profession.

I urge upon the Government to consider exempting handloom products and their raw materials from GST, thereby promoting the sector and safeguarding the economic well-being of weavers across the country.

---

* Original in Marathi

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on a very important issue.

I would like to raise an important issue of a tragic and deeply disturbing incident of self-immolation and death of a young student in Balasore, Odisha. She has been facing mental harassment and victimisation, and there is a failure of institutional and administrative mechanisms to respond to her repeated claims. She had escalated to her local MLA, local MP, Chief Minister, Education Minister, and even the Union Education Minister, but it fell into deaf ears. वह बेचारी बार-बार लड़ाई करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने मजबूरन खुद को जलाकर मार दिया. And this is a very, very sad incident.

उड़ीसा में ऐसी घटनाएं बार-बार होती चली आ रही हैं। तीन लोगों ने एक माइनर महिला को जला दिया, जिसके बाद वह ऐम्स में भर्ती हो गई। हर दिन रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेज़ आते रहते हैं।

1424 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

आप देखेंगे कि उड़ीसा में एक साल के अंदर 40,000 से ज्यादा महिलाएं निखोज हैं, 15,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेज़ हैं और हर दिन 8 रेप होते हैं। उड़ीसा की लॉ और सिचुएशन पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। बालासोर की इस पर्टिकुलर घटना पर मेरे कुछ सुझाव है। There should be a time-bound supervised investigation. Negligent officials should be suspended. Mandatory campus safety audits should be done. There should be constitution of an ICC; POSH compliance; surveillance; 24x7 confidential digital complaint and tracking platform; rapid harassment response protocol with 72-hours protective mandate; trauma counselling; witness and victim-family protection; and fast-track trial.

फ्यूचर में ऐसी घटनाएं न हों, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1425/PC/SNL)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष यह मांग रखता हूं कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। बाबा महाकाल का मंदिर बड़ा प्राचीन है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने महालोक का लोकार्पण किया था। उसके बाद एक साल में वहां तीर्थ यात्रियों और दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। लगभग एक साल में सात करोड़ लोग वहां आने लगे हैं।

वर्ष 2028 में वहां सिंहस्थ होने वाला है। अत: वहां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मैंने पहले भी मांग रखी थी और आज भी रख रहा हूं, सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) वहां के लिए दी जाए। पहले भी वहां उत्तर प्रदेश का दुबे पकड़ा गया है। अभी वहां एक कोई जासूस भी पकड़ी गई है। वह क्षेत्र 'सिमी' का गढ़ रहा है, पीएफआई का गढ़ है। इसलिए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दोनों में से एक वहां के लिए दी जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, यह देश संविधान से चलता है। लेकिन, संविधान के द्वारा प्राइमरी के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय एवं 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है।

इसके पूर्व में भी एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों का संविलियन करके प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में चल रही मर्जर प्रक्रिया से जहाँ छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वहीं हजारों रसोईयों की सेवा भी समाप्त हो जायेगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं ग्राम प्रधान/विद्यालय प्रबन्ध समिति पर दबाव बनाकर विद्यालय बंद करने के समर्थन में प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार विद्यालय बंद करके नौनिहालों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, श्री गोडम नागेश जी।

… (व्यवधान)

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : हजारों प्रधानाध्यापकों के पद एवं रसोईयों की सेवा समाप्ति जैसे निर्दयी एवं कठोर निर्णय की कल्पना नहीं की जा सकती है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : नागेश जी, आप स्टार्ट कीजिए।

… (व्यवधान)

*SHRI GODAM NAGESH (ADILABAD): I would like to raise an important issue pertaining to my parliamentary constituency Adilabad in Telangana. The Telangana government has released a G.O to reserve a land parcel of 1,49,000 hectares of land for creating a tiger corridor as part of tiger conservation, which affects 339 villages. Though this proposal was made by the state government, now they are trying to blame the Central Government for this decision. Recently, people belonging to various sections like SC, ST and OBC protested against this decision and as a result the Telangana government stayed that G.O. I request the minister for Forests and the

* Original in Telugu

central government to direct the state government to cancel the G.O, which has been stayed in the interest of the public. I thank you for giving me this opportunity.

(1430/SPS/SMN)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, धन्यवाद। जिस मुद्दे से देश के सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, मैं उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डीपीसीओ एक्ट, 2013 के अंतर्गत कुछ एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, जिनका रेट कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन भारत में जो सबसे अधिक दवाएं उपयोग की जाती हैं, उनमें बीपी और डायबिटीज़ की हैं, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेम कंपोज़ीशन की मेडिसन 10 अलग-अलग कंपनियां बना रही हैं और सभी कंपनियों के दाम अलग-अलग हैं। वे 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का प्रॉफिट कमा रही हैं। आप देखिए तीन रुपये की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एक कंपनी उसको दस रुपये की दे रही है और दूसरी पचास रुपये की दे रही है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि कम से कम सेम कंपोज़िशन वाली दवाओं के रेट की कैपिंग की जाए, ताकि देश के लोगों से जो लूट हो रही है, वह बंद हो सके।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 1960 में कांग्रेस सरकार ने मेरे लोक सभा क्षेत्र बदरपुर गांव में एनटीपीसी का पावर हाउस बनाने के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी थी। अब एनटीपीसी का पावर हाउस बंद हो चुका है, तो क्षेत्रवासियों की यह इच्छा है कि उस खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर क्षेत्रवासियों के लिए एक कॉलेज, स्टेडियम और हॉस्पिटल बनाया जाए।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हॉस्पिटल, स्टेडियम और कॉलेज बनाने के लिए इस एनटीपीसी की खाली पड़ी ज़मीन में से जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे हॉस्पिटल, कॉलेज और स्टेडियम बनाया जा सके। एनटीपीसी की ज़मीन पर जो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, उसे बंद करने पर विचार किया जा रहा है। यह छात्रों के हित में नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय को बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं। इसके अलावा, बदरपुर गांव में जो बड़ा स्टेडियम था, कांग्रेस सरकार ने उसे समाप्त कर दिया था। अब उसके स्थान पर नया स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है।

*SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): Hon'ble Chairman, my Nashik district produces 10% of the entire onion production in India. During last season, it was more than the average, but due to unseasonal rains in the month of May, the onion and grapes production badly affected. I have given a request letter to Hon'ble Agriculture Minister in this regard. Due to heavy raining, crops like onion and grapes are severely damaged. So, a wet drought should be declared.

Currently, the farmers are not getting remunerative prices for onions and hence incurring losses. They are unable to recover even the production cost. Hence, I would like to request Central Government to declare an MSP for onion and it should be procured through NAFED and NCCF.

An onion-based food processing industry should also be set up in my constituency. Thank you.

---

* Original in Marathi

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत बिलग्राम-मल्लावा-उन्नाव स्टेट हाईवे संख्या 38 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह राजमार्ग एक तरफ हरदोई और उन्नाव को जोड़ता है और दूसरी तरफ शाहजहांपुर को नेशनल हाईवे 730 से जोड़ता है। हरदोई में इसके संकरा होने के कारण यहां आए दिन भीषण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले वर्ष मल्लावां के नगर पालिका अध्यक्ष की यहां मृत्यु हो गई थी और इसके अलावा 15 अन्य लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की थी।

मेरा सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्टेट हाईवे संख्या 38 और स्टेट हाईवे संख्या 137 को नेशनल हाईवे की स्वीकृति दी जाए और उसे फोर लेन बनाया जाए। धन्यवाद।

(1435/RHL/RP)

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आज शून्यकाल में लोक महत्व के प्रश्न पर केन्द्र सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय का ध्यान प्रतापगढ़, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, में उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या 32 लाख से अधिक है एवं इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 85 प्रतिशत से ज्यादा है। जिले के अधिकतर परिवार कृषि पर निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति निम्नवर्गीय है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है, तो उनका परिवार अतिरिक्त बोझ सहन नहीं कर पाता है। उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली या लखनऊ जैसे शहरों में जाना पड़ता है। विशेष रूप से यह स्थिति छात्राओं के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक परिवेश, दूरी और सुरक्षा के कारण माता-पिता अपनी बेटियों को अन्य जिलों में भेजने से हिचकते हैं। परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली छात्राओं को भी उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है और वे स्नातक की पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जिले में कोई महाविद्यालय नहीं है, जो उन्हें सुरक्षित और सुलभ शिक्षा दे सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रतापगढ़ जिले में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु सर्वे कराकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। वन अधिकार अधिनियम, 2006 की मूल भावना थी कि आदि-अनादि काल से वन विभाग की भूमि पर निवास करने वाले आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन वन अधिकार अधिनियम, 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदायों ने अपना दावा पेश किया, जिसमें से 25 लाख आदिवासियों को मालिकाना हक मिला। आज भी 26 लाख आदिवासी परिवारों ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है। मतलब डेढ़ से दो करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार के अधिकारियों ने कहा है कि बाघों को स्थापित करने के लिए चार लाख आदिवासियों को

विस्थापित किया जाय। अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो जो ऐसे अधिकारी और मंत्री जी हैं, उनके वहां एक-दो टाइगर छोड़ दिए जाएं। टाइगरों को रखने के लिए आदिवासियों को क्यों विस्थापित किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के देवास शहर में बारिश के मौसम में आदिवासी समुदाय के परिवारों को वन विभाग द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। आजादी के पहले आदिवासी समुदाय के लोग अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेकर आते थे, तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे, लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है। कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, जो गलत है। मेरी मांग यह है कि वर्तमान में जो 26 लाख आदिवासी परिवारों के पेंडिंग दावे हैं और जो निरस्त कर दिए गए है, सरकार पुन: उनका रिव्यू करे और इन आदिवासी समुदाय के परिवारों को उनका मालिकाना हक दिया जाय।

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : सभापति महोदय, धन्यवाद। जब यहां शून्यकाल शुरू हुआ, तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दिनांक-25 जुलाई, 2025 को एक घटना घटी। हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की तीन भोली-भाली बेटियों को बहला-फुसला कर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहां पर दो नन मिलीं, जिन्होंने उनको आगरा ले जाने के लिए टिकट करवाई थी। एक बच्ची रो रही थी, जिसको देखकर कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। यह सुबह साढ़ आठ बजे की बात है। जब उस बच्ची से पूछा गया तो वह रोते हुए बोली कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूं। उसने अपने जीजा जी का नंबर उपलब्ध करवाया। पहले उनसे बात हुई, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस तथा जीआरपी थाना के अधिकारी एवं कर्मचारी आए, बजरंग दल के साथी भी आए, इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए। उस बीच पूरी छानबीन हुई। वे जो दो नन हैं, उनमें से एक जबलपुर से आई थी और दूसरी आगरा से आई थी। वे क्यों आई थीं? पहली बार छत्तीसगढ़ आई थीं?

(1440/KN/RTU)

वे कहीं नहीं रुकी और स्टेशन पर ही रुकीं। यह प्रश्न उठता है और हमारे वरिष्ठ माननीय सांसदगण, जो जिम्मेदार हैं, अनेक पदों पर रह चुके हैं, ने इसका भ्रामक प्रचार किया है। कांग्रेस के सांसद खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्विट किया है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने इसमें ट्विट किया है। छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है। उसके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। वहां पर दो धर्मों को लड़ाने का प्रयास कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। ... (व्यवधान) आप लोग बिना जानकारी के... (व्यवधान) हाँ, वे मेरे को जानती हैं। वे कहां से आईं। जब केरल की लड़कियां यहां आईं तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बचाएंगे? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, आप इधर एड्रेस कीजिए।

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : हम अपनी आदिवासी बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे बस्तर के माननीय सांसद महेश कश्यप जी के क्षेत्र से वे लड़कियां लाई गईं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका धन्यवाद।

श्री सालेंग ए. संगमा जी।

... (व्यवधान)

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Thank You, Mr. Chairman Sir. I rise to speak on drugs crisis and epidemics in Meghalaya. I rise to expose the catastrophic failure threatening the North-East especially Meghalaya which faces unprecedented drugs with 10 per cent of our population, that is, 3 lakh people trapped in addiction, a horrifying increase from 2 lakh since last year. Among youth aged 15-29 years, the prevalence rate reaches a devastating 30 per cent of our population in Meghalaya. Meghalaya's proximity to the golden triangle and Manipur's unrest have worsened trafficking. However, this has not been reflected in the Customs inspection. Only 10 per cent of anything entering India is checked. Rest of the illegal drugs coming to Meghalaya are not checked. That is why I would like to urge upon the Government to kindly see that whatever is coming through the international border should be checked. Therefore, hon. Chairperson, I urge the Ministry of Home Affairs to immediately establish the "National Drug Eradication Command" in the North-East, provide funding to the Government run rehabilitation Centre and conduct an onslaught on the drugs menace in Meghalaya.

Hon. Chairperson, instead of arresting whole of the drugs cartel and the mafia, the Government of Chhattisgarh is arresting the two Christian nuns who were innocent.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। राजस्थान प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले के समय से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। एसआई भर्ती, जिसमें 859 नए थानेदार बनाने थे, 103 से ज्यादा ट्रेनी और अन्य लोग जेल के अंदर हैं। उसकी एसओजी जांच कर रही है। हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में बड़ी रैलियां कीं। एक-डेढ़ लाख लोगों की रैली जयपुर में की और राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया। आज भी 100 दिनों से प्रदेश के युवा एसआई भर्ती को रद्द कराने और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जयपुर में धरने पर हैं। मैं स्वयं लगातार 70 दिनों से ज्यादा धरने पर था। लोक सभा चल रही है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आरपीएससी को भंग करें। एसआई भर्ती को रद्द करें। पेपर लीक की तमाम घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही हैं, जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर

दिया है। हम चाहते हैं कि इन मामलों की सीबीआई जांच हो। हम प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से अपील कर चुके हैं और उनसे टाइम भी मांगा है कि एसआई भर्ती रद्द करें। पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए नया कानून राजस्थान के अंदर बनाये। यह हमारी मांग है।

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Mysuru is a city known for its heritage, its education and its culture. Indeed, it is the cultural capital of Karnataka. It is a matter of great surprise that the city is now in the news for the uncovering of a synthetic drugs MDMA manufacturing centre.

(1445/UB/ANK)

The worth of the drugs was reported to be around Rs. 390 crore. The drugs manufacturing unit was in plain sight of the authorities. Yet, no action was taken by the Karnataka Police. It is extremely shocking that it was the Maharashtra Police which came to Mysore and uncovered this drugs manufacturing unit. When asked, the Home Minister of Karnataka Government simply said that they failed. This attitude is weakening our institutions responsible for maintaining law and order in Karnataka.

Recently, in Udayagiri also, when a police station was attacked, no action was taken against the perpetrators of the attack. In the case of stampede in Bangalore, the police were simply scapegoated as being the perpetrators. The synthetic narcotics case points towards an operation that is crucially hampering the lives of youth in Mysore. It is also a matter of concern that in a recent raid in Gulbarga, the aid of the Minister of IT in the Karnataka Government was also caught in the same drug bust.

I would ask the Home Ministry through you, Sir, to launch an inter-State investigation into this matter and establish an NCB Task Force unit in Mysore until such activities are brought to an end.

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I am raising this issue regarding long pending wages. It is a charter of demand which has been pending for more than five years regarding general insurance employees. General insurance companies like the GIC, the New India Assurance, the Oriental Insurance Company Limited, the United India Insurance Company, and National Insurance Company are public sector companies and they have been performing extremely well. Usually, public sector banks' charter takes place first. After that, the insurance industry is

addressed. So, LIC is done. This time around, more than five years ago, LIC was paid. LIC was given their dues but general insurance companies' employees and unions demonstrated in different ways. They had talks with the management. They represented through their memorandums. I represented through memorandums of theirs. I represented to the Finance Ministry's DFS. But nothing has been done. Since the performance was also good, the Government expected that two or three companies out of them would perform well. The Government had infused capital also. The results were good. I want to ask the Government to give reasons why the employees' rights have been withheld.

I am drawing the attention of the Government and, at the same time, this august House would also agree with me that whatever is due to the employees, their rights should be given. I hope the Government takes cognizance of this and expedites the wage revision of the employees.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to draw the attention of the Home Ministry as well as the External Affairs Ministry regarding an issue of illegal recruitment of youth from India to foreign countries.

The human trafficking of Indian citizens, particularly of Keralites in Mayavadi, Myanmar, has become a major issue. There is a network of cybercrime cell personnel and the agents offering good jobs in the USA and taking aspirants to Bangkok airport on tourist visa. Then they were trapped and taken to unknown places of Mayavadi. A youth from Kollam, Sri Vishnu Preetha Sreenarayanan, is one of the victims of this trap. He belongs to my constituency. The cybercriminals at Mayavadi have a network of human trafficking in India. The traffickers confiscated their documents and demanded a huge amount for their release. The underworld criminals at Myanmar tortured the victims physically and mentally. They killed those who opposed their illegal acts. More than 144 people are there, 74 people have already been caught and most of the people are in the detention centre of Bangkok.

Therefore, I would like to urge the Government to initiate immediate diplomatic action to prevent human trafficking in Mayavadi, Myanmar, and

take legal action against the agents of cybercriminals in India. Also, I would like to urge the Government and the External Affairs Minister to do the needful so as to bring back all the persons who are trapped in the detention centre. They are now under the custody of the Thailand-Bangkok Government. This matter has to be addressed at the earliest.

(1450/RAJ/NKL)

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद है और मुरादाबाद के लोगों को रोजगार के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में जाना-आना पड़ता है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे आग्रह पर मुरादाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलाई है, जो सप्ताह में एक दिन चलती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि जो ट्रेन मुरादाबाद से मुंबई डायरैक्ट जाती है, वह सप्ताह में एक दिन न जाकर, प्रतिदिन जाए तो मेरे क्षेत्रवासियों को मुरादाबाद से मुंबई आने-जाने और अपना व्यवसाय-रोजगार करने में सुविधा होगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूं।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. आज मैं इस सदन में एक ऐसे ऐतिहासिक इश्यू की ओर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। The institution of the Dalai Lama is in question today. Currently, His Holiness the 14th Dalai Lama is 90 years old. The Nalanda tradition of Tibetan Buddhism has brought the religious practice of reincarnation. 90 सालों के बाद रीइनकारनेशन होगा, लेकिन आज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इंटरफेयर किया है कि the 15th Dalai Lama will be approved and recognised by the Communist Party of China.

सभापति महोदय, 90 साल होने के बाद यह एक क्वैश्चन मार्क है? नालंदा बुद्धिज्म के लिए, तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए दलाईलामा नहीं है। आज दुनिया के बुद्धिज्म के लिए हिज होलिनेस 14वें दलाईलामा एक सिंबल है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह कहना चाहूंगा।

His Holiness the Dalai Lama is the messenger of peace, non-violence and compassion. India, the land of non-violence should recognise His Holiness the 14th Dalai Lama by awarding Bharat Ratna to Him for His service to non-violence, compassion and peace in the world. Thank you.

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, सर, दुनिया में धार्मिक आजादी और ह्यूमन वैल्यूज की बात होगी, सबसे बड़ी शहादत की बात होगी तो नौवें गुरु तेगबहादुर

साहिब जैसी कोई शहादत नहीं है। आज से साढ़े तीन सौ साल पहले उन्होंने धार्मिक अजादी और ह्यूमन वैल्यूज के लिए अपनी शहादत दी थी।

सर, मैं आनंदपुर साहिब लोक सभा क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूं। गुरु साहिब की शहादत का सफर आज से साढ़े तीन सौ साल पहले श्री आनंदपुर साहिब से शुरू हुआ था, जहां कश्मीर के लोगों ने आकर उनसे आग्रह किया था कि हमारे धर्म पर बहुत बड़ा संकट है, ह्यूमन वैल्यूज पर बड़ा संकट है। गुरु साहिब ने वह सफर श्री आनंदपुर साहिब से शुरू किया और आज जहां हम लोग खड़े हैं, दिल्ली के चांदनी चौक पर उनकी शहादत हुई थी। हालांकि साढ़े तीन सौ साल की शहादत के अवसर पर पंजाब सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत बड़े समागम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भी उनकी शहादत को समर्पित बहुत बड़ा कार्यक्रम करेगी।

मैं भारत सरकार से एक छोटा-सा आग्रह करता हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चांदनी चौक से बिल्कुल लगा हुआ है। गुरु तेगबहादुर जी की साढ़े तीन सौ साल की शहादत के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नामकरण उनके नाम पर किया जाना चाहिए ताकि सारे देश में जो लोग सफर करते हैं, वे गुरु साहिब के इतिहास को जानें और उनसे प्रेरणा लें।

(1455/NK/VR)

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदया, संसदीय क्षेत्र राजनादगांव में 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत पूर्व में हॉकी की एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी, कबड्डी एकेडमी प्राप्त हुई है। हाल ही मे राजनांदगांव जिले में एथलेटिक्स की तैयारी हेतु सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के कवर्धा जिले में कबीरधाम है, कवर्धा में विकास की अपार संभावनाएं है। खेल के लिए बहुउद्देश्यीय भवन के माध्यम से, एक ही स्थान पर बैंडमिंटन, बास्केटबॉल, जूडो, हैंडबॉल तीरंदाजी सहित अन्य खेलों की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

महोदया, कबीरधाम जिले में विशेष रूप से पिछडी जनजाति बैगा बस्तियों की भी बसाहट है। उनकी रूचि तीरंदाजी में अधिक है। उस क्षेत्र के युवाओं की एथलेटिक खेल के प्रति रूचि है, जिस हेतु एथलेटिक ट्रैक की स्थापना किया जाना भी बहुत आवश्यक है।

महोदया, मैं बहुउद्देश्यीय भवन हेतु लगभग 20 करोड़ का प्रस्ताव एवं एथलेटिक ट्रैक हेतु लगभग 7 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट दे चुका हूं। खेल के विकास हेतु खेलों की अधोसंरचना की व्यवस्था के आधार पर ही यह सभव है।

कवर्धा में खेल के विकास हेतु बहुउद्देशीय भवन की स्वीकृति प्रदान कर राशि आबंटित करने की कृपा करे, जिससे खेल में कवर्धा आगे बढ़ सके।

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Thank you Chairman, Sir, for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance with regard to my constituency Lakshadweep, which is a Scheduled Tribe area. It is a socially and economically backward area. A notification has been issued by the Revenue Department of Lakshadweep which talks about acquiring Bitra Island which is the smallest island in Lakshadweep. Its stretch is less than a kilometre and it has not more than 500 people living there. Despite that, it hosts a significant economic zone, as the lagoon of Bitra Island is the largest in area, bigger than those of any other island in Lakshadweep. Fishermen from all the islands go, camp and fish there. It is a big economic opportunity for them.

In the pretext of national security, the Revenue Department is acquiring this land. After Independence, we have never had any national security issue for the last many decades. A Coast Guard unit and a Navy unit are already there on this island for national security purposes. Through you, my humble suggestion to the Government is to withdraw this notification immediately. This is an ill-conceived idea which does not have any compensation or rehabilitation plan for those who are already living there. Thank you, Sir.

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं बहुत भारी मन से एक विषय उठा रहा हूं जो पूरे देश का है और सभी सांसदों का है। नृत्यांगना मंच पर परफॉर्मेंस कर रही है, वहीं गिर कर मर गई, क्रिकेटर ने एक छक्का मारा और वहीं गिरा और मर गया। मामा भांजे की शादी में नाच रहा है, गिरा और मर गया। बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, गिरी और मर गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ, मर गया। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं।

हमारे संसदीय क्षेत्र के पांचों विधान सभाओं में कम से कम दर्जनों ऐसे लोग अचानक मरे। मैं सरकार से मांग करता हूं, चूंकि ये घटनाएं अचानक हो रही हैं, न ये हॉस्पिटल जा पाते हैं, न पोस्टमार्टम होता है, क्या हम उनके परिवार को भाग्य भरोसे छोड़ देंगे?मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार कोई ऐसा विकल्प तलाशे, ऐसा कोई रास्ता निकाले, अचानक किसी भी आयु वर्ग के लोग की मौतों के लिए कोई उपाय निकाले, जो मर गए हैं उनका रिकार्ड भारत सरकार रखे। उनके परिवारों को बचाने और पालने के लिए कम से कम दस-दस लाख रुपये मुआवजा भारत सरकार देने का काम करे।

(1500/PBT/IND)

*DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): Hon'ble chairman, thank you very much for allowing me to speak in Zero Hour. The onion and cotton growing famers are landed in trouble in Kasmade and Khandesh region of my Dhule Lok Sabha constituency. The onion growers are not getting remunerative prices. Its production cost is around Rs. 1500-1800 but, they are getting only Rs. 700-800. An MSP of at least Rs. 3000 should be given to onion on the basis of Dr. Swaminathan Committee Report recommendations.

Farmers have to procure seeds, fertilizers, pesticides and farm equipments and they have also to pay 18-25% GST on it, that should be cancelled immediately.

Government should also declare a complete loan-waiver to stop the growing number of farmers' suicides. We always regard India as an agriculture dominated country, but a farmer has got a very little importance unfortunately. Our Exim policy is also not justified and logical. Government should take an initiative to form a committee to fix an import-export policy urgently.

Thank you.

€SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Hon'ble Chairman, thank you very much for allowing me to speak in Zero Hour. With heavy heart, I want to raise an important issue today. Beed is a very important district in Maharashtra and it has played an important role in the overall development of Maharashtra BJP Leader Late Gopinathji Munde also belonged to this Beed district. Recently, many such incidents took place in this district which has brought shame not only to Maharashtra but also the entire humanity. Santosh Deshmukh and Mahadev Munde were killed very brutally and all the party leaders have criticized it, but Home Department of Maharashtra is not ready to take any action in this regard. So, I would like to request Union Home Ministry to take appropriate action to do justice to these two and other persons. The family member of Santosh Deshmukh and Mahadev Munde are requesting MPs and MLAs to support them because the Home Department of Maharashtra is not ready to investigate these brutal murder cases.

Hence, I would like to request Home Minister to initiate a CBI enquiry in these cases. Thank you.

---

*Original in Marathi

€ Original in Marathi

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Sir, I would like to bring to the notice of this august House the issues of environmental pollution, climate problems, vegetation, and water treatment and river conservation.

Our country is facing all these problems. We cannot rely only on the modern technologies. I would like to know whether we have any policy to preserve the Himalayan mountain ranges alongside Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, and all the North-East States. We need to preserve the mountains. The Government should bring a policy or create a cell or a department to save our environment. The 15th Finance Commission granted funds for development based on population. But in the hilly areas, the population is always less.

So, my request is that the 16th Finance Commission may be asked to consider grant of more funds for development of North-East despite less population so that our mountain ranges can be developed. Thank you.
(1505/KDS/SNT)

*DR. SAMBIT PATRA (PURI): Thank you sir for giving me the opportunity to speak in Zero hour. I was listening to INC MP Shri Saptagiri Ulaka, who made some remarks about an incident in Balasore. We all are deeply saddened by this unfortunate incident that claimed the precious life of our sister. We all are praying for her soul to rest in peace. This is a very sensitive issue. The statistical figures presented by Sri Ulaka are false and misleading. I want to mention here emphatically that the Odisha govt is a sensitive govt and our Chief minister was very much concerned. He was directly monitoring all the developments relating to the victim. He has taken prompt action and all the accused have been arrested immediately. I want to mention that the Congress backed student organisation NSUI is responsible for instigating the victim through their social media campaign to commit suicide. All the documents are there to prove my point. Stringent action must be taken against those instigators. Thank you sir.

*Original in Odia

श्री रवीन्द्रशुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आपने जीरो ऑवर में लोक महत्व के इस मामले को उठाने की मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यहां छोटे-छोटे कस्बों से लेकर बड़े-बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल्स हैं। इनमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। ढाबों और होटल्स के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों के मूल्य ग्राहकों से लिए जाते हैं। आप यदि फाइव स्टार में वड़ा पाव खाएं तो उसका दाम अलग है और मुंबई में किसी अन्य जगह पर वड़ा पाव खाएं, तो उसका दाम अलग है। चांदनी चौक में समोसा सस्ता मिलता है, तो गोरखपुर के गोला बाजार में अलग दाम पर मिलता है। फाइव स्टार होटल में तो इसका रेट और भी ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किसी वस्तु की मात्रा क्या होगी, इसका मानकीकरण नहीं किया गया है। कहीं छोटी सी कटोरी में खाद्य पदार्थ दे दिया जाता है, कहीं बड़ा समोसा, तो कहीं छोटा समोसा मिलता है। आज तक यह हमें भी समझ नहीं आया। इतना बड़ा बाजार, जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल और रेग्युलेशन के चल रहा है।

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने पिछले 11 सालों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगान्तकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक यह क्षेत्र अछूता है। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपये में तो किसी दूसरी जगह 120 रुपये में, कहीं पर ढाई सौ रुपये में तो कहीं पर में चार सौ रुपये में तड़का दाल मिलती है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर, सामान्य होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, फाइव स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता व उनकी मात्रा निर्धारित करने वाला कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता-युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : धन्यवाद सभापति जी, मैं आपका ध्यान जोधपुर, पाली, बालोतरा जिले में संचालित हो रही अवैध और नियमों का उल्लंघन कर रही फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो प्रदूषण युक्त पानी, बिना ट्रीटमेंट किए जोजरी नदी और लोनी नदी में डाल देती हैं। वहां लगे हुए ट्रीटमेंट्स का उपयोग नहीं लिया जा रहा है। वे खंडहर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। इस वजह से आस-पास के क्षेत्रों में गंदा, पॉल्यूशन युक्त रासायनिक पानी भर गया है। कल्याणपुर के आस-पास के गांवों, तालाबों, श्मशान घाट व स्कूलों आदि में प्रदूषण युक्त पानी भर जाने की वजह से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और इसके समाधान हेतु कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा सख्ती की जाए और वहां टीम भेजकर अवैध फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर उनको करवाया जाए। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं चल रहे हैं, उनको चलाया जाए और नए ट्रीटमेंट प्लांट्स की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि भविष्य में इस समस्या का समाधान किया जा सके।

महोदय, पिछले मानसून सत्र में भी मैंने यह विषय उठाया था, लेकिन पुलिस की टीम वहां आई खानापूर्ति करके चली गई व कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। यह समस्या साल-दर-साल चली आ रही है। अत: इसका समाधान निकालने के लिए कोई नीति बनाएं। धन्यवाद।

(1510/CS/VPN)

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को और माननीय नितिन गड़करी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा इन्दौर को देश के दूसरे सबसे बड़े आउटर रिंग रोड की सौगात दी है। इसमें जिन किसानों की जमीन जा रही है, उनका एक मुद्दा है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार इस पर विचार करे। किसानों का पहला मुद्दा यह है कि उनको वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजा मिलना चाहिए। उनका दूसरा मुद्दा यह है कि जहाँ सरकारी जमीन है, जो काकड़ है, उस पर इस प्रकार का अलाइनमेंट होना चाहिए कि सरकारी जमीन ज्यादा से ज्यादा जाये और किसानों की जमीन कम जाये ताकि उपजाऊ जमीन पर किसान खेती कर सकें। उनका तीसरा मुद्दा यह है कि आउटर रिंग रोड अगले 25-30 साल को ध्यान में रखकर बनाया जाए। उसे बाईपास से दूर बनाया जाए। इसे आने वाले 25-30 साल को ध्यान में रखकर बनाया जाए। इससे जनता को सुविधा रहेगी। मैं सरकार से चाहता हूँ कि वह इन मुद्दों पर विचार करे। धन्यवाद।

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मेरा लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा-भोगनीपुर है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आजादी के 75 साल बाद भी आज तक, हमारा जो जनपद, मुख्यालय उरई है, उससे दिल्ली के लिए कोई रेलवे सेवा नहीं है। जो श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन है, वह दिल्ली से चलकर कानपुर में लगभग 18 घंटे खड़ी रहती है। जो ग्वालियर-बरौनी ट्रेन है, यह बरौनी से चलकर ग्वालियर में लगभग 12 घंटे खड़ी रहती है। जो गतिमान ट्रेन है, वह दिल्ली से चलकर झाँसी में लगभग ढाई घंटे से ज्यादा खड़ी रहती है। अगर इन ट्रेन्स में से किसी भी ट्रेन को उरई तक चला दिया जाए तो उरई, जो हमारा जालौन का मुख्यालय है, हमीरपुर, कानपुर देहात और जालौन के जो यात्री परेशान होते हैं, वे दिल्ली से जुड़ जाएंगे।

दूसरा, नई दिल्ली रेलवे लाइन का कोंच से सर्वे हो गया है। कोंच से जालौन-भिंड-इटावा होते हुए ग्वालियर से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो जो यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस पिछड़े क्षेत्र के लोग सीधे ग्वालियर होते हुए दिल्ली से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak in the Zero Hour today. I would like to request the hon. Minister of Heath and Family Welfare, through you, to please grant us a medical college for Nuapada district in my Kalahandi constituency. It is an aspirational district and does not have any higher education college. It would be a big development for the area if the hon. Minister would grant this as not only would people be able to pursue their career from their own

constituency but also the opening of a medical college would help the people in a big way by offering different kinds of treatment to the people of the constituency. Students from different areas would also come to Nuapada for higher education which would benefit Nuapada in every way. I am hoping and praying that Nuapada medical college is sanctioned and the work starts soon. Thank you so much, Sir.

श्री परिमल शुक्लबैद्य (सिल्चर) : महोदय, आपने आज हमें एक जरूरी मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, आपको इसकी जानकारी है। आज आप इस सभा के भी सभापति हैं और मेरी पार्टी के भी असम के अध्यक्ष हैं। आपको बराक घाटी के बारे में, सिल्चर के बारे में इंच-इंच की जानकारी है। आप इनके बारे में भलीभाँति जानते हैं कि हमारा सिल्चर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। यहाँ आने-जाने के लिए रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। साल भर में रोडवेज और रेलवेज फ्लड और लैंड स्लाइड के कारण तीन महीने बंद रहती हैं। हमारे पास एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कोलकाता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए दिल्ली या अन्य जगहों पर जाएं। पहले सिल्चर से त्रिपुरा की फ्लाइट चलती थी। सिल्चर से मेघालय की फ्लाइट चलती थी। अभी वे फ्लाइट्स नहीं हैं। एयर इंडिया की वाया कोलकाता और गुवाहाटी, दिल्ली तक आने-जाने की एक फ्लाइट थी। यह भी बंद पड़ी हुई है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से माँग है कि आने-जाने के लिए कम से कम एक फ्लाइट सिल्चर टू दिल्ली देने की कृपा करें। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपके माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर को यह अर्जी पेश करता हूँ। हम लोगों ने पहले भी लिखकर दिया है, लेकिन अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। यह काम होने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ। धन्यवाद।

(1515/MNS/AK)

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसा कि हम सब टेलीविजन पर देख ही रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंडी में कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान-माल का कितना नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेज, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं। हमें केंद्र सरकार से जो भी हजारों करोड़ रुपये का रिलीफ फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उससे क्या काम कर रही है? प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास का कितना काम कर रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार से कितना फंड, कब-कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, कल मंडी सदर में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की यहां से जो भी आर्मी फोर्सेज जाकर रक्षा करती हैं, उसकी क्या समय-सीमा तय की गई है, वह भी हमें बताने की कृपा करें। साथ ही इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत रैपिडली हो रही हैं।

उसके लिए यदि कोई रिपोर्ट है, किसी तरह की अनुशंसित, दीर्घकालिक रणनीतियां केंद्र सरकार ने बनायी हैं, तो उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय महोदय, हमारे प्रदेश के प्रशासक द्वारा महाभयानक परंपरा शुरू करवायी जा रही है। सभी सर्किट हाउस प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं। पहले सरकारी फंडों से करोड़ों रुपये के आलीशान सर्किट हाउस बनाए जाते हैं। जैसे ही सरकारी पैसे से वे प्रोजेक्ट बन जाते हैं, वैसे ही वे निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं। यहां तक कि दिल्ली में स्थित एकमात्र सरकारी भवन भी निजी हाथों में सौंप दिया गया है।

महोदय, अब हमारे प्रदेश में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, वह किस पर बनाया जा रहा है? वह हिंदू श्मशान भूमि और कब्रिस्तान पर बनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के लोगों को इस प्रशासक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिंदा लोगों का तो सुख-चैन छीन ही लिया था, अब मरे हुए लोगों को भी श्मशान और कब्र में चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। यह क्या हो रहा है? सरकार ने हमारे प्रशासक को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है कि वह कुछ भी करे? कम से कम श्मशान और कब्रिस्तान को तो छोड़ देना चाहिए। जब हमारे प्रशासक को सरकारी प्रोजेक्ट बनाकर निजी हाथों में सौंपकर, एक प्रकार से बेच ही देना है तो प्रशासन श्मशान और कब्रिस्तान में कन्वेंशन सेंटर बनाकर यह कहे कि श्मशान भूमि और कब्रिस्तान को भी बेच देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान ले और हमारे प्रदेश के लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करें, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की रक्षा करे। सरकारी निवासों को सरकारी ही रहने दिया जाए, क्योंकि आज सरकारी निवास के लिए हमारे दमन और दीव के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है और जब हम एक-दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आवास के लिए तरसते हैं। 500 रुपये का कमरा आज 8,000 से 12,000 रुपये का हो गया है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्किट हाउसों को हमारे लोगों के लिए रखा जाए और हमारी श्मशान भूमि और कब्रिस्तान की रक्षा की जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से देश के शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि भारत देश में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी हैं, अब इनको राज्यों में भी खोला जाना है। लेकिन इसके साथ एक पॉलिसी बना दी है कि एक राज्य में दूसरा आईआईटी नहीं खुल सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरा भी खुला हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईआईटी है, लेकिन वहां से 700 किलोमीटर दूर मेरा भिंड का क्षेत्र है, सतना औद्योगिक जिला है, वहां पर भी एक आईआईटी संस्थान खोला जाए। यदि आईआईटी संस्थान नहीं खुल सकता तो कम से कम कैंपस तो खोला जा सकता है, मैं शिक्षा मंत्री जी से ऐसी मांग करता हूं।

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHIRABAD): Hon. Chairperson Sir, I thank you for giving me this opportunity.

The 'Dhobi' caste is also called Rajaka or Chakali, which is in the Scheduled Caste List in 17 States.

(1520/SRG/RV)

On the other side, in 11 States, namely, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Goa, Dhobhi caste is in OBC list, depriving them of Scheduled Caste reservation facilities. Their social status is similar and these people should get equal facilities. They are representing the matter before the State Government and Union Government, but nothing has been done. Every time the Ministry of Social Justice replied to take up the issue with the concerned State Government. If any report is sent, that is also returned in the name of modalities etc.

I request the Government of India to take up this issue directly and do justice to bring uniform status to Dhobhi people in the entire country. It is also brought to your notice that the profession itself amounts to untouchability. They are extending services to the society from birth to death.

*SHRIMATI SATABDI ROY BANERJEE (BIRBHUM): Honourable Chairperson Sir, I want to talk about some post offices in my Birbhum constituency, including the Margram Post Office. I know that today, in the era of email, fax, and WhatsApp, there is no value in writing letters. But apart from letters, the post office has many other functions that are executed to meet the collective demand from people. Some post offices in my area are in a dilapidated state, so when we demand renovation, the Ministry asks us to use the MP-LAD fund. You know that the MP-LAD is merely 5 crore rupees. There is a Bengali proverb which effectively means, living hand to mouth. There are some recommendations that go to the Ministry from the Post Office through us. If those are imposed on us, then we will not be able to do anything else. If the departments of the concerned ministry properly perform their tasks, then we can do something with the 5 crore rupees; or if the MP-LAD fund is increased, we will gladly do everything. Thank you.

*Original in Bengali

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आज आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बागपत से गुजरने वाली जो हिंडन नदी और कृष्णा नदी है और साथ में ही मेरठ से गुजरने वाली जो काली नदी है, इन नदियों का पानी इतना दूषित हो गया है, इतना जहरीला हो गया है कि इन नदियों के आस-पास के गांवों में पीने का पानी भी दूषित हो गया है। दूषित पानी के कारण वहां के निवासियों को कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है।

महोदय, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि पहले उन नदियों का जल इतना स्वच्छ रहता था कि पर्व के समय उन नदियों के किनारे मेले लगते थे और लोग उनमें स्नान किया करते थे। उस समय अगर कोई सिक्का भी उसमें गिर जाता था, तो वह पानी में साफ नजर आता था और लोग उसको निकाल लेते थे। लेकिन, आज इन नदियों का पानी बहुत दूषित हो गया है। वहां न तो इनकी सफाई का इंतजाम है और न ही उसमें ऐसा कोई दूसरा काम होता है।

महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि नदियों के किनारे स्थित जो सुगर मिल्स हैं या जो दूसरे उद्योग हैं, जो पानी को दूषित कर रहे हैं, जिसके कारण लोग गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उन फैक्ट्रीज़ को, उन उद्योगों को दंडित किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि परियोजना बनाकर उन नदियों के दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए नदियों की सफाई का अभियान शुरू किया जाए, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके।

SHRI E. TUKARAM (BELLARY): Sir, thank you for giving me the opportunity to raise an important matter during Zero Hour.

I wish to draw the attention of the House to the total outstanding dues owed by the Central Government to various States under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). As per the response provided by the Ministry of Rural Development in the Lok Sabha, a total of Rs. 14,603.94 crore remain pending as on 22nd July 2025 under both the wage and material components. Karnataka State alone has an outstanding amount of Rs. 374.80 crore.

MGNREGS is a flagship welfare scheme of the Government of India, aimed at ensuring employment and livelihood security to the rural village people.

(1525/SM/MY)

The delay in disbursement of these funds severely hampers the effective implementation of the scheme and asset-generating development works. So, I am requesting the Ministry to clarify as to when these pending dues will be

released to the States. I also request the Ministry to take immediate steps for disbursement of MGNREGA dues.

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रतिष्ठित सदन में मैं अपने क्षेत्र के एक ऐतिहासिक लोक महत्व के मुद्दे को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय विमानन मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि सागर में एक आधुनिक हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल की स्थापना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें।

महोदय, सागर मध्य भारत का हृदय, एक संभागीय मुख्यालय और स्मार्ट सिटी है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मध्य भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है, जो लॉजिस्टिक हब बनने की अपार संभावनाएं रखता है। सागर में बीना रिफाइनरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि उन्होंने 50,000 करोड़ रुपये बीना रिफाइनरी को विस्तार देने के लिए देकर एक सराहनीय कार्य किया है। इसका शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ही किया किया था। यह क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ला रहा है। इससे न केवल उद्योगों का विकास हो रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सागर में सैन्य इकाइयाँ और कैंटोनमेंट बोर्ड की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और अन्य विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सागर को पर्यटन का एक चमकता सितारा बनाते हैं। यहाँ का केंद्रीय स्थान देश के हर कोने को जोड़ने में सक्षम है। हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल न केवल सागर, बल्कि पूरे मध्य भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनेगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। इस परियोजना से लॉजिस्टिक क्षेत्र में हजारों रोजगार, पर्यटन में वृद्धि और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मैं माननीय विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी से निवेदन करती हूं कि इस मांग को प्राथमिकता देते हुए सागर के सुनहरे भविष्य को साकार करें। सागर की जनता की आकांक्षाएँ और मध्य भारत का गौरव आपकी इस पहल से नई ऊँचाइयों को छुएगा।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : बहुत-बहुत शुक्रिया सर। पिछले 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। 13 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। चूंकि मेरा इलाका बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए वहां की बोली बंगाली भाषा से मिलती है। आज हरियाण और उत्तर हिन्दुस्तान में उन लोगों को तंग किया जा रहा है। Bengali-speaking people from West Bengal, Assam, Kishanganj and Bihar are being harassed. उनके द्वारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड देने के बावजूद भी उनको बोला जाता है कि यह फ्रॉड कार्ड है। मेरा आपके माध्यम से गुजारिश है, खासकर हरियाणा सरकार को चेताया जाए कि वह इस तरह का हरकत न करे, ताकि हमारे लोगों को तकलीफ हो।

दूसरा, जब से यह सरकार आई है, मुसलमान माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, जिसके बारे में चर्चा हुई। वहां भी इनको टारगेट किया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह रुकना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहती हूं। दिल्ली के रोज के अखबारों में एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। डीडीए के पार्क में छह साल की बच्ची को कुते ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर मैं सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल के कुते के काटने के केसेज का जिक्र करूं तो वर्ष 2021 के पूरे एक साल में 63,600 केस थे। वर्ष 2025 में एक जनवरी से अभी जुलाई तक यानी सात महीने में 90,000 से अधिक केस हो चुके हैं।

(1530/MLC/GM)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे भारत में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और निगम हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए कि कुत्तों के लिए आश्रय घर बनाए जाएं और इसकी डेडलाइन भी केन्द्र सरकार की तरफ से तय की जाये। ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत गंभीर विषय है। समय देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।

श्री देवेश शाक्य (एटा) : बहुत-बहुत धन्यवाद मान्यवर। यह मुद्दा मजदूरों और छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। मेरी लोकसभा एटा कासगंज के जनपद एटा में जवाहर तापी परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा की गई थी, जिसकी लागत 2,566 करोड़ रुपये थी, जिसको अप्रैल, 2021 तक पूर्ण होना था, परंतु इसका समय बढ़ते-बढ़ते 23.06.2025 तक हो गया, जिसके चलते इसकी लागत चार हजार करोड़ रुपये बढ़कर 14,628 करोड़ रुपये हो गई है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मेसर्स डूसान कंपनी, जिसके पास इस प्लांट को बनाने का टेंडर हुआ था] इस कंपनी पर कार्य में देरी के लिए क्या अर्थदण्ड दिया गया? मेरे पूछे जाने पर कंपनी का भुगतान रोके जाने का आग्रह इस आशय के साथ किया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है और अभी डूसान कंपनी पर लगभग 100 करोड़ रुपये लोकल मजदूरों और छोटे ठेकेदारों का बकाया है। कहीं ऐसा न हो कि कानपुर में नेटवर्क बनाने वाली कंपनी, जो कि तुर्किए की थी, वह मजदूरों और गरीबों का 80 करोड़ रुपये मारकर भाग गई है। ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जवाहर तापी परियोजना बनाने वाली कंपनी मेसर्स डूसान का भुगतान तब तक पूर्ण न किया जाये, जब तक वह सारी आर्थिक अर्हताएं पूर्ण न कर दे। समयवृद्धि का पांच परसेंट आर्थिक दंड दिया जाये। इस परियोजना के प्रबंधक अजय कुमार को मुझे सही और संतोषजनक उत्तर न देने के लिए उचित कार्रवाई की जाये। धन्यवाद।

*SHRI RAVINDRA VASANTRAO CHAVAN (NANDED): Hon'ble Chairman, today I rise to raise one very important issue related to my Nanded district. The benefits of the crop insurance scheme 2024 have not been provided to the farmers of my Nanded district. So, I want to request the Union Government to credit the benefits of this scheme to farmers accounts immediately. Banana growing farmers have incurred losses due unseasonal rains one and half month ago. The crop insurance company did not consider the loss of the banana crop and denied the insurance benefits. So, I would like to request the Government to set up an automatic whether station at Nanded.

We are going to celebrate the Birth Anniversary of the father of Green revolution, Dr. Swaminatham on 7th August.

Hence, I would like to urge upon the Government that this day should be celebrated as Agriculture Student day. Thank you.

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान खीरी लोकसभा क्षेत्र के विकासखंड पलिया, निघासन, बिजुआ, रमियाबेहड़, फूलबेहड़ और नकहा में आ रही भयंकर बाढ़ की समस्या पर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। लगातार कई गांव जैसे करसौर, ग्रांट नंबर 12 आदि गांव में कटान जारी है और लोगों के मकान और खेती कट रही है। सरकार डूब क्षेत्र के नाम पर बाढ़ से बचाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही और लगभग एक लाख की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अत: मेरी मांग है कि डूब क्षेत्र की बंदिश को हटाया जाये और सैकड़ों गांवों को नदी कटान से बचाया जाये और नदी को चैनलाइज किया जाये। इतना कार्य किया जाये और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाये। धन्यवाद।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : श्री बलभद्र माझी – उपस्थित नहीं।

श्री कुलदीप इंदौरा जी।

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संकट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर-हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती जिलों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है।

*Original in Marathi

(1535/GG/RCP)

आदरणीय महोदय, 'ऑपरेशन सिंदूर' से पहले और बाद भी पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार हो रही है। महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र गंगानगर-हनुमानगढ़ व पंजाब के साथ-साथ राजस्थान नशे और हथियारों की तस्करी का नया केंद्र बनता जा रहा है। तस्करी के कारण अपराध, नशाखोरी में भी काफी वृद्धि हुई है। इससे निपटने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सीमा पर अत्याधुनिक ड्रोनरोधी तकनीक, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल कैमरों की तैनाती की जाए।

बीएसएफ और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठा कर इसमें पहल की जाए। सीमावर्ती गांवों में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरुकता और उपचार योजनाएं लागू की जाएं। बीएसएफ और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में अपराध और नशा बढ़ने पर रोक लग सके।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा के जनपद, लखीमपुर, सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महौली, हरगांव, मोहम्मदी, मितौली सहित तमाम जगह खाद की भारी किल्लत है। लंबी-लंबी लाइनें समितियों पर लगी हैं। किसानों को खाद नहीं दी जा रही है, बल्कि किसानों और महिलाओं को पुलिस की लाठियां मिल रही हैं।

पिछले सदन में माननीय उर्वरक मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में कही हुई बात भी असत्य साबित हो रही है। नेपाल पड़ोसी देश है। उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर दलाल कालाबाज़ारी कर के यूरिया और डीएपी को नेपाल में भेजने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारी आपसे मांग है कि केंद्र सरकार, उर्वरक मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दें कि तत्काल खाद का संकट समाप्त किया जाए।

श्री आलोक शर्मा (भोपाल) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग एक हजार वर्ष पूर्व राजा भोज ने कोलांस नदी सहित 365 जलस्रोतों को मिलाकर बडा तालाब बनवाया था। महोदय, भोपाल में यह बड़ा तालाब 3869 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसका फुलटैंक लेवल 86.176 किलोमीटर है। 361 वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका विशाल कैचमेंट एरिया है। इसके चारों तरफ 223 किस्म के जलीय औषधीय पौधे लगे हुए हैं, जिनमें से 103 पौधों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने दुर्लभ घोषित किया है।

माननीय सभापति महोदय, सैकड़ों प्रजाति के जलीय जीव, अनेकों प्रजाति के पक्षियों का घर भोपाल का बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है। इसी कारण बड़ा तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिला है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भोपाल का बड़ा तालाब चारों तरफ से अतिक्रमण और प्रदूषण की चपेट में है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी आग्रह है कि इस विशाल जल धरोहर को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त करके क्या इसे संरक्षित और सुरक्षित करने की पर्यावरण एवं जलवायु विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा सकती है तो कृपया उससे अवगत कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का पावंटा साहिब कालां एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2003 में औद्योगिक पैकेज दिया था और उस समय बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र में स्थापित हुईं थीं। फार्मास्युटिकल के मामले में आज यह क्षेत्र एशिया में नंबर वन पर आता है। लेकिन यह एरिया अभी भी रेलवे से कनेक्टिड नहीं है। मैं इस विषय को पूर्व में भी माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाया हूँ और उनको लिखित में भी दिया है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस रेलवे लाइन का प्रारंभिक सर्वे वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिया गया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है।

(1540/YSH/PS)

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र को शीघ्रातिशीघ्र रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, ताकि जो आद्यौगिक इकाइयां हैं, वहां पर कच्चा माल पहुंचाया जा सके। इसके साथ-साथ तैयार उत्पाद को मार्केट में पहुंचाया जा सके, जिससे लोगों को भी लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू में अरावली एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिसका नम्बर 14701 और डाउन का 14702 है। यह रामगढ़ शेखावाटी होते हुए श्रीगंगानगर से बांद्रा टर्मिनल (मुम्बई) के बीच चलती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर नहीं होने से यहां के सैनिकों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार और रेल मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन संख्या 14701 और 14702 अरावली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर करने की कृपा करें, जिससे इस ट्रेन का फायदा लोगों को मिल सके।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और रेलवे मंत्रालय का ध्यान विरार लोकल ट्रेन सेवाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। विरार से चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। विशेषकर पीक आवर्स में विरार से दहानू और दहानू से विरार तक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जानी चाहिए। विरार से दहानू के बीच एसी लोकल ट्रेन सेवा जल्द शुरू की जाए। इस रूट पर नॉन एसी लोकल ट्रेनों की संख्या एवं फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि जरूरी है। ट्रेनों में कोचेस की संख्या 12 से बढ़ाकर 15 की जानी चाहिए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

सभी स्टेशनों के दोनों छोरों पर स्वच्छ शौचालय, डिजिटल साइन बोर्ड और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाए। सुबह चार बजे दहानू से चर्चगेट के लिए लोकल ट्रेन सेवा बहुत जरूरी है इसलिए उसे शुरू किया जाए। शाम छह बजे विरार-दहानू की एक्स्ट्रा ट्रेन सेवा चालू की जाए और लोकल ट्रेन सेवा, जो दहानू तक सीमित है, उसे उमरगांव तक एक्सटेंड किया जाए।

*SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon'ble Chairman, Raymond ltd, which is a big industry in Yavatmal, has been landed in trouble. Since 21st July, 2025, around 1000 employees of this company started demonstrations because the older wage contract is expired. As per rules, the wages should have increased since 1st April, 2025 but it could not be materialized. The worker are getting meager salaries and it is not sufficient for their survival. The company set aside the workers and trying to settle this issue with the leaders of a recognized trade union. This company is not ready to sign a new wage contract with workers. The workers union has approached the court of law and matter is still pending. The workers' families are in distress and they are unable to meet their daily needs too.

The wage contract should be for 3 years ideally but the company has fixed it for 4 years. The company also trying to punish the workers by suspending them and not ready to listen to their grievances.

Sir, this is a serious situation and the Government is not ready to take any action . Yawatmal is a very backward district. So, I would like to request the Union Government and Labour Ministry to take a serious note of this workers agitations. Government should try to resolve this issue and do justice to the poor and needy workers of reymond company. Government should also try to setup new industries in this region to provide employment to the youths. Thank you.

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। वहां पर सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां पर करीब 76 गांव हैं और 76 गांवों में पूर्वजों की संस्कृति, पूर्वजों के प्राचीन मकान और मंदिर बने हुए हैं।

(1545/STS/SMN)

सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए वहां पर डुमरी बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका वहां के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डुमरी बांध को निरस्त कर वहां की आम जनता को लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI (GUWAHATI): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to draw the attention of the alarming situation concerning Deepor Beel, the only Ramsar Wetland Sites, in Assam and a vital ecological treasure of Guwahati city. It plays a crucial role in groundwater

*Original in Marathi

recharge, flood mitigation and livelihood support for numerous local communities.

However, this critical ecosystem is under grave threat due to encroachment and illegal land filling in and around the Beel. There is continuous pollution from municipal solid waste which is resulting into degradation of bird habitat threatening over 150 bird species.

Through you, Sir, I urge the Central Government to direct the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to take immediate steps to restore and conserve Deepor Beel and declare it as a protected eco-tourism zone.

Thank you, Sir.

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : सर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहां वर्ष 2014 में एक एफएम स्टेशन स्थापित हुआ था, लेकिन अभी 2025 तक भी उसमें स्टूडियो नहीं बना है और न ही उसके अंदर स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं। यह सिर्फ एक रिले केंद्र बन कर रह गया है। मेरा निवेदन है कि यहां पर एक स्टूडियो स्थापित किया जाए, जिससे यहां के कलाकारों को अपनी परफॉर्मेंस वहां पर करने का मौका मिल सके और किसानों को मौसम की प्रॉपर जानकारी मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Many Government schools across the country in rural areas continue to lack basic facilities like sufficient classrooms, boundary walls, kitchen sheds, dining halls, toilets, approach roads, etc. which are excluded from the current guidelines of MNREGA.

These deficiencies impact not only the safety and hygiene of students but also their ability to learn in a conducive environment.

Sir, there are also many complaints about delayed payments especially the labour component in the MNREGA work and even after completion of work, people have to wait for months to receive payment.

As MNREGA is a social security scheme with the objective of generating employment to arrest migration of labour, if this payment gets delayed, then the entire purpose of this scheme gets defeated.

Therefore, I urge the hon. Minister of Rural Development to take immediate steps to streamline the fund release process, ensure timely wage payments and promote convergence of MNREGA with school infrastructure development on priority by amending the current guidelines.

Thank you, Sir.

*SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. People in my Tirunelveli Constituency are mostly dependant on agriculture. Agriculture crops are very much affected due to heavy rains, cyclones and various other natural disasters besides the wild animals. But the Union Government is providing very less compensation to crop losses. This was the Union Government which always claim to double the income of our farmers. I therefore urge that the compensation given by the Union Government for the crop-loss should be enhanced and timely disbursal should be ensured. I request through you that wild pigs which destroy the crops of farmers should be removed from the Protection of Wildlife Act of the Union and the interests of our farmers should be protected. Thank you.

(1550/MK/RP)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : धन्यवाद सभापति महोदय। भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1954 में समझौते के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर में कोसी नदी पर वर्ष 1963 में बैराज बनाया गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है। फलस्वरूप, गत वर्ष भी बैराज के ऊपर से पानी बह रहा था।

अत: सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कोसी नदी पर पुन: नये बैराज का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 बनाया गया था। उसमें साफ कहा गया है कि एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार का व्यावहारिक लाभ मिल सके।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत नीति-निर्देशक तत्वों का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि "राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह शैक्षिक और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विशेष सुरक्षा करेगा और प्रोत्साहन देगा तथा सामाजिक अन्याय व शोषण के रूपों से उनकी रक्षा करेगा।"

साथ ही, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य की कोई नीति या कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अतः राज्यों के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप अपना विषय रखिए।

---

* Original in Tamil

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सर, मैं अपना विषय ही बता रहा हूं। यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को एक किलोमीटर या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। गरीबों को एवं उनके बच्चों को बचाया जाए। महोदय, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो मैं आपके माध्यम से यूपी सरकार से कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।

*SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Honourable Chairperson, Sir. First of all, I would like to speak in Bengali to protest against the ongoing attack on the Bengali language and Bengali speakers across India. My constituency is Krishnanagar. There has been a long-standing public demand for the Krishnanagar-Karimpur Railway Line. During Mamata Banerjee's tenure as the Railway Minister, she mentioned this project in the Railway budget. This Railway line is being demanded by 12 Lakh people. When I became the MP in 2019, I reiterated the importance of this project to the Railway Ministry and requested them to complete this. Honourable Railway Minister, Shri Ashwini Vaishnaw, had sanctioned 2 crores to conduct a feasibility study. That study ended in December 2023. We didn't get any further information on that. It was informed to us by the Railway Ministry two months back, that they have decided to shelve the project for the time being. Which means they won't be able to carry out this project at the moment. Railway is a very important medium for commuting throughout the country. The Krishnanagar-Karimpur Railway line will benefit 12 Lakh people from three assembly constituencies. You must provide a universal service. Making profit shouldn't be the only mandate of the Railways. Even if you can't make a profit, you still have to immediately start this railway line under the universal obligation. Please don't shelve this and restart work on this.

(1555/UB/SK)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I want to raise an issue regarding the National Livestock Mission. In my constituency, there were a lot of applications under the Mission and a lot of people have got benefited under the scheme. The NLM has helped in developing goat and sheep farms and making fodder units also. It has empowered youth, SHGs and FPOs. Most of the beneficiaries are either SCs or STs under the scheme.

However, there are two issues that we are facing related to the NLM. The first is regarding time taken for sanctioning the loan application. It almost takes two years to get the loan sanctioned. It is such a long time. The applicant has to put the asset in place to

*Original in Bengali

get the loan. The waiting period is almost two years. The second issue is regarding the website of NLM which has been closed ten days ago. Eight months are left for the next Budget to come and before eight months, the website is closed. No new applications are being entertained. Every day, a number of applicants are coming for loans. I request the Ministry concerned to look into the issue, reduce the time period to sanction the loans and open the website to accept new applications.

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के कारण भूगर्भीय असंतुलन हो रहा है और जन-धन की हानि हो रही है।

भीलवाड़ा के उपनगर पुर में सैकड़ों मकानों में अवैध ब्लास्टिंग के कारण दरारें आ गई हैं और जान-माल की अति गंभीर स्थिति बन गई है। जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा अनुबंधों के अनुसार न तो निवेश किया गया है और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। जालिया गांव में 300 मीटर की परिधि में 15 मीटर का घेरा बनाकर 45 किलोग्राम का बारूद भरकर अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। इसी प्रकार से खसरा संख्या-2096 में चरागाह भूमि में भी अवैध खनन हो रहा है। खसरा संख्या-21/44 में गैर मुकीन नाले को बंद कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेक गतिविधियों के कारण आमजन में भारी असंतोष हो रहा है और आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि किसान आत्महत्या की चुनौती भी दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के आगमन के समय भी लोगों ने उनके सामने उपस्थित होकर आत्महत्या के लिए विवश होने की बात कही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को अविलंब बंद कराया जाए।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश के चरखी-दादरी में पिछले साढ़े तीन महीने से किसान धरने पर बैठे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ की है। मेरी मांग है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी लोगों को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये दिलाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बवानी-खेड़ा, नारनोद, हासी इलाकों में तनाना, तालु, जताई से लेकर कुंगड़ तक बाढ़ आई हुई है और इसके कारण लोगों की फसल खराब हो गई है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस तरह से आपने गांव को इकाई माना है, गांव के बजाय एकड़ को इकाई माना जाए क्योंकि आधे खेत में बाढ़ आ जाती है और आधे खेत में सूखा पड़ जाता है और दोनों जगह नुकसान होता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिन लोगों की फसल बाढ़ में डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी फसल बीमा योजना के तहत पैसा दिलाया जाए।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : आज मैं युवाओं के बारे में बात करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं जयपुर शहर से आती हूं, वहां कोचिंग क्लासिस में बच्चे सुनहरा भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। कोचिंग क्लासिस में कम जगह में ज्यादा बच्चों को प्रवेश तो दे दिया जाता है लेकिन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है।

मुझे लगता है कि जयपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इसी तरह की कोचिंग क्लासिस चलती हैं और सुविधाओं के अभाव में आग लगने पर कभी बच्चे ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाते हैं और कभी गैस रिसाव के कारण बेहोश हो जाते है। उनको अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जहां ऐसे कोचिंग सैंटर्स चलते हैं, वहां बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

(1600/VB/NKL)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्यगण, अभी बहुत-से सदस्यों को बोलना है, इसलिए आप अपने डिमांड्स को केवल दो सेंटेंसेज में रख दीजिएगा, नहीं तो सब लोग बोलने से रह जाएंगे।

श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली – उपस्थित नहीं।

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय, जो एक देशव्यापी समस्या भी है, पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।

हमें अत्यन्त दुख होता है, जब हम राजमार्गों पर चलते हैं, तो बेसहारा गोवंश भटकते हुए या सड़क पर कटे हुए मिलते हैं। यह देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। मेरा आमजन से निवेदन है कि गोवंश को बेसहारा न होने दें। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हर जिले में कम से कम 500 एकड़ जमीन दी जाए, जिस पर गो-संरक्षण और गो-संवर्धन केन्द्र स्थापित किया जा सके। वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा और जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगा। मेरी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। इससे जन-धन और किसानों को पशुधन का भी लाभ होगा।

धन्यवाद।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

I would like to draw the attention of this august House towards a pressing issue of severe sea erosion in my parliamentary constituency, Kasaragod. According to a study conducted by the Indian National Centre for Ocean Information Services, Kasargod is one of the districts in Kerala that is highly vulnerable to coastal erosion. The coastal areas of Kasaragod, particularly Choottad and Pamburuthi in Kannur, as well as Madakkara, Keezhoor, Ajanur, the Chithari River region, Meenirukk Centre, Kanwatheertha, Manjeswaram, Chembirika, and Thrikkannadu, are living examples. The Kerala Government cites a lack of funds, while the Central Government withholds timely assistance. As a result, the existing sea walls, which serve as protective structures, have proven insufficient to mitigate soil erosion.

So, I urge upon the Government to immediately release Central funds to prevent sea erosion in Kerala, particularly in my constituency, Kasaragod. I would also request time-bound compensation for and rehabilitation of the affected families. Thank you very much.

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) : माननीय सभापति महोदय, मैं शून्य काल के माध्यम से आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र जालना में, जालना से नांदेड़ तक द्रुतगति मार्ग जा रही है, जिसे समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण करने के लिए किसानों की कृषि भूमि, बाग, कुएं आदि का मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन यह मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के पुराने रेडी रेकोनर की दर से हो रहा है। जबकि इसकी अधिसूचना वर्ष 2021 में निकली है और इस कार्य को वर्ष 2024-25 में अवार्ड किया गया है। इसके कारण किसानों को उनकी संपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उनको पुराने दर के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। इसके कारण किसान असंतुष्ट हैं।

इस सदन के माध्यम से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि रेडी रेकोनर दर में प्रतिवर्ष 10 टके की बढ़ोतरी करके अनुशंसित दर के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। मुम्बई-नागपुर समृद्धि महामार्ग की महत्ता को देखते हुए किसानों के घर, कुएं, सिंचाई, पेड़ों, और फलों के बागान के लिए उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए। उनको मौजूदा लागत पर मुआवजा मिले और भविष्य में समुचित मूल्यांकन हो सके। इसके साथ-साथ, जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रावधान किया जाए। मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद।

(1605/SJN/VR)

*SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Every MP gets Rs 5 crore every year under MPLAD Scheme. Out of this amount of Rs 5 crore, Only Rs 4 crore could be utilized for carrying out developmental work. Out of the remaining Rs. 1 crore, an amount of Rs 10 lakh is taken back by the Union Government in the name of administrative expenses. Remaining amount of Rs. 90 lakh is also taken back by the Union Government in the form of GST. I must say that a parliamentary constituency consists of six Assembly constituencies and almost more than 20 lakh people live there. We are unaware as to how the execution of developmental work with just Rs 4 crore under MPLADS for one year could be done. Moreover, the enhancement of MPLAD fund can be done once in ten years. But this fund has not the enhanced during the last 11 years. Not only that, on behalf of all MPs, I request that this fund should be enhanced besides providing additional amount for paying GST. Thank you.

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, देश में बड़े पैमाने पर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन मेरा कोसी नदी का इलाका है, उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है, उसके पास सुपौल और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र भी है। वहां रेल लाइन के दोहरीकरण का एक इंच भी काम नहीं हुआ है, जबकि वहां से बड़े पैमाने पर रेल यात्री अन्य स्थानों पर जाते हैं। वहां बहुत सारी रेलगाड़ियां चल रही हैं। चूंकि रेल लाइन का दोहरीकरण नहीं हुआ है, इसलिए वहां भारी दिक्कत होती है। कई स्टेशनों पर रेलगाड़ी को रोकना पड़ता है।

* Original in Tamil

माननीय रेल मंत्री जी बड़े पैमाने पर रेल का विकास कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरा पूर्व मध्य रेलवे का इलाका है, जो हाजीपुर के अंतर्गत आता है। मानसी से सहरसा, पूर्णिया और सहरसा से सुपौल तक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम किया जाए। यह जनहित में है और इससे हम लोगों की परेशानी दूर होगी। माननीय रेल मंत्री जी, इस विषय पर जरूर ध्यान दें।

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय जी, मैं इस माननीय सदन को अत्यंत श्रद्धा और कर्तव्य भाव से अवगत कराने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में देशी गौ माता को जो स्थान प्राप्त है, वह अद्वितीय और अनमोल है। प्राचीन समय से ही गाय को भारतीय समाज में माता के रूप में पूजा जाता है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और औषधीय महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पहले था।

आज के समय में जब हम वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत को सहेजने की बात करते हैं, तो यह अत्यावश्यक है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर, उनको उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करें। गाय न केवल हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाती है, बल्कि वह कृषि, दूध उत्पादन और औषधीय लाभों के माध्यम से आर्थिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

महोदय, मेरा इस माननीय सदन से निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सशक्त कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दें कि संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के हम कितने प्रतिबद्ध हैं। गौ माता, जो सड़कों पर मारी-मारी फिर रही हैं, गौशालाओं और अभ्यारण्यों को आर्थिक सहयोग देते हुए, सभी राज्यों को निर्देशित करें। मोदी जी का संकल्प है कि प्राकृतिक खेती और श्री अन्न का संरक्षण हो, उसके लिए गौ माता का संरक्षण और संवर्धन अत्यावश्यक है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है, लेकिन बिहार में भी एक शेक्सपियर थे और वे भोजपुरी के शेक्सपियर थे। शायद भारत के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भोजपुरी के एक शेक्सपियर थे, जिनका नाम भिखारी ठाकुर था। वे नाई समाज से थे। उनका जन्म सन् 1887 में हुआ था। वे छपरा के एक दूरगामी गांव से बाहर निकलकर कोलकाता गए थे, जहां वे नाई का काम करते थे। पता नहीं, उनको वह काम पसंद नहीं आया और वे वापस लौटकर छपरा (बिहार) आ गए।

भोजपुरी में उनके बारे में जो कहा जाता है, उनका जन्म 18 दिसंबर, 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जुलाई, 1971 में हुई थी। बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा में पैदा हुए भिखारी ठाकुर जी एक चर्चित गीतकार, गायक, नाटककार, नृतक और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे कभी स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने एक जाने-माने कलाकार के रूप में उस समय 'बेटी बचाओ' का आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने उस समय सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने लेख और गीतों से आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी।

(1610/PC/SNT)

अपने फ़न के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले श्री भिखारी ठाकुर जी की करीब 84 वर्ष में मौत हो गई। श्री भिखारी ठाकुर जी अपनी बात समाज के सामने रखने में कभी डरते नहीं थे। हालांकि, वे पिछड़े समाज से थे, नाई जाति से थे। आज भी गांव-गांव तक उनकी लेखनी की, उनकी कला की और उनके गीतों की तूती बोलती है।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, आप अपनी मांग बताइए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : उनके नाटक इतने शानदार होते थे कि आज नहीं, बल्कि आजादी के पहले उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। … (व्यवधान) उन्होंने देश की सामंतवादी संस्कृति व गवई लोगों पर चढ़े हुए जातीय, समुदाय व रंग के खिलाफ गीत गाए थे और लोगों को जगाया था। … (व्यवधान) अत: ये थे हमारे श्री भिखारी ठाकुर जी। ऐसे लोगों को हम लोग स्मरण नहीं कर पाए।

लेकिन, यह मेरा सौभाग्य है कि आप वहां बैठे हैं और आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि बिहार का शेक्सपीयर, देश का शेक्सपीयर, भोजपुरी आवाज में बोलने वाला शेक्सपीयर हमारी धरती का था, जिस माटी से मैं जीतकर आता हूं। … (व्यवधान) मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूगा कि ऐसा व्यक्ति, जिसका ऐसा इतिहास है, जो हमारी भाषा का शेक्सपीयर है, उन्हें सम्मानित किया जाए। … (व्यवधान) सरकार जो भी उचित समझती है, चाहे पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, लेकिन, निश्चित रूप से उन्हें मरणोपरांत इनमें से किसी एक सम्मान से नवाज़ा जाए, यही मेरी मांग है। … (व्यवधान)

धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : माननीय सभापति जी, मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। खलीलाबाद, संत कबीर नगर से बहराइच के बीच जो नई रेल लाइन बन रही है। वहां मिट्टी का काम हो रहा है। इससे आसपास में इतना पानी जमा हो जा रहा है कि किसान परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे खेतों में जो फसल है, वह भी बर्बाद हो रही है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पटरी बनाने के साथ-साथ पानी निकालने की व्यवस्था भी सरकार तत्काल करे, जिससे किसानों और वहां के आम जन-मानस को लाभ हो सके।

धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवईनिया, गंगापुर, दामोदरपुर, छोटकी, बहोरनपुर, सारंगपुर, सरेमनपुर, लक्षुटोला और लालूडेरा, आरा मुफ़स्सिल प्रखंड के मनीराय का टोला, अचरज राय का टोला, बड़हरा प्रखंड के मंझौली, ख्वासपुर, नकनाम टोला और नथमलपुर और कोइलवर प्रखंड के ज्ञानपुर सहित दर्जनों गांवों में गंगा नदी के पानी से भयानक बाढ़ आई हुई है। इस कारण चार लोगों की पानी में डूबकर मौत हो गई है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी मांग बताइए।

… (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सर, मैं अपनी मांग बताता हूं। … (व्यवधान) जवईनिया गांव के सामने वर्ष 2022-23 में जब आरा-मोहनिया फोर-लेन बन रहा था, तब ठेकेदारों ने और सड़क बनाने वाली कंपनी ने भारी खुदाई की और वहां से मिट्टी और बालू ले गए। इसकी वजह से इस साल पूरे जवईनिया गांव के 300 घर और पिछले साल 69 घर गंगा में विलीन हो गए। पूरा गांव नक्शे से मिट रहा है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है।

… (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सर, मैं मांग करता हूं कि सड़क निर्माण कंपनी पर जांच बैठाकर उस पर उचित कार्रवाई की जाए, उनको दंडित किया जाए। जिन लोगों का घर गंगा नदी में डूब गया … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है।

… (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सर, मुझे बस पांच सेकेंड और दे दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, डॉ. हेमांश जोशी जी।

… (व्यवधान)

डॉ. हेमांग जोशी (वडोदरा) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अतिआवश्यक आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। … (व्यवधान)

यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यातायात को संभालने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और संचालनशील है। किंतु, आवश्यक अधोसंरचना एवं अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बावजूद इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, वडोदरा हवाई अड्डा केवल वडोदरा जिला ही नहीं, बल्कि गुजरात के मध्य एवं दक्षिण मार्गों में कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे आनंदखेड़ा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद एवं भरुच को भी सेवाएं प्रदान करता है। यह क्षेत्र औद्योगिक, शैक्षणिक और आदिवासी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। … (व्यवधान)

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स बढ़ाई जाएं। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी के जमाने में यह देश के सबसे पहले हवाई अड्डों में से एक था। … (व्यवधान) हमें वडोदरा के उस स्वर्णिम काल को फिर से वापस लाना है। … (व्यवधान)

धन्यवाद।

(1615-1620/SPS/AK)

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन और सरकार का ध्यान इस देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किए गए आशा कार्यक्रम को पूरे 20 साल हो गए हैं। वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के महान उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।

महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि 20 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमारी आशा कार्यकर्ताएं सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित हैं। उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और भविष्य के लिए कोई आर्थिक गारंटी भी नहीं है।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप अपनी मांग बताइए।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, देश के अलग-अलग राज्यों में उन्हें अलग-अलग मानदेय मिलता है। इनके संबंध में मेरी चार मांगें हैं। मेरी मांग है कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ताओं के लिए 'सेम रूल, सेम पेमेंट' का सिद्धांत लागू किया जाए और उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाए। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाए। सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए। ... (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। त्रिपुरा में उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में उनाकोटी नाम से एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें एक कम एक करोड़ देवी-देवताओं की मूर्ति बनी हुई हैं। यह 8वीं और 9वीं शताब्दी की धरोहर है और इसका रखरखाव एएसआई के पास है, लेकिन एएसआई इसके रखरखाव में सही ढंग से काम नहीं करता। जब त्रिपुरा सरकार ने इसके डेवलपमेंट के लिए फण्ड दिया और काम करने की कोशिश की, तो एएसआई इसमें बाधक बनता है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि यह हिन्दुओं और सनातन की बड़ी धरोहर है, इसको बचाने के लिए सौ करोड़ रुपये के आस-पास एक पैकेज बनाकर वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक किलोमीटर की फोर लेन रोड बनाने के लिए, वहां कैफेटरिया और बाकी सब सुविधाओं के लिए दिया जाए। इसके साथ ही वहां लाखों टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था हो करें। वर्तमान में एएसआई का ऑफिस नॉर्थ-ईस्ट के मिजोरम में है। वहां 90 परसेंट ऐतिहासिक धरोहरें त्रिपुरा में हैं, लेकिन ऑफिस मिजोरम है। वे मिजोरम से जाकर वहां देखभाल नहीं करते हैं। मैंने कई बार यह मुद्दा उठाया है कि इस ऑफिस को मिजोरम से परिवर्तित करके त्रिपुरा में किया जाए, ताकि वहां की धरोहरों की उचित देखभाल और विकास हो सके।

*SHRI K. GOPINATH (KRISHNAGIRI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. After raising my hands for the last 2 hours requesting for an opportunity to speak, now you have permitted me to speak at last. First of all, I thank you for this opportunity. My Krishnagiri Parliamentary Constituency is the fastest growing constituency of our country. On one side we have Karnataka and other side we have Andhra Pradesh. There are more than 2000 industries which are engaged in manufacturing sector. Approximately Rs. 500 to Rs. 600 Crore worth flowers are being exported to foreign countries from Krishnagiri. But there is a long pending request for a rail route between Bangalore and Jolarpettai via Hosur and Krishnagiri. We have been raising this demand for so long in this august House. I had even met the hon. Minister for Railways and handed over a letter in this regard. I request the government, through you Sir, to announce in the forthcoming budget, about the laying of a new railway line between Bangalore and Jolarpettai via Hosur and Krishnagiri. Thank you for this opportunity. Thank you. Vanakkam. Jai Hind.

#SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Thank you, Chairperson Sir. Every day, we are witnessing something akin to a theatre being enacted in this House, and this theatrics is performed by none other than the All India Trinamool Congress MPs. In West Bengal, Bengali women are being attacked, raped, and murdered. The state government has failed to protect the honour of the Bengalis. I know that whenever elections occur, many people will once again lose their lives. I demand that government jobs be given to the families of the victims. The hon. Chief Minister, Mamata Banerjee, has also indulged in theatrics, which are nothing but part of a grand drama designed to fool the people. Bengalis are living in hunky-dory conditions. We, the Bengalis, will progress under the leadership of our hon. Prime Minister. But under the patronage of the hon. Chief Minister of West Bengal, people are being murdered every day. The hon. Governor of Haryana, Shri Ashim Kumar Ghosh, is also present in West Bengal.

These people engage in theatrics in the House, while back in West Bengal, murders are taking place under their watch. These killings must stop. If someone is murdered, there must be a provision to provide a government job to a member of the victim's family. Thank you.

श्री मोहिब्बुल्लाह (रामपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं।

सर, मेरे जिले में कई लोगों की मौतें इसलिए हो चुकी हैं कि उनकी दुकानों को, जो 50-50 साल से थीं, उनके पास में 60-70 साल पुराने नक्शें भी मौजूद थे, तब भी उन दुकानों को तोड़

* Original in Tamil

Original in Bengali

दिया गया। रामपुर म्यूनिसिपैलिटी, नरपत नगर में और इसी तरह से पूरे देश में अतिक्रमण को हटाने के नाम से खास तौर पर मुसलमानों की दुकानों को, उनकी इबादतगाहों, मस्जिदों तथा मदरसों को तोड़ा जा रहा है। यह बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से जिन-जिन सरकारों द्वारा देश में यह काम किए जा रहे हैं, मैं यह अपील करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। इससे देश की एकता और अखंडता को सख्त नुकसान पहुंचता है। देश की सरकारों का काम रोजगारों को देना है, न कि गरीबों को मिटाना और उनके कारोबारों को उजाड़ना है। अगर कहीं सड़कें चौड़ी भी की जा रही हैं तो पहले उनको बसाया जाये। अगर उनको बसाया नहीं जाएगा तो उनके बच्चे और हमारे शहरी भूखे मरने लगेंगे।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे कुशीनगर के बड़े गंभीर मुद्दे को रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वर्तमान समय में हमारे कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लोक सभा के इलाके, गांव, टोले, मजरे के छूटे व वंचित क्षेत्र के विद्युतीकरण की सुविधा को पूर्ण करने के लिए आज संचालित किया जा रहा है। मैंने कुशीनगर में इसका शुभारंभ भी बड़े जोर-शोर से किया था। लेकिन जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ा तो हम लोगों के संज्ञान में आया कि सर्वे के द्वारा जितने भी कार्य आरडीएसएस योजना से लिए गए हैं, अभी 250 ऐसे गांव हैं, टोले के इलाके हैं, जो विद्युतीकरण की सुविधा से अभी भी वंचित हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि आरडीएसएस योजना के लिए एक बार पुन: सर्वे करवा कर वंचित इलाकों में भी विद्युतीकरण की सुविधा दी जाए।

*SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Hon. Chairman Sir, thank you.

In Maharashtra, the number of farmers suicides cases is increasing day by day due to infertility of land and farm loan burden. This number is alarming and the Government is totally indifferent. During election campaign, it was promised by the ruling coalition to declare a loan waiver for farmers in their manifesto.

The Chief Minister of Maharashtra is not ready to fulfill this poll promise. He is not even ready to comment on it. Hence, I would like to request our Prime Minister Shri Narendra Modi to instruct Shri Devendra Fadanvis to declare a loan waiver for the poor and distressed farmers of Maharashtra. I am sure he cannot defy his orders.

Thank you.

---

* Original in Marathi

(1625/RAJ/SM)

*SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. We have been timing and again raising several issues, particularly about railway projects pertaining to our constituencies. I requested for “one minute” stoppages for several trains and introduction of new train services in certain routes. These are some of the demands pertaining to my Thanjavur parliamentary constituency. But the Union Government is not paying heed to the demands of Opposition MPs like me. I am requesting the hon. Minister of Railways once again that ‘one minute’ stoppages should be provided for trains between Tambaram-Shengottai; Tambaram-Rameswaram in Athiramappattinam and Peravurani. All the trains passing through Athiramapattinam and Peravurani should have a stoppage for at least one minute. Similarly, Mannargudi-Jodhpur train should have a stoppage at Needamangalam. Our Railway Minister takes pride in Vande Bharat trains. I request Hon Minister for Railways to introduce Vande Bharat train services between Thanjavur and Chennai besides Thanjavur and Bengaluru.

Thank you.

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : सभापति महोदय, मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं। लातूर में एक रेलवे कोच फैक्ट्री लग चुकी है जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी ने डेढ़ साल पहले किया था, लेकिन अभी तक वहां प्रोडक्शन नहीं शुरू हो पाया है। इसका क्या कारण है? वहां जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू किया जाए। लातूर के लिए पुणे और हैदराबाद से वंदे भारत ट्रेन चालू की जाए। यह हमारी मांग है। लातूर से नॉर्थ इंडिया के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां से जल्द से जल्द लॉंग रूट की ट्रेन नॉर्थ इंडिया के लिए चालू की जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं।

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Thank you hon. Chairman, Sir. I rise today to draw the attention of this esteemed House to a critical and urgent matter concerning my Kanyakumari constituency.

Sir, due to sea erosion, the infrastructure has been damaged vastly. I request the Government to allocate immediate funds for comprehensive sea erosion control measures including construction of sea wall, groynes and other scientific interventions to safeguard the coastline; restoration and strengthening of damaged road networks to ensure uninterrupted connectivity for fishing villages; rehabilitation support for affected families to protect their homes and belongings from further destruction; long-term sustainable development plans

* Original in Tamil

to support the fishing communities in adapting to the changing environmental conditions.

Sir, I appeal to the Government to treat this issue of constructing the sea walls on war-footing and ensure that the necessary funds and resources are provided without any delay. Thank you.

1629 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Sir, India today is an undisputed leader in global IT exports. From about 23 billon US dollars in 2005, our exports have grown to nearly 200 billion US dollars in 2025. It directly employs 50 lakh Indians and supports millions in ancillary services.

A significant part of this success is rooted in Special Economic Zone. Out of 351 Special Economic Zones, nearly 226 SEZs are dedicated to IT and IT-enabled services. Cities like Bengaluru, Hyderabad, Gurugram, Pune and Chennai owe much of their global stature to these thriving IT clusters.

(1630/GM/NK)

While we have built world-class office spaces inside these SEZs, we have left behind the very people who power them. Across India's tech corridors, lakhs of young professionals, many of them first-generation white-collar workers, migrate in search of opportunity. But what they encounter is a harsh reality: sky-high housing costs, long hours of commute, and daily struggles to balance work and life. In Bengaluru, for example, housing near major IT corridors can consume 40 to 60 per cent of an average tech worker's salary. In Gurugram and Pune, it is a one and a half to two-hour daily commute. For women professionals, these challenges are not just about convenience, they raise safety, equity, and workforce retention concerns. The SEZ Act permits residential and social infrastructure in non-processing areas, yet there is no additional clarity, consistency, or urgency in implementation. As a result, developers remain hesitant and state approvals are patchy.

In China, Shenzhen, a small fishing village, has transformed into a 400-billion tech economy through integrated SEZ planning. The GIFT City in Gujarat has demonstrated integrated living and working spaces and has led to higher productivity, better retention, and improved quality of life.

I urge the Government of India and the Ministry of Commerce to issue clear national guidelines to enable residential housing within or adjacent to IT SEZs with uniform approval timelines, sustainability standards, and affordability norms. This is not merely a policy tweak, it is a structural reform that will ease urban congestion and lower carbon emissions through walk-to-work models, improve retention and safety, especially for women, strengthen India's competitiveness in attracting global investment and talent. If SEZs are to remain centres of economic excellence, they must become centres of dignity, inclusivity, and liveability. Let us not allow the people behind India's digital success to be left behind in the very cities they are building.

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों ने लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर बोलने के लिए आज नाम दिए हैं, उन्हीं को कल बोलने का अवसर मिलेगा। जिन्होंने आज नाम दिए हैं, उनको ही कल अवसर मिलेगा। कल नाम देने वालों को अवसर नहीं मिलेगा। लॉटरी वालों पर भी विचार करेंगे कि उन्हें समय देना है या नहीं। आज सभी को बोलने का अवसर दिया है, कल भी देंगे।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Dr. Nishikant Dubey	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shrimati Priyanka Gandhi Vadra	Shri K.C. Venugopal Shri Hibi Eden Shri V. K. Sreekandan Adv. Dean Kuriakose Adv. Adoor Prakash Shri Kodikunnil Suresh
Shri Harish Chandra Meena	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Jagdambika Pal

Shri Neeraj Maurya	Shri Jagdambika Pal
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare
Shri Dharambir Singh	Shri Chandra Prakash Joshi Shri Sudheer Gupta
Shri Ujjwal Raman Singh	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar
Shri K.C. Venugopal	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri B. Manickam Tagore Adv. Francis George Shri Hibi Eden Shri V. K. Sreekandan Adv. Dean Kuriakose Shrimati Priyanka Gandhi Vadra Adv. Adoor Prakash Shri M. K. Raghavan Shri Benny Behanan Shri N. K. Premachandran
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Hibi Eden Shri V. K. Sreekandan Adv. Dean Kuriakose Shrimati Priyanka Gandhi Vadra Adv. Adoor Prakash Shri M. K. Raghavan Shri Benny Behanan
Shri Kirti Azad	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Rajkumar Chahar	Shri Jagdambika Pal
Shri Manish Jaiswal	Shri Shrirang Appa Chandu Barne Dr. Prashant Yadaorao Padole

Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri Sunil Dattatrey Tatkare	Shri Shrirang Appa Chandu Barne Dr. Prashant Yadaorao Padole
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Arvind Ganpat Sawant	Dr. Prashant Yadaorao Padole Shrimati Supriya Sule
Dr. Namdeo Kirsan	Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar
Shri Anurag Singh Thakur	Shrimati Smita Uday Wagh
Dr. Nishikant Dubey	Shrimati Smita Uday Wagh
Shri Dilip Saikia	Shrimati Smita Uday Wagh
Shri Amrinder Singh Raja Warring	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Karti P. Chidambaram	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Hibi Eden	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Adv. Francis George	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Balya Mama Suresh Mhatre	Shrimati Supriya Sule
Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil
Shri Balwant Baswant Wankhade	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Dhairyasheel Rajsinh Mohite-Patil Shri Nilesh Dnyandev Lanke
Shri Ravindra Dattaram Waikar	Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Shrirang Appa Chandu Barne Shri Naresh Ganpat Mhaske
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	Shrimati Anita Subhadarshini
Shri Laxmikant Pappu Nishad	Shri Jagdambika Pal
Shri Rajiv Pratap Rudy	Shri Jagdambika Pal
Shri Vijay Kumar Dubey	Shri Jagdambika Pal

(1635/IND/RCP)

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

1635 बजे

माननीय अध्यक्ष : मणिपुर से संबंधित सांविधिक संकल्प को पारित करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस सभा ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 अप्रैल, 2025 की बैठक में किया था। अनुच्छेद 356 (4) के अनुसार इस अनुमोदन की वैधता 6 माह तक होती है।

अनुच्छेद 356 (4) के परंतुक के अनुसार राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने तक बढ़ाना हो, तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में इस सांविधिक संकल्प को पारित किया जाना आवश्यक है।

कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ है कि मणिपुर बजट और मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक पर यह सभा दो-दो घंटे चर्चा करेगी। माननीय सदस्यों को मणिपुर के विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। फिर भी अगर सभा की सहमति हो तो संक्षिप्त चर्चा आज करा देते हैं। माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में बोलेंगे ताकि छह बजे आज की कार्यवाही समाप्त की जा सके।

माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष जी, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

1636 hours

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Speaker Sir, I rise to speak on the discussion and voting on the Demands for Grants (Manipur) for the year 2025-26 and introduction, consideration and passing or return of the related Appropriation Bill and the Resolution seeking approval of extension of President's Rule imposed through Proclamation issued by the President on 13th February, 2025 under article 356(1) of the Constitution of India in relation to the State of Manipur with deep pain and anguish.

1636 hours (Kumari Selja *in the Chair*)

My heart is very heavy as I speak not only as a Member of Parliament but as a human being watching the continued suffering of our brothers and sisters in Manipur. What has happened there, and what is still happening, is not just a law-and-order problem; it is a complete collapse of governance. That collapse lies squarely on the inefficiency of the BJP-led Government, both at the Centre and in the State.

Manipur which literally means 'a jewelled land' has been reduced to ashes. A State once known for its green hills and harmony now bleeds red. The sounds of nature have been replaced with the cries of mothers who watched their children killed, with the screams of women stripped of their dignity and with the silence of a Prime Minister who chose not to speak when the people needed him most. Let us call this, what it truly is, a man-made disaster caused by the inefficiency, apathy and failure of this Government.

The violence in Manipur began in 2023. Instead of acting swiftly to de-escalate, the Government allowed the situation to spiral into uncontrolled violence, bloodshed and chaos. Where was the Central Government when the State was burning? Where was the Union Home Ministry which is constitutionally responsible for maintaining law and order in such situations? What we saw was not just a slow response; it was no response. In fact, the inaction of the Government enabled the violence. It gave room for mobs to attack, for homes to be burnt, and for over 60,000 people to be displaced. Over 200 lives were lost, and nearly 500 churches were demolished, and yet this Government waited for months to even speak a word! This silence is not accidental; it is deliberate. It is a reflection of the BJP's lack of political will and

absence of administrative efficiency, especially when it comes to the North-Eastern part of India.

This is the same Government that never fails to chant "*Bharat Mata ki Jai*" in the Parliament. But what about *Bharat Mata's* daughters in Manipur, who were stripped, paraded and assaulted by mobs? A former soldier, whose wife was among the victims, said with deep pain, "I served the country, but I could not protect my wife." What kind of country are we building where our soldiers feel helpless and our women are not safe?

The Prime Minister, who often speaks for hours on less important matters, took months to say just a few words after a shocking video from Manipur came out. Even then, all he said was that it was shameful. When the Union Government controls the paramilitary forces, controls the intelligence machinery and has the power to intervene in serious internal conflict, why did they do nothing?

(1640/PS/KDS)

This was not just a delay, but it was a complete failure to do their duty. It showed a serious lack of leadership.

Madam, the Manipur Government instead of protecting its people, has worsened the situation through internet shutdowns, curfews, and brutal police actions. On June 12, 2023, the Rapid Action Force vandalised private vehicles. This act was caught on CCTV. Later, three RAF personnel were caught trying to burn down a store. Is this the Government's definition of peacekeeping?

People have been cut off from the world, with internet shutdowns lasting over two months. In a democracy, this is unacceptable. It hides what is really going on, stops victims from speaking out, and clearly shows that the Government cares more about controlling the story than actually solving the problem.

Let me remind the House that even the United Nations raised an alarm in September 2023. The UN experts cited serious human rights violations -- extra-judicial killings, sexual violence, forced displacement, and torture -- and slammed the inadequate humanitarian response of the Indian Government. Even when the international community sees and reacts, why does the Indian Government turn away?

The pattern of inaction is not limited to Manipur. Just recently, two nuns from Kerala were arrested in Chhattisgarh on baseless charges of forced conversion. They were harassed at a railway station and the State Government remained mute. Again, it is the minorities and the marginalised who suffer, and again, the BJP-led Governments either look away or support the actions of the right-wing groups.

And now, let me bring the attention of the House to a deeply ignored truth. In our country, most educational institutions are run by the Christian community. It is through these schools that most of the people there have learnt their first alphabets. The Christian community has always upheld values of love, service, and brotherhood. And yet, today, they are being hunted, humiliated, and accused, while the current Government offers protection to their attackers.

Let me ask one thing to those sitting in the House. Can any one of you honestly say that the schools you studied in forced you to convert your faith? In Kerala, our educational success is rooted in a simple concept: “A school beside every church”. This is how every village was given an access to education beyond race, caste, and belief. It was a vision, not violence, that uplifted our State.

When the Government turns a blind eye to this truth, it cannot hide behind slogans. It becomes an act of betrayal; a betrayal of the Constitution, of justice, and of humanity. And that betrayal is what the people of Manipur, and many others across this country, are enduring right now.

Thank you.

(ends)

1643 बजे

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, हमें आज यह संकल्प लाना पड़ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 356 में आपात स्थिति में जब किसी राज्य का शासन राज्य सरकार द्वारा न चल पाए, तब इसका प्रयोग करने का उपबंध है। निश्चत रूप से मणिपुर में जो स्थितियां बनी हैं, वे काफी गंभीर हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जब भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, तो जिस तरह के शब्दों का वे चयन करते हैं और अहंकारमय भाषण देते हैं, निश्चित रूप से वही कारण है, जिस वजह से हम मणिपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं 'एक देश, एक चुनाव' और दूसरी तरफ एक छोटे राज्य में, जहां केवल दो सांसद चुने जाते हों, वहां काफी दिनों तक जिस तरह की स्थितियां बनीं, जिस तरह से महिलाओं के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ।

(1645-1650/CS/SMN)

महोदया, हम लोगों ने जो वीडियो देखा, निश्चित रूप से वह शर्मनाक वीडियो था और उसको देखकर आँखों में आँसू आने की स्थिति बनी है। एक सभ्य समाज में इस तरह का वातावरण देखने का निश्चित रूप से अवसर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर ऐसी स्थितियाँ पैदा कीं। काफी दिनों तक माँग करने के बाद भी उस सरकार को भंग करने का काम नहीं किया गया। वहाँ उस समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करने का काम किया गया। आज जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 6 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी हम वहाँ की शांति व्यवस्था को बहाल नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। निश्चित रूप से आज यह सरकार केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। यह देश रहे या न रहे, इनका वोट बैंक बना रहे, ये केवल इस धारणा के साथ काम करते हैं। ये इस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसी के कारण हम वहाँ पर, एक छोटे से राज्य में चुनाव कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से हमारी यह चाहत है कि सरकार केवल वोट बैंक की दृष्टि से काम न करते हुए लोगों की भावनाओं को समझते हुए वहाँ शांति का वातावरण पैदा करने का प्रयास करे और जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके वहाँ के लोगों को अवसर देने का काम करना चाहिए। हमें देश सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलना चाहिए कि हमारा देश सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का कैसे ज्यादा वोट बढ़ेगा, जब हम केवल इस सोच से काम करते हैं, चाहे कहीं पर भी जब हम इस सोच से काम करते हैं तो यह देश के लिए घातक होता है। भारतीय जनता पार्टी की उसी नफरत की सोच के कारण आज ये परिस्थितियाँ हैं। अभी कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी यह बात आयी कि चाहे वह 1965 की लड़ाई रही हो, चाहे 1971 की लड़ाई रही हो, चाहे 1991 की लड़ाई रही हो, उस समय हमारे देश के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े नजर आते रहे हैं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की नीति है, उसके कारण चाहे हमारी विदेश नीति हो, वह पूरी तरफ से फेल हुई है और उसी के कारण मणिपुर आज भी इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी यह माँग है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए। वहाँ के लोगों से बातचीत करके, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करके वहाँ की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देश सर्वोपरि है, अगर हम इस नीति के तहत काम करने का काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम वहाँ पर चुनाव करा पाएंगे। ऐसा हो जायेगा तो हमें बार-बार यह संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मेरा विचार है। मेरा कहना है कि इस आधार पर हमें काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

(इति)

1648 hours

*DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Hon. Chairperson Madam. As a representative of my party the All India Trinamool Congress, I am strongly opposing the resolution to reinstate Article 356 in Manipur which will further push the people of the state into darkness. Manipur has been burning for more than two years. On the instructions of our Honorable leader and Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee, as a part of the team of All India Trinamool Congress, I went to Manipur and saw the deplorable condition. Yet the Prime Minister didn't visit Manipur even once. He is touring the world but didn't feel the need to visit Manipur. Terrorists are infiltrating across our international borders. We have witnessed terrorists entering our land in April and killing 26 people. Similarly, terrorists from Myanmar are entering Manipur with Arms and drugs. There is sufficient evidence of their involvement in subversive activities as well. These border areas are not being properly maintained. President's rule can't be a permanent solution. This is an emergency provision of the constitution- which is designed to be temporary. Its repetition is a mockery of democracy, an insult to the rule of law, and an admission of the utter failure of the central government. It is the ideal of a democracy to establish a government through electoral process. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (KUMARI SELJA): Hon. Member, please do not interrupt. Please sit down.

… (*Interruptions*)

* Original in Bengali

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. You cannot interrupt like that.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not interrupt like that.

… (*Interruptions*)

*DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): If we employ Article 356 in the state, that doesn't reflect the people's consensus. … (*Interruptions*) Manipur was recognized as a state in 1972. The Bharatiya Janata Party government was established there through 2 elections in 2017 and 2022. The government has been an utter failure in that state. … (*Interruptions*) We have seen the Archeological Survey of India report. The Meitei community are 53 per cent of the population in the state but they only own 11 per cent land. The Kuki and Naga indigenous communities live in the hills, they possess hilly lands. … (*Interruptions*) The cultivation of Opium is rising there. During the tenure of Bharatiya Janata Party in 2017 and 2022, the Opium cultivation has risen from 1853 acres to 6743 acres. The BJP government couldn't stop Opium Cultivation. According to the United Nations report, the Government is unable to stop the drugs, opium, arms and terrorists infiltrating from Myanmar. … (*Interruptions*) The law-and-order situation is in turmoil. This is an embarrassment for India. The first and foremost duty of the country is to provide security to their citizens. More than 200 people have died.

HON. CHAIRPERSON: Please sit. Kakoli ji, please wait for one minute.

… (*Interruptions*)

---

* Original in Bengali

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Madam, I need the real protection. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I know. I think, the whole House needs protection.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly take your seat. The Minister will answer. Please sit down. You can go and talk to the Minister.

Kakoli ji, please continue.

… (*Interruptions*)

*DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Women have been paraded naked in the streets. We have witnessed it. … (*Interruptions*) More than 60000 people have lost their homes and are living in the relief camps. I have visited and seen pregnant women delivering their babies in the relief camps. There has been a scarcity of medicine and food. Homes are being burnt down. Temples and Churches being burnt down. There is no brotherhood amongst the communities.

The Bharatiya Janata Party government is to be entirely blamed for this condition. The President's rule isn't the solution. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. This cannot go on.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kakoli ji, please wait a minute.

… (*Interruptions*)

* Original in Bengali

(1655/UB/MY)

HON. CHAIRPERSON (KUMARI SELJA) : Kakoli ji, you can start again.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, this cannot go on like this. Your mic is off.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Who are you speaking to?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is very regrettable.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will adjourn the House. You will start later.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned till 5.30 pm.

1656 hours

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past Seventeen of the Clock.

(1730/NKL/GG)

1730 बजे

लोक सभा सत्रह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प – जारी

1730 बजे

माननीय अध्यक्ष : डॉ. काकोली घोष दस्तीदार।

*DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Honourable Speaker Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I stand in the Parliament with deep sorrow and with a demand for justice to strongly oppose the proposal to re-impose President's Rule i.e. Article 356 in Manipur and to extend its duration.

I have seen with my own eyes the kind of social justice that has been trampled on and how people are dying in Manipur over the last few years. On behalf of the All India Trinamool Congress, we have come to this consensus that we cannot support the re-deployment of Article 356 in any way. On the instructions of our Honorable leader Mamata Banerjee, I myself went to Manipur in 2023. We saw how human rights were violated and how people were killed there. There are people from the Meitei community who are Vaishnavites, and just as their temples have been burnt; the churches of the Kuki community who are Christians have also been burnt. There is no development there, development has come to a standstill.

The President's rule was imposed on the state. But this can't be the long-term solution. This is an emergency provision of the constitution- which is designed to be temporary. Its repetition is a mockery of democracy, an insult to the rule of law, and an admission of the utter failure of the central government. I want to say that Manipur was recognized as a state in 1972. And the Bharatiya Janata Party government was established there through 2 elections in 2017 and 2022. But in the subsequent stage, the former Chief Minister of the State and the United Nations expressed concern on Manipur's deteriorating condition post-2022. In the hills where the Kuki community lives,

* Original in Bengali

from 1853 acres, opium is now cultivated in 6,743 acres. And how are these drugs, weapons, and terrorists entering from the neighbouring country Myanmar?

The long-standing unrest in Manipur, and the horrors we have witnessed, should have prompted the Honorable Prime Minister to go there at least once so that he could help the people. Therefore, we want a government to be established there through a democratic electoral process so that democracy can be re-established.

More than 60,000 people are in camps, 5,000 houses have been burnt, over 200 people have died. Women have lost their dignity and respect. There is no progress in Manipur today. Therefore, instead of re-instating Article 356, elections should be held within 3 months to establish an elected Government so that peace can be restored and development can take place there.

I have expressed my support for establishing a peaceful coexistence between the Meitei and Kuki communities as in the past.

Thank you.

(ends)

(1735/VR/YSH)

1735 hours

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Thank you, Chairperson, for this opportunity. I just wanted to remind the House that the first time when the Motion for Imposition of the President's Rule was introduced after a gruelling session of discussions, it seemed that all the representatives from the State did not get a chance to speak. Being a representative of the people of my State, I hope that the Chair will give me adequate time to express the sentiments of the people.

Sir, just as we had a long discussion on Operation Sindoor, I expect that the House will discuss it given the gravity of the situation in Manipur over the last one year. As terrorists came from Pakistan and created havoc and tried to divide this country and provoked us on communal lines, if my memory serves me well, the Union Home Minister on 9th August, 2023 on the floor of the House said that the crisis in Manipur was caused by the influx of illegal immigrants. Similarly, the intelligence agencies have flagged off the involvement of armed groups from Myanmar in the crisis in the State. So, it is like what we had experienced in Pahalgam in some sense. Ironically, Manipur is also called a little paradise just as Kashmir is called a paradise on earth. The only difference is that national attention is given to what happened in Kashmir and not to what happened in the State of Manipur.

Sir, our existence is at the periphery and a marginal existence has been reaffirmed, time and again, creating a sense of alienation and humiliation to the people of the State. Let me give an example of the recent times. When Shri Ratan Thiyam, the doyen of Indian theatre, expired, neither a single word came from this House, nor the Prime Minister, who had expressed similar condolences when other artistes expired uttered a word. This is a shameful reminder that how marginal Manipur is. However big you are and whatever role you have played in this country, I do not need to repeat the stature of Ratan Thiyam. He was mourned globally. Luckily, some of the Chief Ministers from distant States did mourn his demise.

Now, let me put two or three issues here about the extension of the President's Rule. There are a couple of myths that we need to know and, through you, I would like to inform the House as well as the country and the

entire world that when the Union Government takes over a State under Article 356, it is on the assumption that the constitutional order is not working, and the law and order has gone beyond what it should be normally. But the fact of the matter is that the imposition of the President's Rule in Manipur is not occasioned by such a concern. It is to save that embarrassment for the Ruling Party. If they had to do it, they would have done it a long time back. The Supreme Court in a couple of months after the initial period of the crisis had said that the law and order in the State had completely gone out of control and the constitutional order was not in order. But they did not do it at that time. So, that is the first myth that we need to understand. This is not to restore constitutional order but to save the embarrassment that the Ruling Party was about to face in that month.

Secondly, the Union government has been hand in glove with the then State Government in creating havoc in the State. Let me cite some of the examples. The Chief Minister had said that whatever he did was on the advice of and with the consent of the Prime Minister, Modi and the Home Minister, Mr. Amit Shah. Similarly, the Home Minister said on the floor of the House that the Chief Minister is cooperating with us.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तथ्यों के बिना सदन में बात नहीं रखनी चाहिए।

… (व्यवधान)

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Sir, let me continue. I do not want to waste the time of the House.

The ex-Chief Minister again said that the valley would be under him and the Home Minister would take care of the hills. Such a thing has never happened. The subversion of the federal policy and constitutional order was already there. *....(Interruptions)*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, ये क्या बोल रहे हैं? यहां पर इस बात से क्या मतलब है? … (व्यवधान)

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): The Union Home Minister was dictating terms to the then State Government in terms of appointing and changing officials as if Article 257A was operational. It happened so much so that some of the officers of the Central Security Forces bluntly said on record that they did not take orders from the State Government but from the Union Government.

(1740/PBT/STS)

Such a subversion has happened right now through the collusion between the State Government and the Union Government. Therefore, what we need to know is that the nature of the President's Rule … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : रूल क्या है?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, रूल 353 के अनुसार वहां के गर्वनर का रूल है, … (व्यवधान) वे वहां क्या कर रहे हैं, उसको रूल 356 के तहत यहां डिसकस नहीं किया जा सकता है। यही कंस्टीट्यूशन कहता है और रूल भी यही कहता है। … (व्यवधान)

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Let us first have a clarity that the President's Rule in Manipur was not imposed in order to recover a constitutional order. It was imposed because in collusion with the then State Government, the Union Government itself has subverted the constitutional order. They are creating that kind of a lawlessness for two years.

The other point regarding why we should not be extending the President's Rule is this. Given these reasons, we must also remember that Article 356 is supposed to be used in the rarest of the rare moments.

If I can recollect in this House, on 3rd of August, 1949, Dr. Ambedkar introduced Article 277A, which later on became Article 355, as a legal and moral premise for Article 356. We are supposed to use this very judiciously because rather than the President's Rule, the mandate of the people should govern the people. That was a clear position. There is a Supreme Court judgement on the Bommai Case as well as Sarkaria Commission had reminded us that these particular provisions should not be used for whimsical reasons. Therefore, instead of introducing this and extending this President's Rule in Manipur, which is almost illegimate morally in some sense, we should have a fresh mandate in the State of Manipur. Despite having a brutal majority, you are not able to form the Government. In collusion with that State Government and the Union Government, you have created this tragedy in Manipur since the last two years. I expect the House that instead of extension of this President's Rule, a JPC should be constituted, so that the people of Manipur do not feel neglected, we take care of what had happened, and fix the accountability.

I must remind again that the executive conduct must have some accountability in this House. Therefore, just as we discussed Operation Sindoor, just as we had long discussions on Constitution Amendment, I expect this House to have at least five to six hours of discussion on what steps can be taken in this House, so that all of us can have a healing process beginning from this House.

I would like to end my interventions by appealing to the rest of the country as well. We have suffered constantly this humiliation and the constant reminder that you do not matter. The crisis in Manipur is unprecedented. Our LoP has said it. You have never seen this challenge in the other Indian States.

The legitimate use of physical force has been challenged. Nowhere has it happened. The partition of 1947 is a living reality in Manipur today. The freedom of movement is not there. The Meiteis cannot travel on the national highways, just as the Kukis cannot. All the citizens should have access to freedom of movement. We are not able to have it. Therefore, I expect this House to be more serious rather than reducing this kind of extension to a mere formality and ritual.

The pain and suffering of the people of that State must be taken seriously. Insofar as the 19th State of this Union, this House must take it seriously, just as you have taken it seriously on the question of Pahalgam and that of any other issues in this country.

I, therefore, object to this extension of President's Rule and I demand that instead of this, please dissolve that Assembly and let us have a fresh mandate. The rule of the people and the will of the State must have the say rather than dictating terms, even if it is a small State.

Thank you, Mr. Speaker Sir.

(ends)

(1745/SNT/MK)

1745 hours

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Speaker Sir, *Vanakkam*. Thank you for allowing me to take part in this important discussion.

माननीय अध्यक्ष : आपको ज्यादा अवसर नहीं दिया है। केवल दो मिनट का समय दिया है।

मणिपुर वाले माननीय सदस्यों को समय के लिए टोका नहीं गया है।

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I am opposing the Resolution brought here to extend the Hon President's Rule in Manipur.

I start my speech opposing the resolution for extending the Hon President's Rule in the State of Manipur. As the voice of Hon Chief Minister of Tamil Nadu and as per the policy of my party Dravida Munnetra Kazhagam we want to register in this august House that we will always oppose the imposition of Hon President's Rule. People are aware of the fact that the then BJP led Government of Manipur and the then Chief Minister were the primary reason for all the riots that happened in Manipur. Nation is aware of the fact that similar to what BJP does in all other States of the country for their vote bank politics, they divided the people of Manipur on the basis of providing reservation. BJP was engaged in a false propaganda terming Kukis as migrants and drug sellers.

The Union Government should clarify in this august House that the reason for imposing President's Rule in Manipur during February 2025 and the reason for extending it for another six months now. What were the measures taken for restoring normalcy and peace in the State of Manipur during the last six months of President's Rule in Manipur? The Union government should explain. The number of CRPF soldiers put on duty in Manipur has been increased from 11 thousand to 21 thousand. Even then you are finding it difficult to restore peace in Manipur. You should explain in this august House about the measures undertaken for the welfare of the people of Manipur in a democratic manner. This Government should also clarify whether it intends to extend President's Rule, time and again, in Manipur. Union Government should take measures for resettlement of children and women displaced from their homes due to violence.

Thank you.

(ends)

* Original in Tamil

1748 hours

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I stand in support of this Resolution to extend the President's rule in the State of Manipur. I know it is a very hard decision. It is not an easy decision to implement President's rule in Manipur, but it is a very necessary decision. So, we stand in support of this.

By endorsing the extension of President's rule in Manipur, we are giving Manipur a chance to heal with dignity. We support this with total confidence in hon. Home Minister, Amit Shah ji, who has clarity of thought. Under his stewardship, we have seen how Jammu & Kashmir transitioned from a State of political deadlock and militancy to a relative calm and accelerated development. Five years back, till he came to the Parliament with the Bill about abrogation of Article 370, we used to think how '*ek desh*, *do pradhan*, and *do nishaan*' will work. But he has shown us and he has promised us in this House saying, 'We are going to repeal this; we will make sure that Jammu & Kashmir will be on the path of development'. In the discussion that has happened on Pahalgam also, he has mentioned very clearly how the militancy has come down, how terrorist activity has come down, and how stone pelting has also come down in Jammu & Kashmir in the last five years. A lot of development has also been happening in Jammu & Kashmir. This is the record of the hon. Home Minister.

Manipur is not just about law and order. This is about rebuilding trust in the Constitution, trust in the rule of law, and trust in the idea of India. And I say with pride hon. Home Minister has lived up to the trust. His decision is not an act of control; it is an act of courageous compassion ensuring that both Meitei and Kuki communities are heard, protected, and reconciled without fear and favour. I heard the hon. Member from Manipur. I request him to remember this moment not as a moment of Central intervention only, but as a moment of national healing enabled by a leader who does not look away when duty calls.

I thank and salute the hon. Home Minister for placing peace before politics, principle before partisanship, and Constitution above all. Thank you very much.

(ends)

(1750/ALK/VPN)

1750 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि मणिपुर की यह हिंसक घटना। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अन्नादुरई जी राष्ट्रीय नेता, लावू श्रीकृष्णा जी राष्ट्रीय नेता, ज्यादा राष्ट्रीय नेता मत बनिए। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : इन राष्ट्रीय नेताओं को बहुत-बहुत, धन्यवाद। इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे दिए हैं जिनका मैं उत्तर दूंगा तो उनको सुनने में खराब लगेगा। मेरा उत्तर जो भी होगा, यथार्थ की धरातल पर, सत्य का पाँव थामकर मैं वही बोलूंगा जो मणिपुर के लिए सही और सत्य है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कम समय में अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट का एक फैसला आरक्षण से संबंधित था। उसमें जो आदेश आया था और उसको लेकर जो बातें सामने आईं, उन्हें लेकर हिंसा फैली और वह हिंसा जातीय थी। यहां माननीय एंटो एन्टोनी साहब बोल रहे थे कि जैसे वहां दो धर्मों के बीच संघर्ष हुआ हो। मणिपुर में दो धर्मों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है और न अभी हो रहा है, जातीय हिंसा जरूर हुई थी। ... (व्यवधान)

यहां पर लालजी वर्मा साहब भी बोले, काकोली घोष मैडम भी बोलीं। वहां जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय से अभी तक मात्र एक हिंसा हुई, उसमें एक की जान गई और चार महीने के अंदर वहां एक भी मौत नहीं हुई। अकोइजम साहब बोल रहे थे कि वहां कोई शांति व्यवस्था नहीं है, क्या शांति व्यवस्था का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? यहां अन्नादुरई साहब बोल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन क्यों बढ़ाया जा रहा है? मैंने कहा कि वहां शांति व्यवस्था बहाल हो रही है, चार महीने में एक भी मौत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अभी राष्ट्रपति शासन जरूरी है, इसके लिए मैं आपके पास निवेदन लेकर आया हूं।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट में हुए विकास, विश्वास, शांति और स्टेबिलिटी की चर्चा एक मिनट में करना चाहूंगा। माननीय मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में 70 बार नॉर्थ-ईस्ट का दौरा किया और इसके फलस्वरूप पिछले दस वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों का ऑलराउंड विकास हुआ। हम नॉर्थ-ईस्ट के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन को पांच क्षेत्रों में देख सकते हैं - कनेक्टिविटी की क्रांति, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग, सशक्तिकरण और समावेशी विकास, युवाओं और महिलाओं का कल्याण, शांति और स्थिरता। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाया गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिनको हर बात पर हंसने की आदत है।

(1755/SK/AK)

कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिनको हर बात हंसने वाली लगती है। जब उनके नेता बोलते हैं, उस समय भी उन पर हंसते रहते हैं। पता नहीं, उनकी हंसी में व्यंग्य होता है या कौन सा राज छिपा होता है।... (व्यवधान)

महोदय, इसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर की शांति में स्टेबिलिटी हुई है। यूपीए सरकार के समय में 11,327 हिंसक घटनाएं हुई थीं, एनडीए सरकार के समय में मात्र 3511 घटनाएं दर्ज की गई है यानी 69 प्रतिशत कमी आई है। हताहत सुरक्षा बलों की संख्या पहले 456 थी, जो अब घटकर 135 हो गई है यानी 70 प्रतिशत की कमी आई है। हताहत नागरिकों की संख्या घट गई है यानी 85 प्रतिशत की कमी आई है। ... (व्यवधान) इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक 10,600 विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। नार्थ-ईस्ट में वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच कुल 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं इसलिए आज नॉर्थ-ईस्ट में शांति दिखाई देती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब वहां शांति व्यवस्था है। हिंसा की घटनाओं में जो कमी आई है, मैंने इसका उल्लेख किया है।

इस अवधि में मणिपुर में 2500 से ज्यादा हथियार, 1900 से ज्यादा विस्फोटक और 30,000 से ज्यादा गोला-बारूद बरामद किए गए। कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। संवाद प्रक्रिया के दौरान दोनों समुदायों के मतभेद दूर कर चिरस्थायी शांति की बहाली के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहां डॉ. घोष मैडम ड्रग्स समस्या के संबंध में बोल रही थीं। मणिपुर को नशा मुक्त करने के लिए नशे के व्यापार में लिप्त नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मणिपुर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहां जो लोग नशे के आदी हो गए हैं, इससे मुक्त हों, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, मैं एक-दो घटनाओं को जरूर याद कराना चाहूंगा। इसके बारे में बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये लोग अपनी ओर भी देखें।... (व्यवधान) वर्ष 2002 से वर्ष 2012 तक कांग्रेस की सरकार रही, 1200 हत्याएं हुई थीं। वर्ष 1997 में कांग्रेस सरकार के समय 352 लोगों की मौत हुई। वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 750 लोगों की मौत हुई थी। ... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल से हमारी बहन घोष मैडम बोल रही थीं, मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर में लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज्यादा मौतें पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में टीएमसी सरकार और उसके कार्यकर्ताओं ने ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) का रूप लेकर ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) बहनों के साथ बलात्कार हुआ। ... (व्यवधान) ऐसी भी घटनाएं हुईं। ... (व्यवधान) जो बहू ब्याहकर लाई गई थी, एक दिन के बाद ही पति और पत्नी को अलग करके अपहरण कर लिया गया। ... (व्यवधान) यह बहुत अन्याय है।... (व्यवधान) बोलने से पहले ये लोग देखें। ... (व्यवधान)

मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि वहां शांति बहाल हो रही है इसलिए आप कृपया भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मणिपुर की हिंसा शुरू में निरंतर दो दिन तक आगे बढ़ती रही, उसमें बाहर के लोग भी लगे थे। उनके सोशल मीडिया को खंगालकर देखिए कि जो हिंसा भड़की थी, किस प्रकार से इन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया था। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं अंत में अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उदघोषणा को 13 अगस्त, 2025 से आगे छ: माह की अवधि के लिए जारी रखने का इस सदन द्वारा अनुमोदन किया जाए। संविधान के तहत निर्धारित उद्घोषणा की एक प्रति परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल पर रखी गई है।

(इति)

(1800/VVK/SRG)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1801 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 जुलाई 2025 / 9 श्रावण, 1947 (शक)</u>
<u>के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>